



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28, 1978/माघ 8, 1899

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28, 1978/MAGHA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

### PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities  
(other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1977

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1977

का०आ० 222.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 10-थाना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रोड्रिक्स स्टानी जोरान डेना बैंक भयान्दर के पास डाकखाना भयान्दर, ताल्लुका थाना, जिला थाना (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता का कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रोड्रिक्स स्टानी जोरान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कलावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० महा० लो०सं०/10/77(1)]

S.O. 222.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rodricks Stany Joran, Near Dena Bank Bhayander, Post Bhayander, Taluka Thana, District Thana (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the House of the People held in March, 1977 from 10-Thana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rodricks Stany Joran to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MR-HP/10/77(1)]

का०आ० 223.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7-बम्बई उत्तर पूर्व निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कमलाकर आरमाराम प्राधामले, तिलक नगर, चेम्बुर, जिल्हिंग सं० 70, रुम नं० 2510, बम्बई, 400089 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,

1951 तथा तद्वर्षीय बनाए गए नियमों द्वारा अर्पणित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में अग्रगण्य रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस अग्रगण्यता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अग्रगण्यता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्योचित्य नहीं है,

अतः अद्य, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री कमलाकर आत्माराम आधंगले को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कलावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० महा० मो०स०/7/77(2)]

आर० डी० शर्मा, अवर सचिव

### ORDER

**S.O. 223.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamalakar Atmaram Adhangale, Tilak Nagar, Chembur, Building No. 70, Room No. 2510, Bombay-40089, a contesting candidate for general election to the House of the People held in March, 1977 from 7-Bombay North-East constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kamalakar Atmaram Adhangale to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-HP/7/77(2)]

R. D. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1978

**का०आ० 224.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, श्री दिल-सुखराम, सरकार के सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को 31 अक्तूबर, 1977 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक श्री के० बी० लाल के स्थान पर, आन्ध्र प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्वारा नाम निर्दिष्ट करता है।

[सं० 154/आ०प्र०/77]

एस० पी० राजे, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd January, 1978

**S.O. 224.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby nominates Shri Dilsukhram, Secretary to Govt., General Administration Department as the Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh with effect from 31 October, 1977 (AN) and until further orders vice Shri K. B. Lal.

[No. 154/AP/77]

S. P. RAJE, Under Secy.

### निधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

**का०आ० 225.**—एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैगर्स सील हाट शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1296/76) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 2/18/77-एम०-2]

### MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th January, 1978

**S.O. 225.**—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. Nilhat Shipping Co. Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 1296476).

[F. No. 2/18/77-M. II]

**का०आ० 226.**—एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैगर्स जे० थामस एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1297/76) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 2/29/77-एम०-2]

**S.O. 226.**—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. J. Thomas & Co. Pvt. Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 1297476).

[No. 2/29/77-M. II]

**का० आ० 227.**—एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैगर्स साराभाई सन्स लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 526/70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 2/32/74-एम०-2]

**S.O. 227.**—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. Sarabhai Sons Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 526/70).

[F. No. 2/32/74-M. III]

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1978

**का० आ० 228.**—एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैगर्स ड्यूक्स एण्ड मैलि-योविल्स लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1056/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 2/52/75-एम०-2]

New Delhi, the 9th January, 1978

**S.O. 228.**—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. Tubes And Malleables Ltd. under the said Act (certificate of Registration No. 1056/75).  
[F. No. 2/52/75-M. II]

का० आ० 229.—एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैमस ब्यूब सप्लायर्स लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 1099/75) के निरस्तीकरण का अधिसूचित करती है।

[सं० 2/53/75-एम० 2]

चन्द्रकान्त खूशाल दास, उप सचिव

**S.O. 229.**—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the Cancellation of the Registration of M/s. Tube Suppliers Limited under the said Act (Certificate of Registration No. 1099/75)

[F. No. 2/53/75-M. II]

C. KHUSHALDAS, Dy. Secy.

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1978

का०आ० 230.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबन्ध तथा बैंकिंग विनियमन (सहकारी समितियाँ) नियम, 1966 के नियम 10 रत्नागिरि ग्रबेन कोऑपरेटिव बैंक लि० रत्नागिरि पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उनका सम्बन्ध समाचार पत्र में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाली वर्ष के तुलन पत्र लाभ हानि लेखा के प्रकाशन से है।

[संख्या एक० 8-5/77-ए०सी०]

लोकेन्द्र नाथ शर्मा, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 2nd January, 1978

**S.O. 230.**—In exercise of the powers conferred by the section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act and Rule 10 of the Banking Regulation (Cooperative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the Ratnagiri Urban Cooperative Bank Ltd., Ratnagiri in so far as they relate to the publication of its balance sheet, profit and loss account for the year ended the 30th June, 1976 together with the auditor's report in a newspaper.

[No. F. 8-5/77-AC]

L. N. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1978

का०आ० 231.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और

20 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबन्ध निदेशक श्री बी० एम नटराजन् को 6 जनवरी, 1978 से आरम्भ होने वाली तथा 5 जनवरी, 1981 को समाप्त होने वाली 3 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करती है।

[सं० एक० 8/7/77-बी० ओ०-1]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 6th January, 1978

**S.O. 231.**—In pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 19 and sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank, hereby appoints Shri V. S. Natarajan, Deputy Managing Director of the State Bank of India as the Managing Director of the State Bank of India for a term of three years commencing on 6th January, 1978 and ending with 5th January, 1981.

[No. F. 8/7/77-BO-I]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

का०आ० 232.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 20, रिपन स्ट्रीट और 38 वेस्टर्न स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित दो मंजिला पुरानी बिल्डिंगों के बारे में 18 नवम्बर, 1978 तक युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि०, कलकत्ता पर लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15 (37)-बी०ओ०-III/77]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 7th January, 1978

**S.O. 232.**—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply till the 18th November 1978 to the United Industrial Bank Ltd., Calcutta, in respect of the two storeyed old buildings situated at 20, Ripon Street and 38, Weston Street, Calcutta.

[No 15(37)?H.O./II/77]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

(बीमा पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1977

का०आ० 233.—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64 पठ की उपधारा (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1983 तारीख 30 मई, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाखण्ड अनुसूची में मद 10 में अंत में "या भारतीय पोत सर्वेक्षक रजिस्टर" शब्द जोड़े जाएंगे।

[का० सं० 51(7)/बीमा-1/77]

ए० रामानाथन, अवर सचिव

(Insurance Wing)

ORDER

New Delhi the 2nd December, 1977

**S.O. 233.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (10) of section 64 UM of the Insurance Act, 1938 (4 of

1938), the Central Government makes the following amendment to the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance No. S.O. 1983, dated the 30th May, 1970, namely :—

In the Schedule annexed to the said Order, in item 10, the words "or Indian Register of Shipping Surveyors" shall be added at the end.

[F. No. 51(7)/Ins-1/77]

S. RAMANATHAN, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1978

### बीमा

का०आ० 234.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिमोर्गियों की वेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 552 तारीख 16 फरवरी, 1974 को अधिकाृत करते हुए नीचे की सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी हैं, और जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समुह्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है। उक्त संपदा अधिकारी उक्त निगम की, या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई सम्पत्ति के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

### सारणी

क्रम सं०	अधिकारी का पदाभिधान	अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1. सचिव, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, नई दिल्ली।	हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	
2. सचिव, केन्द्रीय-क्षेत्र कार्यालय, कानपुर	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य।	
3. सचिव, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय कलकत्ता	असम, मेघालय, बिहार, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र।	
4. सचिव, पश्चिमी क्षेत्र मुम्बई।	गुजरात और महाराष्ट्र राज्य और दादरा और नगर हवेली और गोवा वसण और दीव संघ राज्य क्षेत्र।	
5. सचिव, दक्षिण-क्षेत्र कार्यालय, मद्रास।	आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे।	

[का० सं० 102/33/77-बीमा-IV]

आर० डी० खानवालकर, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 1978

### INSURANCE

S.O. 234.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants

Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 552, dated 16th February, 1974 and No. S.O. 1021, dated 24th February, 1976, the Central Government hereby appoints the Officers specified in column (2) of the Table below, being officers of the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), and being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act and the said estate officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction, specified in column (3) of the said Table, in respect of the properties belonging to, or taken on lease by or on behalf of the said Corporation.

TABLE

Sl. No.	Designation of Officer	Local limits of jurisdiction
1	2	3
1.	The Secretary at Northern Zonal Office, New Delhi.	States of Haryana, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Himachal Pradesh and Union territories of Chandigarh and Delhi.
2.	The Secretary at Central Zonal Office, Kanpur.	States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
3.	The Secretary at Eastern Zonal Office, Calcutta.	States of Assam, Meghalaya, Bihar, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur and Tripura and Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh and Mizoram.
4.	The Secretary at Western Zonal Office, Bombay.	States of Gujarat and Maharashtra and Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu.
5.	The Secretary at Southern Zonal Office, Madras.	States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and Union territories of Lakshadweep and Mahe of Union territories of Pondicherry.

[F. No. 102/33/77-Ins IV.]

R. D. KHANWALKAR, Under Secy.

### (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1977

### आय-कर

का० आ० 235.—संबंधाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य-क्रम की विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना कार्यक्रम : कुष्ठता का शीघ्र पता लगाना और उसकी रसायनिक चिकित्सा (इसके अंतर्गत औषधि प्रतिरोध भी है)

आयोजन कर्ता : फाउण्डेशन फार मेडिकल रिसर्च बाम्बे

आरम्भ होने की तारीख : 19 अगस्त, 1977

पूर्ण होने की अनुमानित तारीख : 18 अगस्त, 1982

अनुमानित लागत : 84 लाख (चौरासी लाख रुपये मात्र)

फाउण्डेशन आफ मेडिकल रिसर्च बाम्बे को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) (iii) के अधीन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 1200 (फा० सं० 203/3/76 आ०क०अ०II) तारीख 15-1-76 के अधीन अनुमोदित किया जा चुका है।

[सं० 2042/फा०सं० 203/129/77-आ०क०अ०-II]

जे० पी० शर्मा, उप-सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th November, 1977

### INCOME TAX

**S.O. 235.**—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 by the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

Name of the Scientific Research Programme : Early Detection of Leprosy and its Chemotherapy (including Drug Resistance.)

To be undertaken by : Foundation for Medical Research, Bombay.

Proposed date of Commencement : 19th August, 1977.

Anticipated date of Completion : 18th August, 1982.

Estimated Expenditure : 84 Lakhs (Rupees Eighty-four lakhs only).

The Foundation of Medical Research, Bombay has been approved under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Notification No. 1200 (F. No. 203/3/76-ITA.II), dated 15-1-76.

[No. 2042/F No. 203/129/77-ITA.II]

J.P. Sharma, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

### सीमा-शुल्क

का०आ० 236.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 48-सीमा-शुल्क तारीख 25 मार्च, 1972 को विरुद्धित करती है।

[सं० 17-सीमा-शुल्क/फा०सं० 574/7/77-एल०सी-II]

एन० कृष्णमूर्ति, अवसर सचिव

New Delhi, the 21st January, 1978

### CUSTOMS

**S.O. 236.**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 48-Customs, dated the 25th March, 1972.

[No. 17-Customs F. No. 574/7/77-LC-II]

N. KRISHNAMURTHY Under Secy.

### आयकर आयुक्त कार्यालय, पटियाला

पटियाला, 28 दिसम्बर, 1977

### (आयकर)

का० आ० 237.—धारा 287 के अधीन करदाताओं की सूची :—

भाग (क)

ऐसे करदाताओं की सूची, जिन पर वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान आय छिपाने के कारण 5000/रुपए (पाँच हजार रुपये) से अत्यून का अर्थदंड (पेनल्टी) लगाया गया था।

करदाता का नाम	हैसियत	निर्धारण वर्ष	अर्थदंड की रकम
मसजि शंकर आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल, प्रमलोह	रजिस्टर्ड फर्म	1972-73	8,500 रुपए
		1973-74	29,196 रुपए

भाग (ख)

ऐसे करदाताओं की सूची, जिन पर वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान आय विवरणी फाइल न करने के कारण अथवा लेखा बहिया प्रस्तुत न करने के कारण 5000 रुपए (पाँच हजार रुपये) से अत्यून का अर्थदंड (पेनल्टी) लगाया गया था।

क्रम सं०	करदाता का नाम	हैसियत	निर्धारण वर्ष	अर्थदंड की रकम
1.	मैसर्स प्योर फ्रिक्स (प्रा०) लि० (बम्बई), पटियाला	कम्पनी	1973-74	6,848 रुपए
2.	श्री हरजीत सिंह, मार्फत मै० पटियाला बस सर्विस (प्रा०) लि०, सरहिन्द	व्यक्ति (इन्डिविजुअल)	1969-70	6,900 रुपए
			1974-75	5,094 रुपए
3.	श्री केसर सिंह मार्फत यथोपरि	व्यक्ति	1972-73	5,000 रुपए
4.	श्री किरपाल सिंह मार्फत यथोपरि	व्यक्ति	1972-73	5,157 रुपए
5.	श्री बलवीर सिंह मार्फत यथोपरि	व्यक्ति	1972-73	17,640 रुपए

## भाग (ग)

ऐसे करदाताओं की सूची, जिन पर वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान करों की अदायगी न करने पर 5000 रुपये (पाँच हजार रुपये) से अन्यून का अर्थव्यय (पेनल्टी) लगाया गया था।

क्रम सं०	करदाता का नाम	हेसियत	निर्धारण वर्ष	अर्थव्यय की रकम
1.	मसज पंजाब बीवरेजिज (प्रा०) लि०, पटियाला	कम्पनी	1975-76	5,000 रुपये
2.	मसज प्योर ड्रिक्स (प्रा०) लि० (बम्बई), पटियाला	कम्पनी	1973-74	5,000 रुपये

[फा० सं० रैक (प्रकाशन/II)]

बी० पी० गुप्ता, आयकर आयुक्त

## Office of the Commissioner of Income tax, Patiala

Patiala, the 28th December, 1977

## INCOME-TAX

S.O. 237.—List of assessee u/s 287 :—

## PART (a)

Assessee on whom a penalty of not less than Rs. 5,000 (Rupees five thousands) was imposed for concealment of income during the financial year, 1976-77.

Name of the assessee	Status	Assessment Year	Amount of penalty
M/s. Shankar Iron & Steel Rolling Mills, Amloh.	Regd. firm	1972-73	Rs. 8,500
		1973-74	Rs. 29,196

## PART (b)

Assessee on whom a penalty of not less than Rs. 5,000 (Rupees five thousand) was imposed for failure to file return of income or to produce books of account during the financial year 1976-77.

Sl. No.	Name of the assessee	Status	Assessment Year	Amount of penalty
1.	M/s Pure Drinks (P) Ltd., (Bombay), Patiala.	Coy.	1973-74	Rs. 6,848/-
2.	Sh. Harjit Singh C/o M/s. Patiala Bus Service (P) Ltd., Sirhind.	Indl.	1959-70	Rs. 6,900/-
			1974-75	Rs. 5,094/-
3.	Sh. Kesar Singh C/o above	Indl.	1972-73	Rs. 5,000/-
4.	Sh. Kirpal Singh C/o above.	Indl.	1972-73	Rs. 5,457/-
5.	Sh. Balbir Singh C/o above	Indl.	1972-73	Rs. 17,640/-

## PART (c).

Assessee on whom a penalty of not less than Rs. 5,000 (Rupees five thousand) was imposed for non-payment of taxes during the financial year 1976-77.

Sr. No.	Name of the assessee	Status	Assessment Year.	Amount of penalty
1.	M/s. Punjab Beverages (P) Ltd., Patiala.	Coy.	1975-76	Rs. 5,000/-
2.	M/s. Pure Drinks (P) Ltd., (Bombay), Patiala.	Coy.	1973-74	Rs. 5,000/-

[F. No. Rec./Publication/II]

V. P. GUPTA, Commissioner

## केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1977.

## आय-कर

फा०जा० 238.—पर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मात्र प्रौद्योगिकीय परामर्श एवं प्रबंध परामर्श के क्षेत्र में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 घ की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है।

## संस्था

इस्टीमेशन आफ इकनामिक एण्ड मार्केट रिसर्च, नई दिल्ली

अनुमोदन 1 अप्रैल, 1977 से प्रभावी है।

[सं० 1996/फा०सं० 203/19/72-आई टी० ए-II]

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 24th September, 1977

## INCOME TAX

S.O. 238.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of Section 35D of the Income-tax Act, 1961, in the field of Technological Consultancy and management consultancy only.

## INSTITUTION

The Institute of Economic &amp; Market Research, New Delhi

The approval takes effect from 1st April, 1977.

[No. 1996/F. No. 203/19/72-ITA. II]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1977

## आय-कर

का०आ० 239.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए परामर्श सेवा के तीन क्षेत्रों अर्थात् प्रौद्योगिकी परामर्श, इंजीनियरी परामर्श और प्रबंध परामर्श के लिए अनुमोदित किया गया है।

## संस्था

जे०पी० मुकर्जी एण्ड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 से प्रभावी होगी।

[सं० 2032/का० सं० 203/58/77-आई टी ए-II]

New Delhi, the 29th October, 1977

## INCOME TAX

S.O. 239.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of section 35D of the Income-tax Act, 1961, in the three areas of consultancy service, viz., Technological consultancy, Engineering Consultancy and Management Consultancy.

## INSTITUTION

J. P. Mukherji & Associates Private Limited, Bombay.

The approval takes effect from 1st April, 1977.

[No. 2032/F. No. 203/58/77-ITA-II]

## आय-कर

का०आ० 240.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ की उपधारा (2) की खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, परामर्श के तीनों क्षेत्रों अर्थात् प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और प्रबंध के क्षेत्र में अनुमोदित किया है।

## संस्था

कोठारी कंसल्टेन्ट्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, मद्रास।

अनुमोदन 1 अप्रैल, 1976 से प्रभावी है।

[सं० 2031/का० सं० 203/28/77-आ०क०अ०-II]

## INCOME TAX

S.O. 240.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of Section 35D of the Income-tax Act, 1961, in all the three consultancy fields, viz., Technological, Engineering & Management.

## INSTITUTION

Kothari Consultants and Engineers Limited, Madras.

The approval takes effect from 1st April, 1976.

[No. 2031/F. No. 203/28/77-ITA-II]

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1977

## आयकर

का०आ० 241.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ की उपधारा (2) के खण्ड (क) के

प्रयोजनार्थ (क) प्रौद्योगिक परामर्श और (ख) इंजीनियरी परामर्श की बाबत अनुमोदित किया गया है।

## संस्था

पावर गैस इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई।

अनुमोदन 1-1-1977 से प्रभावी है।

[सं० 2043/का० सं० 203/9/77-आ०क० अ०-II]

जे० पी० शर्मा, सचिव

New Delhi, the 9th November, 1977

## INCOME TAX

S.O. 241.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of Section 35D of the Income-tax Act, 1961, in respect of (a) Technological Consultancy and (b) Engineering Consultancy.

## INSTITUTION

Power Gas India Limited, Bombay.

The approval takes effect from 1-1-1977.

[No. 2043/F. No. 203/9/77-ITA-II]

J. P. SHARMA, Secy.

## वारिण्य मंत्रालय

संपुक्त मुख्य वित्तक आयात निर्यात का कार्यालय, मद्रास

## आवेश

मद्रास, 4 नवम्बर, 1977

का०आ० 242.—आयात लाइसेंस सं० पी/जेड/0267/190/सी/एक्स एक्स/63/एम/76 दिनांक 24-5-1977, सर्वश्री बी० एस० मेटल्स, 71-ए, मिस्ट स्ट्रीट, मद्रास-600001 को जारी किया गया था।

सार्वजनिक सूचना सं० 30/77, दिनांक 28-5-77 के अनुसार आयात लाइसेंसधारियों के लिए यह आवश्यक था कि वे आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से तीन मास के अन्दर माल को आयात करने के लिए पक्की बचनबद्धता कर दे और ऐसा न करने पर लाइसेंस स्वतः अवैध समझा जाएगा। सर्वश्री बी० एस० मेटल्स, 71-ए, मिस्ट स्ट्रीट, मद्रास-1 को एक कारण बताओ सूचना दिनांक 25-8-1977 को जारी की गई थी कि क्या पार्टी ने निर्धारित अवधि के भीतर पक्की बचनबद्धता कर ली है और यदि नहीं की हो तो उक्त आयात लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए। पार्टी ने कारण बताओ सूचना का न कोई उत्तर दिया है और न ही यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उन्होंने पक्की बचनबद्धता की है।

2. पूर्वोक्त कड़िकाओं में जो कुछ भी वर्णन किया है, इसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि बिपयाधीन आयात लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए अथवा अन्यथा रूप से अप्रभावित कर दिया जाना चाहिए। अतः समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9, उप-धारा (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर अधोहस्ताक्षरी पार्टी के नामें जारी किए गए उक्त आयात लाइसेंस को एतद्वारा रद्द करता है।

[सं० आईटीसी/1203/748(ए)/3/4/ए एम०-77/ई० आई०]

## MINISTRY OF COMMERCE

Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports,  
Madras

## ORDER

Madras, the 4th November, 1977

**S.O. 242.**—The Import licence No. P/Z/0267190/C/XX/63/M/76 dated 24-5-1977 was issued to M/s. B. S. Metals, 71-A, Mint Street, Madras-600001.

In terms of Public Notice No. 30/77 dated 28-5-1977 the import licence holder were required to enter into firm commitments for import of the materials within three months from the date of issue of licence, failing which the licence will automatically stand invalidate. A show cause Notice dated 25-8-1977 was issued to M/s. B. S. Metals, 71-A, Mint Street, Madras-1 as to whether any firm commitment has been made within the stipulated period and if not, why the said import licence should not be cancelled. The firm have not replied to the show cause Notice nor produced any documentary evidence to show that they have entered into firm commitments.

Having regard to what has been stated in the preceding paragraphs, the undersigned is satisfied that the import licence, in question, should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in under sub-clause (CC) of Clause 9 of the Import (Control) Order, 1955 as amended from time to time hereby cancel the import licence mentioned above and issued in favour of the firm.

[No. ITC/1203/748(a)/iii/IV/AM. 77/EI]

## आदेश

**क्रा० आ० 243.**—आयात लाइसेंस सं० पी/जेड/0266816/सी/एक्स एम्स/63/एम/76, दिनांक 26-5-77, सर्वश्री सुमेरमल चम्पालाल, 27-बी० एम० एम० कोएल स्ट्रीट, बेलोर-4 को जारी किया गया था।

सार्वजनिक सूचना सं० 30/77, दिनांक 28-5-77 के अनुसार आयात लाइसेंसधारियों को आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से तीन मास के अन्दर मास आयात करने के लिए पक्की वचनबद्धता कर लेनी थी और ऐसा न करने पर लाइसेंस स्वतः प्रवैध समझा जाएगा। सर्वश्री सुमेरमल चम्पालाल, 27 बी० एम० एम० कोयल स्ट्रीट, बेलोर 4 को एक कारण बताओ सूचना दिनांक 25-8-77 यह पूछने हुए जारी की गई थी कि क्या पार्टी ने निर्धारित अवधि के भीतर पक्की वचनबद्धता कर ली है और यदि नहीं तो उक्त आयात लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए। पार्टी ने कारण बताओ सूचना का न तो कोई उत्तर दिया है और न ही यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उन्होंने पक्की वचनबद्धता कर ली है।

पूर्वोक्त कांडिकाओं में जो कुछ भी वर्णन किया है उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन आयात लाइसेंस रद्द अवस्था अन्यथा रूप से अप्रभावित कर दिया जाना चाहिए। अतः समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9, उप-धारा (सी सी) के अन्तर्गत प्रवर्त अधिकारों का प्रयोग कर अधोहस्ताक्षरी पार्टी के नाम में जारी किए गए उक्त आयात लाइसेंस को एतद् द्वारा रद्द करता है।

[सं० आईटीसी/621-622/21(2)/4/ए एम-77]  
के० एम० आर० मेनन, उप-मुख्य नियंत्रक

## ORDER

**S.O. 243.**—The import licence No. P/Z/0266816/C/XX/63/M/76, dated 26-5-1977 was issued to M/s. Sumermal Champalal, 27, B. S. S. Koll Street, Vellore-4.

In terms of Public Notice No. 30/77, dated 28-5-1977 the Import Licence holders were required to enter into firm commitments for import of the materials within three months from the date of issue of licence, failing which the licence

will automatically stand invalidate. As how cause Notice, dated 25-8-1977 was issued to M/s. Sumermal Champalal, 27, B.S.S. Koll Street, Vellore-4. as to whether any firm commitments has been made within the stipulated period and if not why the said import licence should not be cancelled. The firm have not replied to the show cause notice nor produced any documentary evidence to show that they have entered into firm commitments.

Having regard to what has been stated in the preceding paragraphs, the undersigned is satisfied that the import licence, in question, should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in under sub-clause (CC) of Clause 9 of the Import (Control) Order 1955, as amended from time to time hereby cancel the import licence mentioned above and issued in favour of the firm.

[No. ITC/621-622/21(ii)/IV/AM. 77]

K. M. R. MENON, Dy. Chief Controller

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1978

तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण

**क्रा० आ० 244.**—तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री टी० एल० शर्मा, तम्बाकू विकास अधिकारी, मुजफ्फरपुर तथा श्री बी० एम० सिन्हा, सहकारिता के अपर सचिव तथा गुजरात राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, अहमदाबाद की वर्तमान कालावधि 31 दिसम्बर, 1977 को पूरी होने से खाली होने वाले दो स्थानों पर तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में क्रमशः डा० आर० एम० नागपाल, कृषि (बागवानी) के संयुक्त निदेशक, पूना-1 तथा डा० अनिरुद्ध मिश्र, उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग के प्राध्यापक तथा विभाग अध्यक्ष, भुवनेश्वर को एतद् द्वारा नियुक्त करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक 12 तथा 13 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नोक्त क्रमांक तथा प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

- |  |   |
|--|---|
| 12. डा० आर० एम० नागपाल, कृषि (बागवानी) के संयुक्त निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, पूना-1   | सदस्य—महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 13. डा० अनिरुद्ध मिश्र, उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग के प्राध्यापक तथा विभाग अध्यक्ष, भुवनेश्वर। | सदस्य—उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।"    |

[क्रा० सं० 8/7/77-ई० पी०-(एपी-6)]

एन० के० गुप्ता, डैस्क अधिकारी

New Dehli, the 11th January, 1978

## TOBACCO INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL

**S.O. 244.**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (4) of section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby appoints Dr. R. L. Nagpal, Joint Director of Agriculture (Horticulture), Punc-1 and Dr. Anirudha Misra, Professor and Head of the Department of Agronomy, Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar respectively, as member of the Tobacco Board in the two vacancies cause by the completion on 31st December, 1977 of existing term of Shri T. L. Sharma, Tobacco Development Officer, Muzaffarpur and Shri V. S. Sinha, Additional Commissioner of Co-operation and Registrar of Co-operative Societies, Gujarat State, Ahmedabad, and



makes the following further amendment in the notification the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 5417, dated the 17th December, 1975, namely:—

In the said notification, under the heading "Appointed under clause (d) of sub-section (4) of section 4", for serial numbers 12 and 13 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"12. Dr. R.L. Nagpal, Joint Member—To represent the Director of Agriculture Government of Maharashtra. (Horticulture), Government of Maharashtra, Pune-1.

13. Dr. Anirudha Misra, Member—To represent the Professor and Head of Department of Agronomy Government of Orissa." Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar.

[File No. 8/77-EP (Agri.VI)]  
N. K. GUPTA, Desk Officer

मुख्य निर्यातक, आयात निर्यात का कार्यालय,

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978

क्रा० आ० 245.—सर्वश्री आई० डी० एल० एग्री कैमिकल्स लि०, नई दिल्ली, को आई० डी० ए० क्रेडिट के अन्तर्गत 22 सी० टन इंसुलन एक टेक का आयात करने के लिए 14,70,000 रुपए मूल्य का आयात लाइसेंस संख्या पी/डी/2198386, दिनांक 15 जून, 1974, प्रदान किया गया था।

लाइसेंसधारी ने यह बताया है कि उक्त लाइसेंस की मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति उनके बैंकर अर्थात् सिटी बैंक, नई दिल्ली, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा अस्थानस्थ हो गयी है और इसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए निवेदन किया है। शेष 25,000 रुपए को छोड़कर लाइसेंस का 19,45,000 रुपए के लिए उपयोग कर लिया गया था।

अपने निवेदन के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किये हैं। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस संख्या-पी/डी/2198386, दिनांक 15 जून, 1974 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निवेश वेता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सी एच/आई-116(1)ए एम-74आर एम-3/1056]

जी० एस० ग्रेवाल, उप-मुख्य निर्यातक  
हुते मुख्य निर्यातक

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi, the 12th January, 1978

S.O. 245.—M/s. IDL Agro Chemicals Ltd., New Delhi were granted Import Licence No. P/D/2198386, dated the 15th June, 1974 for Rs. 14,70,000 under IDA Credit for the import of 22mt. of Dursban F. Tech.

The licensee has reported that Exchange Control Copy of the said licence has been misplaced either by their bankers, namely City Bank, New Delhi or the Exchange Control Department of the Reserve Bank of India and has requested for issuing a duplicate copy thereof. The licence was utilised for Rs. 19,45,000 leaving a balance of Rs. 25,000.

177 GI/77-2.

In support of their request the applicant have filed an affidavit and other documentary evidence. The under-signed is satisfied that the Original Exchange Control Copy of the said licence be issued to the applicant. The Exchange Control Copy of the licence is being issued separately.

[No. CH/I-116(1)/AM. 74-R.M. III/1056]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller  
for Chief Controller

आदेश

क्रा० आ० 246.—सर्वश्री डाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, दि आन्ध्र वैली पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड और दि डाटा पावर कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को आयात लाइसेंस सं० पी/एच/2070982, दिनांक 17-12-76 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। आगे यह भी बताया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति बम्बई सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत थी और उसका आंशिक उपयोग कर लिया गया था। कुल मूल्य जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया था वह 32,670 रुपए (बत्तीस हजार छः सौ सतर रुपए मात्र) था और वह कुल मूल्य जिसके लिए मूल प्रति उपयोग कर ली गई थी 9,733.00 रुपए था। अब अनुलिपि प्रति बाकी बचे हुए 22,937.00/-रुपए (बाइस हजार नौ सौ सैंतीस पए मात्र) को पूरा करने के लिए चाहिए।

2. इस तर्क के समर्थन में, आवेदक ने नोटरी पब्लिक बम्बई, महाराष्ट्र राज्य के सामने विधिवत् शपथ ले कर दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए यथा संगोषित आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रवक्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री दि डाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, दि आन्ध्र वैली पावर सप्लाय कम्पनी लि० और दि डाटा पावर कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को जारी किए गए उपर्युक्त मूल लाइसेंस सं० पी/एच/2070982, दिनांक 17-12-76 को एतद्वारा रद्द किया जाता है और आगे यह निवेश वेता हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जाए।

[संख्या सी० जी०-4/एच० ई० पी (टी-40)/76-77]

टी० डी० ला, उप-मुख्य निर्यातक

ORDER

S.O. 246.—M/s. The Hydro-Electric Power Supply Company Limited, The Andhra Valley Power Supply Company Limited and The Tata Power Company Limited, Bombay were granted an import licence No. P/H/2070982, dated 17-12-1976. They have applied for a duplicate Customs Purposes Copy of the said licence on the grounds that the original Customs Purposes Copy has been misplaced/lost. It is further stated that the original Customs Purposes Copy was registered with Bombay Custom House and utilised partly. The total amount for which the licence was issued is Rs. 32,670 (Rupees thirtytwo thousand six hundred and seventy only) and the total amount for which the original copy was utilised is Rs. 9,733. The duplicate copy now required is to cover the balance of Rs. 22,937 (Rupee twenty two thousand nine hundred and thirtyseven only).

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before the Notary Public Bombay, Maharashtra State. I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955, dated 7-12-1975 as amended, the said Original Customs Purposes Copy of licence No. P/H/2070982 dated 17-12-1976 issued to M/s. The Tata Hydre Electric Power Supply Co. Limited and The Andhra Valley Power Supply Company Limited and The Tata Power Company Ltd., Bombay is hereby cancelled and further direct that a duplicate Customs Purposes Copy of the said licence may be issued.

[No. CG. IV/HEP(T-40)/76-77]

T. T. LA, Dy. Chief Controller

**ऊर्जा मंत्रालय****(विद्युत विभाग)**

नई दिल्ली 12 जनवरी, 1978

क्र० आ० 247.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, व्यापक परियोजना के संघटक, अर्थात् व्यास पारेषण परियोजना-यूनिट-I के अन्तर्गत एकमात्र कार्य के रूप में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित 220 के०वी०डी०सी० बेहर गंगुवाल लाइन, जिसके संबंध में सन्निर्माण पूरा हो गया है, उक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 79 के अधीन गठित भाकड़ा प्रबंध बोर्ड को सुरक्षित अस्तित्व करती है।

[सं० 21/14/76-बी० एण्ड सी०-एण्ड-II]

पी० एम० बेल्लिप्पा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENERGY**

(Department of Power)

New Delhi, the 12th January, 1978

S.O. 247.—In pursuance of sub-section (5) of section 80 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby transfers, with immediate effect, the component of the Beas Project, namely, 220 KV D.C. Dehar Ganguwal line executed by the Punjab State Electricity Board as exclusive work under Beas Transmission Project-Unit-I in relation to which the construction has been completed, to the Bhakra Beas Management Board constituted under section 79, read with sub-section (6) of section 80, of the said Act.

[No. 21/14/76-B&amp;B-Vol. II]

P. M. BELLIAPPA, Jt. Secy.

**नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय**

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1978

क्र० आ० 248.—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन पेपर एण्ड जीजर सर्वेन्ट्स एसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसिएशन को यथा महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त मुम्बई साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का मुम्बई अधिनियम-I) में यथा परिभाषित बृहत्तर मुम्बई की सीमाओं के भीतर काशी मिर्च की अधिम संविदाओं के बारे में 19 जनवरी, 1978 से 18 जनवरी, 1979 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रवृत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[मिसिल सं० 12(23)-आई०टी०/77]

**MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION**

New Delhi, the 3rd January, 1978

S.O. 248.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Pepper and Ginger Merchants' Association Ltd., Bombay, and being satisfied that it would be in the interest

of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 19th January, 1978 to the 18th January, 1979 (both days inclusive) in respect of forward contracts in pepper within the limits of Greater Bombay as defined in the Bombay General Clauses Act, 1904 (Bombay Act I of 1904), as in force in the State of Maharashtra.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(23)-IT/77]

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1978

क्र०आ० 249.—केन्द्रीय सरकार, अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन इंडियन एक्सचेंज लि०, अमृतसर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए दिये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को विनोले की अधिम संविदाओं के बारे में 11 नवम्बर, 1977 से 10 नवम्बर, 1978 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रवृत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[मिसिल संख्या 12(20)-आई०टी०/77]

बी० श्रीनिवासन, उप सचिव

New Delhi, the 6th January, 1978

S.O. 249.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Indian Exchange Ltd., Amritsar and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said exchange for a further period of one year from the 11th November, 1977, to the 10th November, 1978, (both days inclusive), in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(20)-IT/77]

V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

**पेट्रोलियम मंत्रालय**

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1978

क्र०आ० 250.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रवर्तित किया गया है और पेट्रोलियम पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में जेधन तेल सं० ऐनोड जेड और बायर जेड के लिए पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग में उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) की धारा (1) में निविष्ट कार्य दिनांक 27-11-76 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम 1963 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

#### अनुसूची

एनोड बेड और वायर से बेड के लिए तल पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गाँव	का.प्र.सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम	कड़ी	2176	26-6-76	27-11-76

[सं० 12020/4/77-प्रोडक्शन]

जी० के० बुदानी, गुजरात के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

#### MINISTRY OF PETROLEUM New Delhi, the 4th January, 1978

S.O. 250.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum for Anode Bed & Wire Bed in Kadi oil-field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 27-11-76.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

#### SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline for Anode Bed & Wire Bed.

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum	Kadi	2176	26-6-76	27-11-76

[No. 12020/4/77-Prod.]

G.K. DUDANI,

Competent Authority under the Act for Gujarat

#### कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

का० प्र० 251.—सूजी और मैदा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1977 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रत्यापना करती है, उक्त धारा की अपेक्षा-नुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है तथा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर या उस के बाद विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

#### नियमों का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का नाम सूजी और मैदा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1977 है।

(2) ये भारत में उत्पादित सूजी और मैदा को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में:—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिन्हें साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 के नियम 3 के अधीन, सूजी और मैदा के सम्बन्ध में प्राधिकार-पत्र जारी किया गया हो।

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान:—सूजी और मैदा की क्वालिटी को उपदर्शित करने वाला श्रेणी अभिधान, अनुसूची 3 और 4 के स्तम्भ 1 में यथावस्थित होगा।

4. क्वालिटी की परिभाषा:—श्रेणी अभिधान द्वारा यथावस्थित क्वालिटी, अनुसूची 3 के स्तम्भ 2 से 8 तक और अनुसूची 4 के स्तम्भ 2 से 7 तक में उक्त अभिधानों के सामने यथावस्थित होंगे।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न:—श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा दिए गए एक ऐसे लेबल (जिसमें 'एमआर' शब्द सहित भारत का मानचित्र और "भारतीय उत्पाद" शब्द सहित उगते हुए सूर्य का चिह्न होगा) का होगा, जो अनुसूची 1 में बताए गए चिह्न के अनुसार होगा।

टिप्पण: (1) प्रत्येक लेबल पर क्रम संख्या, और सीरीज सूचित करने वाले अक्षर या अक्षरों को मुद्रित किया गया होगा, उपाहरणार्थ ए-004378।

(2) कागज या कपड़े पर प्रयुक्त होने वाले श्रेणी अभिधान चिह्न, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट करने वाले चिह्न के होते होंगे।

(3) "बी-तवील-जूट के पैलों" पर प्रयोग किया जाने वाला श्रेणी अभिधान चिह्न एक ऐसे बॉक्स जाने वाला आयातक लेबल का होगा जो श्रेणी अभिधान उपदर्शित करता हो।

6. चिह्नान्कन की पद्धति :—(1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से प्रत्येक आधान पर स्पष्ट रूप से चिपकाया जाएगा,

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) पैकिंग की तारीख
- (ख) लॉट संख्या
- (ग) पैकर का नाम और पता
- (घ) शुद्ध भार,

(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके, आधान पर अपना निजी व्यापार चिह्न, उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से अंकित कर सकेगा :

परन्तु यह तब जब कि निजी व्यापार चिह्न, इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपरिष्ठित भुजी और सैदा की बहालियो या श्रेणी से, भिन्न न हो ।

7. पैकिंग की पद्धति :—(1) केवल बी-ट्रील जूट या कागज या कपड़े के बने मजबूत, स्वच्छ और सूखे आधान ही पैकिंग के लिए प्रयुक्त होंगे, तथा आधान, कीटाणु-संक्रमण या कफूंदी संदूषण से मुक्त होंगे और किसी भी अवांछनीय गंध से भी मुक्त होंगे ।

(2) आधान, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से, मजबूती के साथ बन्द और मोहरबन्द किए जाएंगे ।

(3) प्रत्येक पैकेजों में केवल एक ही श्रेणी अभिधान की सूची और सैदा होंगे ।

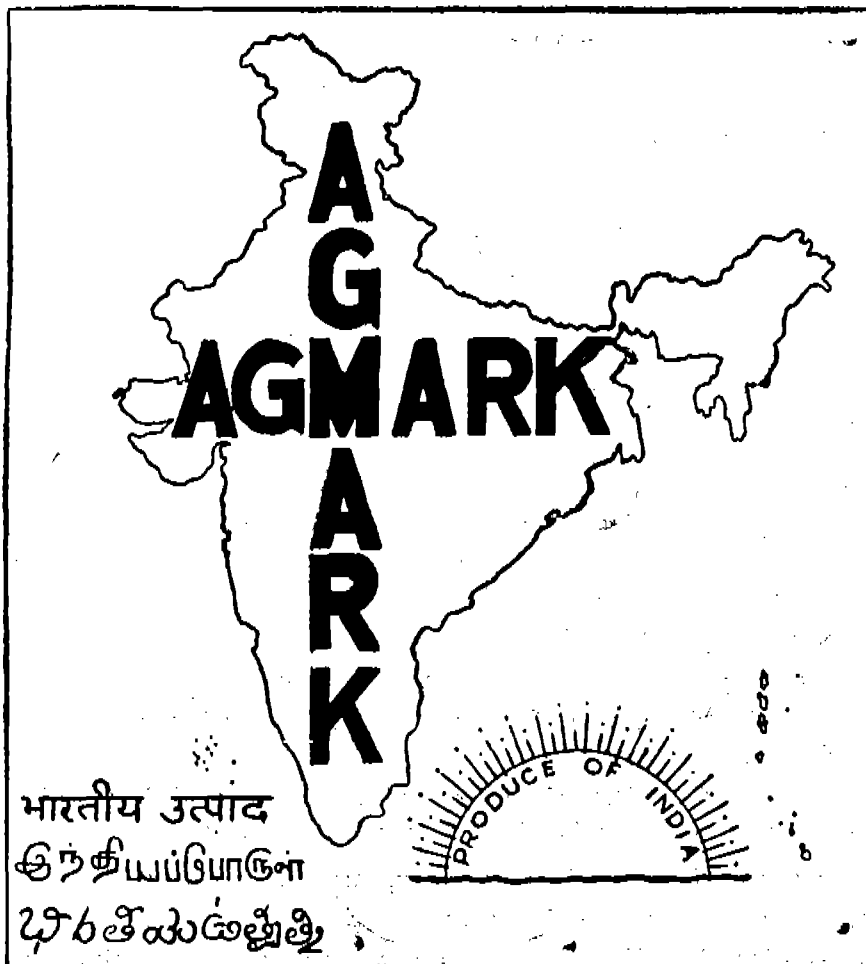
8. प्राधिकार-पत्र की विशेष शर्तें :—साधारण श्रेणीकरण और चिह्नान्कन नियम 1937 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, अनुसूची 2 में बताई गई शर्तें भी इन नियमों के प्रयोजनार्थ जारी किए गए प्रत्येक प्राधिकार पत्र की शर्तें होंगी ।

अनुसूची 1

(नियम 5 देखिए)

भुजी और सैदा के लिए श्रेणी अभिधान चिह्न.

(भारत का मानचित्र)



अनुसूची 2  
(नियम 8 देखिए)

प्राधिकार पत्र की विशेष शर्तें

- (क) प्राधिकृत पैकर भण्डारकरण, प्रसंस्करण और चिह्नीकरण के दौरान गेहूं के साथ अन्य दानों के मिश्रण को बचाने के लिए सभी सावधानियां करेगा।
- (ख) प्राधिकृत पैकर सूजी और मैदा के परीक्षण के लिए ऐसे प्रबन्ध करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं। यह विश्लेषण के समुचित अभिलेख भी रखेगा।
- (ग) नमूने लेने और विश्लेषण, आधान को मोहरबन्ध करने और चिह्नीकरण करने की रीति, अभिलेखों को रखने और विवरणियां प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाएगा।
- (घ) सूजी और मैदा के प्रत्येक लॉट से कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अधिकृत रीति से लिया गया सूजी और मैदा का एक नमूना उस नियन्त्रण प्रयोगशाला को भेजा जाएगा जिसके लिए समय-समय पर निर्देश दिया जाए।
- (ङ) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस निमित्त सम्पन्न प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी को यथावश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

अनुसूची 3

सूजी (रबा) की क्वालिटी का श्रेणी-अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विवरण	कणों का आकार (सिल्क या नाइ- लोन के बोर्ड कपड़े की आई० एस० 710 माइ- क्रोन छलनी पर ठहर जाने वाला प्रतिशत	भार का आधार नमी का प्रतिशत जो निम्न- लिखित से अधिक नहीं होगा	(शुष्क भार के आधार पर) कुल राख का प्रतिशत जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा	(शुष्क भार के आधार पर) अविलेय अम्लता प्रतिशत जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा	90 प्रतिशत एथनाल में भार के आ- धार पर अलकोहलीय अम्लता (जैसे H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> जो शुष्क भार के आधार पर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा	(शुष्क भार के आधार पर) भार के आधार पर ग्लूटेन प्रतिशत, जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा
1	2	3	4	5	6	7	8
एस० पी (बड़े कण)	यह पदार्थ अच्छे और स्वच्छ गेहूं को पीस कर प्राप्त किया जाएगा। इसमें लाक्षणिक स्वाद और गंध होगी तथा रंग कीम-पीत होगा। यह फफूंदी-संक्रमण और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगा।	न्यूनतम 90	13.5	1.0	0.05	0.10	6.0
एस० पी० (छोटे कण)	यह पदार्थ अच्छे और स्वच्छ गेहूं को पीस कर प्राप्त किया जाएगा। इसमें लाक्षणिक स्वाद और गंध होगी तथा रंग कीम पीत होगा। यह फफूंदी गंध, कीटाणु या फफूंदी-संक्रमण और बाह्य-पदार्थ से मुक्त होगा।	अधिकतम 10	12.5	1.0	0.05	0.10	6.0

टिप्पण: (1) कोई भी पदार्थ सिल्क या नाइलोन की 1.18 मि०मी०आई०एस० छलनी में नहीं ठहरेगा।

(2) नाइलोन बोर्डिंग कपड़े की 250 माइक्रोन आई० एस० छलनी पर न्यूनतम 9 प्रतिशत पदार्थ ठहरेगा।

(3) "एस पी श्रेणी" बड़े कण के लिए है तथा एस पी श्रेणी छोटे कण के लिए है।

## अनुसूची 4

सूजे की क्वालिटी का श्रेणी-प्रमाण और परिभाषा  
(नियम 3 और 4 देखिए)

श्रेणी प्रमाण	विशेष लक्षण					साधारण लक्षण
	भार के आधार पर नमी प्रतिशत जो निम्न- लिखित से अधिक नहीं होगा।	(शुष्क भार के आधार पर) भार के आधार पर कुल राख प्रतिशत जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा।	(शुष्क भार के आधार पर) भार के आधार पर अम्ल अम्ल लेय राख प्रतिशत जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा।	90 प्रतिशत भार में भार के आधार पर अम्लोहलीय अम्लता जैसे H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> प्रतिशत जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा।	भार के आधार पर (प्रति- शत) जो निम्न- लिखित से कम नहीं होगा।	
1	2	3	4	5	6	7
हार्ड ग्लूटेन	13.0	1.0	0.05	0.1	10.0	1. यह पदार्थ स्वच्छ, सख्त या नम गेहूं या उसके मिश्रण को पीसने से प्राप्त किया जाएगा।
मीडियम ग्लूटेन	13.0	0.70	0.05	0.1	8.0	
सॉफ्ट ग्लूटेन	13.0	0.70	0.05	0.1	7.0	2. पदार्थ में लक्षणिक स्वाद या गन्ध होगी तथा कीटाणु और फफूंदी संरक्षण, कृतक सत्वण, भूल और अन्य बाह्य पदार्थों से मुक्त होगा।

[सं० 13-8/77-ए० एम०]

## MINISTRY OF AGRICULTURE &amp; IRRIGATION

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 30th September, 1977

S.O. 251.—The following draft of the Suji and Maida Grading and Marking Rules, 1977, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published, as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of fortyfive days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

## DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called Suji and Maida Grading and Marking Rules, 1977.

(2) They shall apply to Suji and Maida produced in India.

2. Definitions.—In these rules,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation under rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1937, in relation to Suji or Maida;

(c) "Schedule" means a schedule appended to these rules.

3. Grade Designations.—The grade designations to indicate the quality of Suji and Maida shall be as set out in column 1 of Schedules III and IV.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designations shall be as set out against the said designations in columns 2 to 8 of Schedules III and 2 to 7 of Schedule IV.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of a label supplied by the Agricultural Marketing Adviser specifying the grade designation and bearing a design (consisting of an outline map of India with the word AGMARK and the figure of the rising sun with the words "Produce of India") resembling the mark set out in Schedule I.

Note : (1) Each label shall have printed thereon a serial number along with a letter or letters denoting the series e.g. A. 004373.

(2) The grade designation mark to be used on paper or cloth shall consist of a paste-on label specifying the designation.

(3) The grade designation mark to be used on B-twill Jute bags shall consist of a rectangular tie-on label specifying the grade designation.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be clearly affixed to every container in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation mark, every container shall be clearly marked with the following particulars, namely :—

(a) date of packing;

(b) lot number;

(c) name and address of packer;

(d) net weight.

(3) An authorised packer may, after obtaining the previous approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer:

Provided that the private trade mark does not represent quality or grade of the Suji and Maida different from that indicated by the grade designation mark affixed on the container in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(1) Only sound, clean and dry container made of paper, cloth or B-twist jute shall be used for packing and the container shall be free from any insect infection or fungus contamination as also from any undesirable smell.

(2) The container shall be securely closed and sealed in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) Each package shall contain Suji or Maida of the same grade designation only.

8. Special conditions of Certificate of Authorisation.—In addition to the conditions specified in rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the conditions set out in Schedule II shall be the conditions of every certificate of Authorisation issued for the purpose of these rules.

#### SCHEDULE I

(See rule 5)

Grade designation mark for Suji and Maida  
(MAP OF INDIA)



#### SCHEDULE II

(See rule 8)

Special conditions of Certificate of authorisation :

- An authorised packer shall take all precautions to avoid admixture of other grains with the wheat during storage, processing and marking.
- An authorised packer shall make such arrangement for testing Suji and Maida as may be laid down from time to time by the Agricultural Marketing Adviser. He shall also maintain proper records of the analysis of samples.
- All instructions regarding the methods of the sampling and analysis, sealing and marking of containers, the maintenance of records and submission of returns which may be issued from time to time by the Agricultural Marketing Adviser, shall be strictly observed.
- A sample of Suji and Maida drawn in a manner laid down by the Agricultural Marketing Adviser from each lot of Suji and Maida produced shall be forwarded to such control laboratory as may be directed from time to time.
- An authorised packer shall provide all such facilities as may be necessary to the Inspecting Officers duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser in this behalf.

#### SCHEDULE III

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of Suji (Rawa)

Grade designation	Description	Particle size (% retained on I.S. 710 Micron sieve of silk or nylon bolting cloth)	Moisture (% by weight not exceeding)	Total ash % (on dry weight basis) not exceeding	Acid insoluble ash % (on dry weight basis) not exceeding	Alcoholic acidity (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) in 90% ethanol % by weight basis not exceeding (on dry weight basis)	Gluten % (as by weight on dry weight basis) not less than
1	2	3	4	5	6	7	8
L.P. (Large Particles)	The material shall be obtained by grinding sound and clean wheat. It shall have a characteristic taste and smell and creamy yellow colour. It shall be free from musty odour, insect or fungus infection and extraneous matter.	Minimum 90	13.5	1.0	0.05	0.10	6.0
S.P. (Small Particles)	The material shall be obtained by grinding sound and clean wheat. It shall have a characteristic taste and smell creamy yellow colour. It shall be free from musty odour, insect or fungus infection and extraneous matter.	Maximum 10	13.5	1.0	0.05	0.10	6.0

- Notes : (1) No material shall be retained on 1.18 mm, I.S. sieve of silk or nylon.  
 (2) Minimum 9% material shall be retained on 250 micron I.S. sieve Nylon bolting cloth.  
 (3) Grade L.P. stands for "Large Particles" and grade S.P. stands for "Small Particles."

## SCHEDULE IV

(See rules 3 and 4)

## Grade designation and definition of quality of Maida

Grade designation	Moisture % by weight not exceeding	Special Characteristics				General Characteristics
		Total ash (on dry basis) per cent by weight not exceeding	Acid insoluble ash (on dry basis) per cent by weight not exceeding	Alcoholic acidity (ash $H_2SO_4$ in 90 % alcohol % by weight not exceeding	Gluten per cent by weight not less than	
1	2	3	4	5	6	7
High Gluten	13.0	1.0	0.05	0.1	10.0	(1) The material shall be obtained by milling cleaned hard or soft wheat or blends thereof.
Medium Gluten	13.0	0.70	0.05	0.1	8.0	(2) The material shall have a characteristic taste or smell and shall be free from insect and fungus infection, rodent contamination dirt, and other extraneous matter.
Low Gluten	13.0	0.70	0.05	0.1	7.0	

[No. F. 13-6/77-AM]

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1978

कां०अ० 252 —कृषि विपणन नियमों का निम्नलिखित प्राकृत्य जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नीकरण) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खली श्रेणीकरण और चिह्नीकरण नियम, 1962 को अधिष्ठात करते हुए बनाने की प्रस्तावना करती है उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्राकृत्य पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

जो आपत्ति या सुझाव उक्त प्राकृत्य की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## नियमों का प्राकृत्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—इन नियमों का नाम बनस्पति खली (पेरी गई या विलायक निस्सारित) श्रेणीकरण और चिह्नीकरण नियम, 1978 है।

2. परिभाषा.—इन नियमों में,—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है।

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान.—खली (पेरी गई या विलायक निस्सारित) की क्वालिटी उपर्युक्त करने वाले श्रेणी अभिधान वे होंगे जो अनुसूची II क से IX ख के स्तम्भ (1) में उपर्युक्त हैं।

4. क्वालिटी की परिभाषा.—श्रेणी अभिधानों द्वारा उपर्युक्त की गई क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची II क से IX ख तक में के प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपर्युक्त है।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह.—श्रेणी अभिधान चिन्ह एक लेबल होगा जिस पर अनुसूची 1 में उपर्युक्त नमूना होगा और उसमें श्रेणी अभिधान, खली का नाम तथा यह पेरी गई है या विलायक निस्सारित है या नहीं, में विनिर्दिष्ट होंगे।

6. चिह्नीकरण की पद्धति:—(1) श्रेणी अभिधान चिन्ह प्रत्येक आधान पात्र पर सुरक्षित रूप से उस रीति में चिपकाया जाएगा या उस पर स्टैम्प किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार अनुमोदित करें और उसमें कृषि विपणन सलाहकार द्वारा पैकर को जारी किए गए प्राधिकरण प्रमाणपत्र का संख्यांक भी दर्शाया जाएगा।

(2) इसके अतिरिक्त प्रत्येक आधान पात्र पर निम्नलिखित विशिष्टियों स्पष्ट और अमिट रूप से चिह्नित की जाएगी:—

(क) साट संख्यांक

(ख) पैकर का नाम

(ग) पैकिंग की तारीख

(घ) पैकिंग का स्थान।



(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् आधान-प्रधान पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न उस रीति में चिह्नित करेगा जो उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, परन्तु प्राइवेट व्यापार चिह्न से खली की उस क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी व्यक्त नहीं होनी चाहिए जो इन नियमों के अनुसार आधान-पत्र पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित की गई है।

7. पैकिंग की पद्धति :—(1) खली केवल जूट या अन्य पदार्थ से निर्मित ऐसे आधानों में पैक की जाएगी जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो :

(2) प्रत्येक आधान मजबूती से बन्ध किया जाएगा और सील किया जाएगा और उसमें केवल एक व्यापार वर्णन तथा एक श्रेणी अभिधान की खली ही होगी।

8. प्राधिकरण-प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें :—साधारण श्रेणीकरण और चिह्नानुक्रम नियम 1937 के नियम 4 के बनिदिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें इन नियमों के प्रयोजन के लिए जारी किए गए हरेक प्राधिकरण-प्रमाणपत्र की शर्तें भी होंगी, अर्थात् :—

(1) प्रत्येक प्राधिकृत पैकर एरण्डी के बीच और एरण्डी की खली की मिलावट की रोकथाम के लिए सभी पूर्वाधानियां बरसेगा।

(2) यदि प्राधिकृत पैकर उन्हीं परिसरों में एक से अधिक प्रकार की खली का कार्य करता है तो वह विभिन्न खलियों की मिलावट की रोकथाम के लिए पर्याप्त पूर्वाधानियां बरसेगा। परिसर साफ एवं स्वास्थ्य कर होने चाहिए और उन्हें कालिक रूप से धुंकारित किया जाना चाहिए।

(3) प्राधिकृत पैकर खलियों के परीक्षण के लिए व्यवस्थाएं करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित की जाएं और नमूनों के विश्लेषण का उचित अभिलेख भी रखेगा।

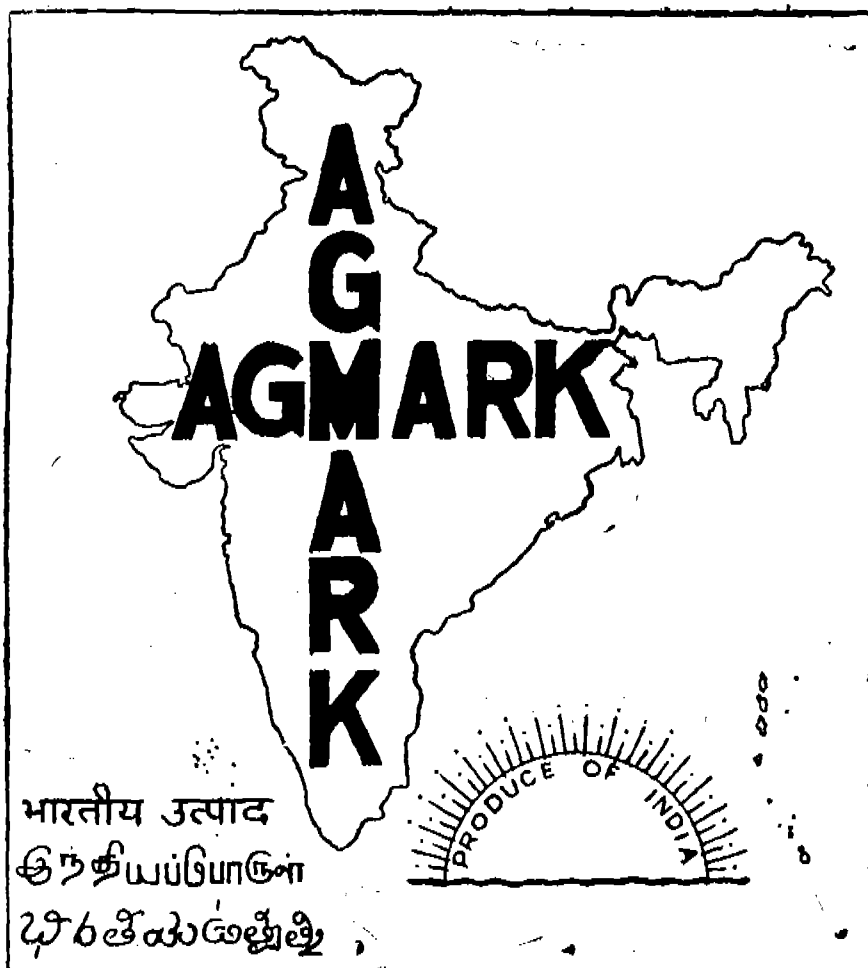
(4) नमूना बनाने और विश्लेषण करने, पैकिंग और चिह्नानुक्रम और अभिलेख रखने की पद्धतियों के बारे में सभी अनुदेशों का, जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाय, अनुपालन किया जाएगा।

(5) उस रीति में जैसी कि कृषि विपणन सलाहकार विहित करे, प्रत्येक लोट से खली का नमूना ऐसी नियंत्रक-प्रयोगशाला को अर्पित किया जाएगा जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए।

#### अनुसूची I

(नियम 5 देखिए)

(लेबलों के लिए श्रेणी अभिधान किया जाएगा)



अनुसूची II क  
(नियम 3 और 4 देखिए)

मूंगफली की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (माइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या अन्य सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अमूल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अण्डी	8.0	50.0	8.0	9.0	7.0	1.5	कुछ नहीं	(1) अण्डी और स्वच्छ श्रेणी केवल छिलके रहित मूंगफली की पैदावार होगी जो बिजली चालित मशीनरी द्वारा पेरने के बाद प्राप्त की जाती है।
स्वच्छ	8.0	50.0	5.0	9.0	7.0	2.0	कुछ नहीं	(2) धानी खली केवल छिलके रहित मूंगफली की पैदावार होगी जो पशुचालित धानी या चक्की के द्वारा तेल पेरने के बाद प्राप्त की जाती है।
धानी खली	10.0	45.0	10.0	9.0	7.0	2.5	कुछ नहीं	(3) पदार्थ दुड़ बनावट का होगा। (4) यह हानिकारक एककों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगी। (5) यह खटास, कीट या फफूँव-बाधा और किण्वित, सख्त या अन्य आपत्तिजनक गन्ध से मुक्त होगी। (6) यह धूल और बाह्य पदार्थ से युक्त होगी।

टिप्पण :-—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-चारे के रूप में छिलके रहित मूंगफली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया।

(आई० एस० 1713-1960)

अनुसूची II ख  
(नियम 3 और 4 देखिए)

मूंगफली की खली (बिलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (माइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या अन्य सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत अमूल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8
अण्डी	10.0	51.0	1.0	10.0	2.5	कुछ नहीं	(1) बिलायक निस्सारित मूंगफली की खली (मील) एक्सपेलन या धानी से पेरी गई मूंगफली की खली बिलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। मील

1	2	3	4	5	6	7	8
स्वच्छ	10.0	47.0	1.5	12.0	2.5	कुछ नहीं	कुछ प्रारम्भिक शोधन के बाद सीधे मृगफली के बीजों से भी प्राप्त की जा सकती है। निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली एक्सपेलर या धानी से पेरी गई मृगफली की खली साफ व ठोस मृगफली (प्रारकिस् हैपीजिया-एल) के पेरने से प्राप्त की गई होगी। प्रोटीन को विकृतिकरण से बचाने और विलायक के रेशे हटाने के लिए मीस निद्रित और विनियमित परिस्थितियों में अधीन ऊष्मा और वाष्प शोधन के अधीन रखी जाएगी। पदार्थ पपड़ी या नून के रूप में होगा और हानिकारक अवशेषों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों मलबा की खली से मुक्त होगा और खटबास, अपमिश्रण, कीट या फफूँव बाधा और सूक्ष्म दुर्गन्ध से मुक्त होगी।

टिप्पण :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित हैं।

पशुधन-कारे के रूप में विलायक निस्सारित मृगफली की खली (मील) के लिए भारतीय मानक विनिर्दिष्ट से लिया गया।

(आई०एस० 3441-1966)

(2) निस्सारण के लिए विलायक :—निस्सारण के प्रयोजनों के लिए केवल घन्ठी श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा।

विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

वजन दूरी 63° से 71° से 0 तक

एथोमेटिक तत्व (अधिकतम) 1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम) 0001 ग्राम/100 मि०लि०

अनुसूची III क

(नियम 3 और 4 देखिए)।

छिलके रहित बिनोले की खली—(पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन) 6.25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या अन्य सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय प्रसल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
घन्ठी	8.0	40.0	8.0	10.0	7.0	1.6	कुछ नहीं	(1) केवल साफ बिनोले की उपज होगी मूल रूप से गिरी के साथ छिलके और रेशे के उन अपरि-हार्थ प्रभागों से बनी हो जो सेल विनिर्माण के समय छूट गए हों।
स्वच्छ	8.0	41.0	5.0	12.0	8.0	2.0	कुछ नहीं	(2) पदार्थ ठोस होगा लेकिन 35 बनावट का न हो।
नं० 2	8.0	37.0	5.0	14.0	9.0	2.5	कुछ नहीं	(3) यह हानिकारक अवशेषों और एरण्डी की खली व भूसी से मुक्त होगी। (4) यह खटबास, अपमिश्रण, कीटों या फफूँव बाधा और किण्वित, सूजन या अन्य आपसिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण : स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित हैं।

पशुधन-कारे के रूप में बिनोले की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया। (आई०एस० 1712-1960)

## अनुसूची III ब

(नियम 3 और 4 देखिए)

छिलके सहित बिनौले की खली (पेरो हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (माइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत बसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेसो का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय भ्रूसी का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	10.0	24.0	7.0	24.0	9.0	2.5	कुछ नहीं	(1) केवल साबुत, साफ और जहाँ कहीं आवश्यक है (विशेष कर रोंयेदार बीज की बशा में) बिनौले से तेल निकालने के बाद प्राप्त पैदावार होगी।
स्वच्छ	10.0	24.0	7.0	28.0	9.0	2.5	कुछ नहीं	(2) पदार्थ ठोस होगा लेकिन बड़ बनावट का न हो। (3) यह हानिकारक प्रवयवों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगी। (4) यह खटवास, अपमिश्रण, कीटों या फफूँव-बाधा और किण्वित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (5) यह धूल और नाण पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण :—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-बारे के रूप में बिनौले की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया। ('आई०एस० 1712-1960)

## अनुसूची III ग

(नियम 3 और 4 देखिए)

छिलके रहित बिनौले की खली (मील) — (विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत बसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेसो का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार भ्रूसी का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	8.0	42.0	1.5	12.0	2.0	विलायक निस्सारित बिनौले की खली (मील) छिलके रहित बिनौले की खली से विलयक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। मील कुछ प्रारंभिक शोधन के बाद सीधे छिलके रहित बिनौले से भी प्राप्त की जा सकती है। निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली, बिनौले की खली साफ और ठोस छिलके रहित बिनौले के पेरने से प्राप्त की गई होगी।

1	2	3	4	5	6	7
स्वच्छ	8.0	40.0	2.0	14.0	2.5	विलायक के रेशे हटाने के लिए मील नियमित और विनियमित दशाग्रों के अधीन उष्मा और माप शोधन के अधीन रखी जाएगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डों की खली या भूसी और महुआ की खली से मुक्त होगा। यह सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगी।

टिप्पण :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-बारे के रूप में विलायक निस्सारित बिनीले की खली (मील) के लिए आपातकालीन भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया है।  
(आई० एस० 3592 ई०-1966)

निस्सारण के लिए विलायक :—निस्सारण के प्रयोजनों के लिए केवल हेक्सेस फूड ग्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा।  
विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

क्वथन दूरी—63° से 71° से० तक

ऐरोमुटिक तरब (अधिकतम) 1 प्रतिशत

अवाष्पशील तरब (अधिकतम) 0001 ग्राम/100 मि०लि०

#### अनुसूची IV क

(नियम 3 और 4 देखिए)

अलसी की खली (मील)—(पैरी टुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डों की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	10.0	29.0	8.0	10.0	8.0	1.5	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की खली बिजली चालित मशीनरी द्वारा अलसी के बीजों से तेल पेरने के बाद प्राप्त उपज होगी।
स्वच्छ	10.0	29.0	5.0	10.0	8.0	1.5	कुछ नहीं	(2) धानी खली पशुचालित धानी द्वारा अलसी के बीजों से तेल पेरने के बाद प्राप्त उपज होगी। (3) पदार्थ हानिकारक अवयवों और एरण्डों की खली या भूसी से मुक्त होगा।
धानी खली	10.0	26.0	15.0	6.0	9.0	2.5	कुछ नहीं	(4) यह खटांस, अपरिश्रण, कीट या फफूँव-आघा और किरूणित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण :—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-बारे के रूप में अलसी की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया है।

(आई०एस० 1935-1961)

## अनुसूची IV ब

(नियम 3 और 4 देखिए)

अलसी की खली (मील) विलायक निस्सारित की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राश का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
एरण्डी	10.0	33.0	1.0	9.0	2.5	विलायक निस्सारित अलसी की खली (मील) एक्सपेलर या घानी से पेरी गई अलसी की खली से विलायक के साधनों द्वारा नेत्र निस्सारण से प्राप्त की जाएगी। मील कुछ प्रारंभिक शोधन के बाद सीधे अलसी के बीज से भी प्राप्त की जा सकती है। निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली एक्सपेलर या घानी से पेरी गई अलसी की साफ और ठोस
सबुलु	10.0	29.0	1.5	11.0	2.5	अलसी (लिग्न प्यूसीटेडीसीयम एल०) पेरने से प्राप्त की गई होगी। प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने और विलायक के रेशे हटाने के लिए मील निर्यन्त्रित और विनियमित वशाओं के अधीन उष्मा और माप शोधन के अधीन रखी जाएगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों या महुआ की खली से मुक्त होगा। यह खटवास, अपमिश्रण, कीटों या फफूंद बाधा और सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगा।

टिप्पण :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-चारे के रूप में विलायक निस्सारित अलसी की खली (मील) के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया।

(आई०एस० 3440-1966)

निस्सारण के लिए विलायक :—निस्सारण के प्रयोजन के लिए केवल हैक्सेन—फूड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा।

विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

क्षयन दूरी ————— 63° से० से 71° से० तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम) ————— 1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम) ————— 0.001 ग्राम/100 मि०लि०

## अनुसूची V क

(नियम 3 और 4 देखिए)

सरसों की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत बसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशों का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	गरुडी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गरुडी	10.0	35.0	8.0	9.0	8.0	1.5	कुछ नहीं	(1) गरुडी और स्वच्छ श्रेणी की खली बिजली चालित मशीन द्वारा सरसों के बीज* से तेल पेरने के बाद प्राप्त उत्पाद होगी।
स्वच्छ	10.0	37.0	5.0	10.0	9.0	2.0	कुछ नहीं	(2) धानी की खली पशु चालित या कोल्हू द्वारा सरसों के बीज से तेल पेरने के बाद प्राप्त उत्पाद होगी।
धानी खली	12.0	33.0	12.0	7.0	8.0	2.0	कुछ नहीं	(3) पदार्थ आर्जीपोन और गरुडी की खली या भूसी सहित हानिकारक अवयवों से मुक्त होगी। (4) यह खटबास, अपमिश्रण, कीट या फफूँव-बाधा और क्षिप्त, सड़न या अन्य अप्रतिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

\*सरसों के बीज शब्द के अन्तर्गत राई (ब्रेसिका जिनिया कास) सरसों (ब्रेसिका कैम्पेस्टिस बैराइटी सरसों), सोरिया (ब्रेसिका कैम्पेस्टिस बैराइटी जोरिया) और तारामिरा (एक्सा स्टार्वा) आते हैं।

स्तर 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी होना के आधार पर संगणित हैं।

पशुधन-आरे के रूप में सरसों और सोरिया की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्दिष्ट से लिया गया। (आई० एस० 1932—1961)

## अनुसूची V ख

(नियम 3 और 4 देखिये)

सरसों की खली—विलायक निस्सारित की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत बसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशों का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
गरुडी	10.0	45.0	1.0	11.0	1.8	विलायक निस्सारित सरसों की खली (मील) ब्रकचालित एक्सपेलर या चक्की से पेरी गई खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। मील प्रारम्भिक शोधन के बाद ली घे

1	2	3	4	5	6	7
स्वच्छ	10.0	43.0	1.5	12.0	2.5	ठोस सरसों के बीज (राई-ब्रेसिका जन्सिया), धरसों (ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस), तोरिया (ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस) और तारा-मोरा (एस्कासेटाइवा) से भी प्राप्त की जा सकती है। प्रोटीन को विह्वल-करण से बचने और बिलायक के लेशो हटाने के लिए कीटक नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन उष्मा और भाप शोधक के अधीन रखी जायेगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों या मधुवा की खली या भार्जीमोन की खली से मुक्त होगा। यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद बाधा और सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगी।

टिप्पण :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है। भारतीय मानक संस्था विनिर्देश से नहीं लिया गया।

(2) निस्सारण के लिए बिलायक : निस्सारण के प्रयोजनों के लिए केवल हैक्सेन-फुड श्रेणी का बिलायक ही काम में लाया जाएगा।

बिलायक की प्रवेशां निम्नलिखित होंगी :—

क्षयन दूरी—63° से 71° से 71° से 71° तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम)—1 प्रतिशत

प्रवाहशील तत्व (अधिकतम)—0.001 ग्राम/100 मि० ली०

#### अनुसूची VI (क)

(नियम 3 और 4 देखिए)

सेसमम (तिल) की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत बसा या ईयर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेसो का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय घमल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	10.0	37.0	8.0	7.0	13.0	1.5	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की खली बिजली चासित मशीन द्वारा सेसमम (तिल) के बीज से तेल घेरने के बाद प्राप्त उपज होगी।
स्वच्छ	10.0	37.0	5.0	7.0	13.0	2.0	कुछ नहीं	(2) धानी की खली पशु चासित धानी द्वारा सेसमम (तिल) बीजों से तेल घेरने के बाद प्राप्त उपज होगी।
धानी खली	10.0	36.0	14.0	7.0	13.0	2.0	कुछ नहीं	(3) यह पदार्थ हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगा। (4) यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद बाधा और कृषित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (5) यह धूल या बाष्प पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण :—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-कारे के रूप में सेसमम (तिल) की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया। (आई० एस० 1934-1961)



**अनुसूची VI (क)**  
(नियम 3 और 4 देखिए)

सेसम (तिल) की खली—विलायक निस्सारण की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (साइटोजेन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर मास का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	10.0	44.0	1.0	8.5	1.8	विलायक निस्सारण सेसम (तिल) की खली एक्सपेलर या घानी से पेरी गई सेसम (तिल) की खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। खली कुछ प्रारम्भिक पोषण के बाद मीथे सेसम (तिल) के बीजों से भी प्राप्त की जा सकती है। निस्सारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक्सपेलर या घानी द्वारा पेरा गया सेसम (तिल) खली ठोस और स्वच्छ सेसम (तिल) बीजों को पेरने से प्राप्त की जानी चाहिए। प्रोटीन की दिव्यतीकरण से अचानक और विलायक के लेश हटाने के लिए कीटक नियंत्रित और घिनियमित दशाओं के अधीन ऊष्मा और वाष्प पोषण के अधीन रखा जाएगा। पदार्थ पंपड़ी या वर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डों की खली या भूसी या दोनों या महुवा की खली से मुक्त होगा। यह खटबाम अपमिश्रण, कीट, फफूंद बाधा और महान कुगन्ध से मुक्त होगी।
स्वच्छ	10.0	44.0	1.5	8.5	1.8	

टिप्पण :— (1) स्तम्भ 3 से 6 तक विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है। भारतीय मानक संस्था विनिर्देश से नहीं लिया गया क्योंकि उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) निस्सारण के लिए विलायक :—निस्सारण के प्रयोजनों के लिए केवल हैक्मेन—फुड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जायेगा।

विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होगी :—

क्षयन दूरी—83° से 71° तक

पेट्रोमेटिक तत्व (अधिकतम)—1 प्रतिशत

अवशोषण तत्व (अधिकतम) .0001/100 मि० ली०

**अनुसूची VII (क)**

(नियम 3 और 4 देखिए)

नारियल की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (साइटोजेन का 6.25) प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर मास का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डों की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	10.0	21.0	8.0	12.0	8.0	1.5	कुछ नहीं	(1) अच्छी श्रेणी की नारियल की खली विद्युत चालित मशीनों द्वारा खोपरे (सूखे नारियल की

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वच्छ	12.0	18.0	13.0	12.0	8.5	2.0	कुछ नहीं	गिरी) से प्राप्त उपज होगी। (2) धानी क्षेत्रों की खली पशु चालित धानी या लकड़ी द्वारा खोपरे (सूखे नारियल की गिरी) से तेल पेरने के बाद प्राप्त उपज होगी। (3) पदार्थ हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगा। (4) यह खटबास, अपमिश्रण, कीट या फफूँव बाधा और कवित, सड़न और अन्य प्रापसिजनक व दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण :—स्तम्भ 3 से 7 तक विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

पशुधन-चारे के रूप में नारियल की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया।

(आई० एस० 2154=1962)

#### अनुसूची VII (ख)

(नियम 3 और 4 देखिए)

नारियल की खली (मिल) विलायक निस्सारित की बवालिटो के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25 का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत बसा या ईथर मार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशों का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय ग्रन्थ राख का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	10.0	23.0	1.0	14.0	1.5	विलायक निस्सारित की खली (मील) एक्सपेलर या धानी से पेरी गई नारियल की खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली एक्सपेलर या धानी से पेरी गई नारियल की खली स्वच्छ और ठोस नारियल पेरने से प्राप्त की गई होगी। विलायक के लेशों हटाने के लिए मील नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन उष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी जायेगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगी। यह हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी या दोनों और मद्दमा की खली से मुक्त होगी। यह खटबास, अपमिश्रण, कीट या फफूँव बाधा और सड़न से मुक्त।
स्वच्छ	10.0	21.0	1.5	15.0	2.0	

टिप्पण :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है। पशुधन-चारे के रूप में विलायक निस्सारित नारियल की खली (मील) के लिए आपात-कालीन भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया (आई० एस० : 3591 ई—1966)

(2) निस्सारण के लिए विलायक निस्सारण के प्रयोजन के लिए केवल ऐक्सेन-फूड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जायेगा। विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होगी :—

व्ययन दूरी—63° से० से 71° से० तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम)—1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम)—0001 ग्राम/100 मि० लि०

## अनुसूची VIII क

(नियम 3 और 4 देखिए)

कुसुम की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशों का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत कुल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अण्डी	8.0	41.0	8.0	13.0	8.0	1.0	कुछ नहीं	(1) अण्डी और स्वच्छ श्रेणियों की खली कुसुम के बीज (कार्यमस टिण्डोरियस एल) की उपज होगी जो विद्युत चालित मशीनरी द्वारा ठोस और स्वच्छ बीजों से तेल पेरने के बाद प्राप्त की गई होगी।
स्वच्छ	8.0	39.0	10.0	15.0	8.0	2.0	कुछ नहीं	(2) धानी खली पशु चालित धानी या चक्की के द्वारा स्वच्छ और ठोस कुसुम के बीज (कार्यमस टिण्डोरियस एल) से तेल पेरने के बाद प्राप्त उपज होगी।
धानी खली	10.0	38.0	13.0	12.0	8.0	1.0	कुछ नहीं	(3) पदार्थ ठुक् बनावट का होगा। (4) यह हानिकारक अवशेषों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगी। (5) यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और कृषिगत, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (6) यह धूल और वाष्प पदार्थ से मुक्त होगी।

टिप्पण :- स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

## अनुसूची VIII ख

(नियम 3 और 4 देखिए)

कुसुम की खली (विलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर सार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशों का प्रतिशत (अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अण्डी	10.0	50.0	1.0	1.5	15.0	विलायक निस्सारित कुसुम की खली (मील) धानी या एक्सपेलर से पेरी गई कुसुम की खली से विलायक साधनों द्वारा तेल

1	2	3	4	5	6	7
स्वच्छ	10.0	47.0	1.0	2.5	18.0	निस्सारण से प्राप्त की जायेगी। धानी या एकपेलर से पेरी गई कुसुम की खली साथ और ठोस कुसुम के बीज (कार्यमम टिण्टोरियस एल) पेरने से प्राप्त की गई होगी। प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने और विलायक के लेशो हटाने के लिये निस्सारित खली नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन रखी जायेगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों या एरण्डी की खली से मुक्त होगी। यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूँव बाधा और सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगी।

- टिप्पण :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।  
 (2) विनिर्देश प्रारूप की अवस्था में भारतीय मानक संस्था के पास है और अभी तक उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।  
 (3) निस्सारण के लिए विलायक-निस्सारण के प्रयोजन के लिए केवल हेक्सेन-फुड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जायेगा। विलायक की अवशेषां निम्नलिखित हैं :—  
 अवयव दूरी—63° से 71° से. तक  
 ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम)—1 प्रतिशत  
 अवशेषांशील तत्व (अधिकतम)—0.001 ग्राम/100 मि० लि०

## अनुसूची IX क

(नियम 3 और 4 देखिए)

तिल्ली की खली (पेरी हुई) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अपरिष्कृत प्रोटीन ताइटीजन 6.25 का प्रतिशत	वजन के अपरिष्कृत बसा या ईथर सार (न्यूनतम)	वजन के अपरिष्कृत रेजो का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अपरिष्कृत राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अपरिष्कृत अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	एरण्डी की भूसी	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अच्छी	9.0	29.0	8.0	9.0	8.0	1.0	कुछ नहीं	(1) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की खली तिल्ली के बजी (म्यूजोटिया एथीसीनिका कास) की पैदावार होगी जो बिजली चालित मशीनरी द्वारा ठोस और स्वच्छ तिल्ली के बीज से तेल पेरने के बाद प्राप्त होगी। (2) धानी खली पशु चलिध धानी या चक्की द्वारा स्वच्छ और ठोस तिल्ली के बजी (म्यूजोटिया एथीसीनिका कास) से तेल पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी। (3) पदार्थ बूँद बनावट का होगा। (4) यह हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या भूसी से मुक्त होगी। (5) यह खटवास, अपमिश्रण, कीटो या फफूँव-बाधा और किण्वित, सड़न या अन्य आपत्तिजनक दुर्गन्ध से मुक्त होगी। (6) यह धूल और बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।
स्वच्छ	9.0	28.0	10.0	12.0	8.0	2.0	कुछ नहीं	
धानी खली	10.0	27.0	13.0	9.0	8.0	1.0	कुछ नहीं	

टिप्पण :—स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है।

## अनुसूची IX ख

(नियम 3 और 4 देखिए)

तिल्ली की खली (बिलायक निस्सारित) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार तमी का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत प्रोटीन (नाइट्रोजन 6.25) का प्रतिशत (न्यूनतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत चर्मा या ईथर मार का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अविलेय अम्ल राख का प्रतिशत (अधिकतम)	वजन के अनुसार अपरिष्कृत रेशे का प्रतिशत (अधिकतम)	माधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
अच्छी	9.0	35.0	1.0	1.5	12.0	बिलायक निस्सारित तिल्ली की खली (मील) घानी या एक्सपेलर से पेरी गई तिल्ली की खली से बिलायक के माधनों द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जाएगी। घानी या एक्सपेलर से पेरी गई तिल्ली की खली साफ ठोस तिल्ली के बीज (गुजोटिय, एबीमीनिक, काम) पेरने से प्राप्त की गई होगी। प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने या बिलायक के लेशे हटाने के लिए मील नियंत्रित और विनियमित दशाओं के अधीन उष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी जाएगी। पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों या एरण्डी की खली या भूसी या दोनों या महुवा की खली से मुक्त होगा। यह खटवास, अपमिश्रण, कीट या फफूंद-बाधा और मृदु दुर्गन्ध से मुक्त होगी।
स्वच्छ	9.0	29.0	1.0	2.5	15.0	

टिप्पण :—(1) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान सभी हीमता के आधार पर संगणित है।

(2) विनिर्देश प्रारूप के प्रक्रम पर भारतीय मानक संस्था के पास है और अभी तक उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(3) निस्सारण के लिए बिलायक प्रारूप निस्सारण के प्रयोजन के लिए केवल हेक्सेन-फूड श्रेणी का बिलायक ही काम में लाया जाएगा। बिलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

क्षयन दूरी—63° से 71° से 0 तक

ऐरोमेटिक तत्व (अधिकतम)—1 प्रतिशत

अवाष्पशील तत्व (अधिकतम)—0.001 ग्राम/100 मि० लि०

[सं० फा० 13-8/76-ए० एम]

New Delhi, the 9th January, 1978

**S.O. 252.**—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of the Oil Cakes Grading and Marketing Rules, 1962, is hereby published, as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fortyfive days from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

## DRAFT RULES

1. Short title and application.—These rules may be called Vegetable Oil Cakes (Expressed or Solvent Extracted) Grading and Marking Rules, 1978.

2. Definition.—In these rules,

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designations.—The grade designations to indicate the quality of oil cakes (expressed or solvent extracted) shall be as set out in column (1) of Schedule II A to IX B.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designation in Schedules II A to IX B.

5. Grade designation marks.—The grade designation mark shall consist of a label bearing the design set out in Schedule I and specifying the grade designation, the name of the cake and whether it is expressed or solvent extracted.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed or stencilled on each container in a manner approved by the Agricultural marketing Adviser and shall also indicate the number of the Certificate of Authorisation issue to the packer by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition, on every container the following particulars shall clearly and indelibly be marked :—

- (a) Lot number
- (b) Name of Packer
- (c) Date of packing
- (d) Place of packing.

(3) The authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said Officer, provided that the private trade mark does not represent quality or grade of the oil cake different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(i) The oil cake shall be packed only in containers made of jute or other material approved by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(ii) Each container shall be securely closed and sealed and shall contain oil cake of one trade description and of one grade designation only.

8. Special conditions of Certificate of Authorisation.—In addition to the conditions specified in rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the following conditions shall also be the conditions of every Certificate of Authorisation issued for the purpose of these rules, namely :—

- (i) each authorised packer shall take all precautions to avoid admixture of oil cakes with castor seeds and castor cake.
- (ii) if an authorised packer handles more than one type of oil cake in the same premises, adequate precautions shall be taken by him to avoid mixing of different oil cakes. The premises should be clean and hygienic and should be periodically fumigated.

(iii) the authorised packer shall make such arrangements for testing oil cakes as may be specified from time to time by the Agricultural Marketing Adviser and shall also maintain proper records of analysis of the samples.

(iv) all instructions regarding methods of sampling and analysis, packing and marking and maintenance of records, which may be issued from time to time by the Agricultural Marketing Adviser, shall be observed.

(v) a sample of oil cake drawn in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser from each lot, shall be forwarded to such control laboratory as may be notified from time to time.

#### SCHEDULE I

(See rule 5)

Grade designation mark for labels



#### SCHEDULE III A

(See rules 3 and 4)

Grade, designations and definitions of quality of groundnut oil cake expressed

Grade Designations	Moisture per cent by weight (Maximum)	Crude protein nitrogen $\times 6.25$ per cent by weight (Minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (Minimum)	Crude fibre, per cent by weight (Maximum)	Total ash per cent by weight (Maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (Maximum)	Castor husk	General Characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	8.0	50.0	8.0	9.0	7.0	1.5	Nil	1. Oil cake of good and fair grade shall be the products of decorticated groundnut along obtained after the extraction of oil by powerdriven machinery.
Fair	8.0	50.0	5.0	9.0	7.0	2.0	Nil	2. Ghani oil cake shall be the product of decorticated groundnut along obtained after the extraction of oil by animal driven ghani or chakki.
Ghani Cake	10.0	45.0	10.0	9.0	7.0	2.5	Nil	3. The material shall be of firm texture. 4. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk. 5. It shall be free from rancidity, adulterant, insect or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour. 6. It shall be free from dirt and extraneous matter.

Note :—The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis. Adopted from the Indian Standard Specification for decorticated groundnut oilcake as livestock feed; IS : 1713—1960).

## SCHEDULE II B

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of groundnut oil cake-solvent extracted

Designation	Moisture per cent by weight (Maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25) by weight (Minimum)	Crude fat other extract per cent by weight (Maximum)	Crude fibre per cent by weight (Maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (Maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8
Good	10.0	51.0	1.0	10.0	2.5	Nil	1. The solvent extracted groundnut oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the expeller or ghani pressed groundnut oil cake. The meal may also be obtained directly from groundnut seeds after a preliminary treatment. The expeller or ghan pressed groundnut oil cake used for extraction shall have been obtained by pressing clean and sound groundnut ( <i>Arachis hypogee</i> L). The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and removal of traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both or mahua cake. It shall be free from rancidity, adulterants, insects or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	47.0	1.5	12.0	2.5	Nil	

Notes :—(1) The value specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis.

Adopted from the Indian Standard Specification for solvent extracted oil cake (meal) as Livestock feed (IS: 3441-1966).

(2) Solvent for extraction :—Only Food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows :—

Boiling range 63° C to 71° C

Aromatic content Maximum 1 per cent.

Non-volatile content, maximum 0.001 g./100 ml.

## SCHEDULE III A

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of decorticated cotton seed oil cake-expressed

Grade designation	Moisture per cent by weight (Maximum)	Crude protein (nitrogen x 6.25) per cent by weight (Minimum)	Crude fat for other extract, per cent by weight (Minimum)	Crude fibre per cent by weight (Maximum)	Total ash, per cent by weight (Maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (Maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	8.0	40.0	8.0	10.0	7.0	1.5	Nil	1. Shall be the product of clean cotton seed only. Composed principally of the kernel with such unavoidable portions of the hull and fibre as may be left in the course of manufacture of oil. 2. The material shall be firm not flinty in texture. 3. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk. 4. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour. 5. It shall be free from dirt and extraneous matter.
Fair	8.0	41.0	5.0	12.0	8.0	2.0	Nil	
No. 2	8.0	37.0	5.0	14.0	9.0	2.5	Nil	

Note :—The value specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

Adopted from the Indian Standard Specification for cotton seed oil cake as Livestock feed (IS : 1712-1960).

## SCHEDULE III B

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of undecorticated cotton-seed oil-cake expressed

Grade Designation	Moisture per cent by weight (Maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat for other extract per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash per cent by weight (maximum)	Acid soluble ash per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	24.0	7.0	24.0	9.0	2.5	Nil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shall be the product resulting from the whole clean and wherever necessary (specially) in the case of (fuzzy seeds) cotton seed only after the expression of oil.</li> <li>2. The material shall be firm but not flinty in texture.</li> <li>3. It shall be free from harmful constituents and castor cakes or husk.</li> <li>4. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour.</li> <li>5. Shall be free from dirt and extraneous matter.</li> </ol>
Fair	10.0	24.0	7.0	28.0	9.0	2.5	Nil	

Note : The value specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.  
Adopted from Indian Standard specification for cotton seed oil cake as livestock feed (IS : 1712-1960)

## SCHEDULE III C

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of decorticated cotton seed oil cake (meal) solvent extracted

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or extract per cent by weight (maximum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	8.0	42.0	1.5	12.0	2.0	<p>The solvent extracted cotton seed oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the decorticated cotton seed oil cake. The meal may also be obtained directly from decorticated cotton seed after a certain preliminary treatment. Cotton seed oil cake used for extraction shall have been obtained by pressing clean and sound decorticated cotton seed. The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated reconditions so as to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes of powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both under andmahua cake. It shall be free from musty odour.</p>
Fair	8.0	40.0	2.0	24.0	2.5	

- Notes :—1. The value specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis. Adopted from the Emergency Indian Standards Specifications for solvent extracted cotton seed oil cake Meal as livestock feed (IS : 3592E—1966).
2. Solvent from extraction : only hexane-food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirement of the solvent shall be as follows :
- Boiling range 63° C to 71° C.
- Aromatic content Max.....1 per cent
- Non volatile content Max.....0.001 gm./100 ml.



## SCHEDULE IV A

(See rules 3 and 4)

## Grade designations and definition of quality of linseed oil cake (meal) expressed

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or either extract per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by weight (maximum)	Acid in soluble ash per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	29.0	8.0	10.0	8.0	1.5	Nil	1. Oil cake of good and fair grades shall be the product obtained after the extraction of oil from linseed by power-driven machinery.
Fair	10.0	29.0	5.0	10.0	8.0	1.5	Nil	
Ghani cake	10.0	26.0	15.0	6.0	9.0	2.5	Nil	2. Ghani oil cake shall be the product obtained after the extraction of oil from linseed by animal-driven ghani. 3. The material shall be free from harmful constituents and castor cake or husk. 4. It shall be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour. 5. It shall be free from dirt and extraneous matter.

Note :— The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

Adopted from the Indian Standards Specifications from linseed oil cake as livestock feed (IS : 1935—1961).

## SCHEDULE IV B

(See rules 3 and 4)

## Grade designations and definition of quality of linseed oil cake solvent extracted

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or either extract per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	33.0	1.0	9.0	2.5	The solvent extracted linseed oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil, by means of solvent from the expeller or ghani pressed linseed oil cake. The meal may also be obtained directly from linseeds after a certain preliminary treatment. The extraction shall have been obtained by pressing clean and sound linseed ( <i>Linum-usitatissimum</i> L.) The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both or mahua cake. It shall be free from rancidity, adulterants, insects or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	29.0	1.5	11.0	2.5	

Note :—1. The values specified in columns 3 to 6 are Calculated on moisture free basis.

Adapted from the Indian Standards Specification for solvent extracted linseed oil cake (meal) as livestock feed (IS : 3440-1966).

2. Solvent from extraction : Only hexane food grade solvent shall be used for the purpose of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows :—

Boiling range 63°C to 71°C.

Aromatic content max. 1 per cent.

Non-volatile content, max. 0.001 gm./100 ml.

## SCHEDULE V A

(See rules 3 and 4)

## Grade designations and definition of quality of Mustard Oil Cake-expressed

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	35.0	8.0	9.0	8.0	1.5	Nil	1. Oil cake of good and fair grades shall be the product obtained after the extraction of oil from mustard seed* by power-driven machinery. 2. Ghani oil cake shall be the product obtained after the extraction of oil from mustard seed* by animal driven ghani or kolhu. 3. The material shall be free from harmful constituents including argemons and castor cake or husk. 4. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from farmented musty or other objectionable odour. 5. It shall be free from dirt and extraneous matter.
Fair	10.0	37.0	5.0	10.0	9.0	2.0	Nil	
Ghani Cake	12.0	33.0	12.0	7.0	8.0	2.5	Nil	

\*The term mustard seed includes rai (*Brassica juncea* coss), Sarson (*Brassica campestris* Var Sarson), toria (*N. Brassica Campestris* Var Toria) and taramira (*Eruca sativa*). The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

Adapted from the Indian Standards Specifications for mustard and range rape oil cake as Livestock feed (IS : 1932-1961).

## SCHEDULE V B

(See rules 3 and 4)

## Grade designation and definition of quality of mustard oil-cake-solvent extracted

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (maximum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (maximum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	45.0	1.0	11.0	1.8	The solvent extracted mustard oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the hydraulic expeller or rotory pressed oil cake. The meal may also be obtained directly from sound mustard seed raitoria ( <i>Brassica campestris</i> ), and tara Mira ( <i>Eruca sativa</i> ) after a preliminary treatment. The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both or mahua cake or argemone cake. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	43.0	1.5	12.0	2.3	

Notes :—1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis. Not adopted from Indian Standards Institution Specifications.

2. Solvent for extraction : Only haxane food solvent shall be used for the purposes of extraction.

The requirement of the solvent shall be as follows :—

Boiling range 63°C to 71°C. Aromatic content max. 1 per cent.

Non-volatile content maximum 0.001 gm./100 ml.

## SCHEDULE VI A

(See rules 3 and 4)

## Grade designation and definition of quality of sesamum (till) oil cake—expressed

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen 6.25) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	37.0	8.0	7.0	13.0	1.5	Nil	1. Oil cakes of good and fair grades, shall be the products obtained after the extraction of oil from sesamum (till) seed by powder driven machinery. 2. Ghani cake shall be the product obtained after the extraction of oil from sesamum (till) seeds by animal-driven ghani. 3. The material shall be free from harmful constituents and castor cake or husk. 4. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour. 5. It shall be free from dirt or extraneous matter.
Fair	10.0	37.0	5.0	7.0	13.0	2.0	Nil	
Ghani cake	10.0	36.0	14.0	7.0	13.0	2.0	Nil	

Note :— The value specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis. Adopted from the Indian Standards Specifications for sesamum (till) oil cake as Livestock feed (IS : 103 1934—1961).

## SCHEDULE VI B

(See rules 3 and 4)

## Grade designations and definition of quality of sesamum (till) oil cake—solvent extracted

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein, (nitrogen 6.25) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	44.0	1.0	8.5	1.8	The solvent extracted sesamum (till) oil cake shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the expeller or ghani pressed sesamum (till) oil cake. The oil cake may also be obtained directly from sesamum (till) seeds after a certain preliminary treatment. The expeller or ghani pressed sesamum (till) seeds oil cake used for extraction shall have been obtained by pressing clean and sound sesamum (till) seed. The oil cake shall have been subjected to heat and steam treatment under controller and regulated conditions so as to prevent denaturation of protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both or mahua cake. It shall be free from rancidity adulterants, insect or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	44.0	1.5	8.5	1.8	

Notes :— 1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis. Not adopted from the Indian Standard Specification as the same are not yet finalised.

2. Solvent for extraction : Only hexane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirement of the solvent shall be as follows :—

Boiling range 63°C to 71°C Aromatic content maximum 1 per cent.

Non-volatile content maximum 0.001 gms/100 ml.

## SCHEDULE VII A

(See rules 3 and 4)

## Grade designations and definition of quality of coconut oil cake-expressed

Grade designation	Moisture, per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or either extract per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	10.0	21.0	8.0	12.0	8.0	1.5	Nil	1. Coconut oil cake of grade good shall be the product obtained after the extraction of oil from copra (dried coconut kernels) by power-driven machinery. 2. Ghani grade oil cake shall be the product obtained after the extraction of oil from copra (dried coconut kernels) by the animal driven ghani or chakka. 3. The material shall be free from harmful constituents and castor cake or husk. 4. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus musty and other objectionable odour. 5. It shall be free from dirt and extraneous matter.
Ghani	12.0	18.0	13.0	12.0	8.5	2.0	Nil	

Note :— The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis. Adopted from the Indian Standard Specification for coconut oil cake as Livestock feed (IS : 2154-1962)

## SCHEDULE VII B

(See Rules 3 and 4)

## Grade designations and definition of quality of coconut oil cake (meal) solvent extracted

Grade designation	Moisture, per cent by weight (minimum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by (maximum)	Acid insoluble, ash, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	23.0	1.0	14.0	1.5	The solvent extracted coconut oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the expeller or ghani pressed coconut oil cake. The expeller or ghani pressed coconut oil cake used for extraction shall have been obtained by pressing clean and sound coconut. The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk or both mahua cake. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	21.0	1.5	15.0	2.0	

Notes:— 1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis. Adopted from 'Emergency Indian Standards Specification for a solvent extracted coconut oil cake (meal) as livestock feed (IS: 3591-E-1966)

2. Solvent for extraction : Only hexane food grade solvent shall be used for the purpose of extraction. The requirement of the solvent shall be as follows:—

Boiling range 63°C to 71°C

Aromatic content max; 1 per cent Non-volatile content max. 0.001 gms./100 ml.

## SCHEDULE VIII A

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of safflower oil cake—expressed

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash per cent by weight (maximum)	Acid insoluble, ash per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	8.0	41.0	8.0	13.0	8.0	1.0	Nil	1. Oil cake of good and fair grades shall be the product of safflower seeds ( <i>Carthamus tinctorius</i> L.) obtained after the extraction of oil from sound and clean seeds by power-driven machinery. 2. Ghani oil cake shall be the product obtained after the expression of oil from clean and sound and Safflower seeds. ( <i>Carthamus tinctorius</i> L.) by animal-driven ghani or chakka. 3. The material shall be of firm texture. 4. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk. 5. It shall be free from rancidity adulterants and insects or fungus infestation and from fermented musty or other objectionable odour. 6. It shall be free from dirt and extraneous matter.
Fair	8.0	39.0	10.0	15.0	8.0	2.0	Nil	
Ghani cake	10.0	38.0	13.0	12.0	8.0	1.0	Nil	

Note: The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

## SCHEDULE VIII B

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of safflower oil cake-solvent extracted

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (maximum)	Crude fat or other extract, per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash per cent by weight (maximum)	Crude fibre, per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	10.0	50.0	1.0	1.5	15.0	The solvent extracted safflower oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the ghani or expeller pressed safflower oil cake. The ghani or expeller pressed safflower oil cake shall have been obtained by pressing clean and sound safflower seeds ( <i>Carthamus tinctorius</i> L.) The extracted oil cake (meal) shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and to remove traces of solvent. The material shall be in the form of either flakes or powder and shall be free from harmful constituents or castor cake or husk or both of mahua cake. It will be free from rancidity adulterants, insect or fungus infestation and from musty odour.
Fair	10.0	47.0	1.0	2.5	18.0	

Notes:—1. The values specified under columns 3 to 6 are on moisture free basis.

2. The specifications are at draft stage with the Indian Standards Institutions and not yet finalised.

3. Solvent for extraction : Only hexane food grade solvent shall be used for the purpose of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows:—  
 Boiling range 63°C to 71°C.  
 Aromatic content max. : 1 per cent.  
 Non-volatile content max. : 0.001 gm./100 ml.

## SCHEDULE IXA

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of niger seed oil cake—expressed

Grade designation	Moisture per cent by weight (Maximum)	Crude protein/ (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract per cent by weight (minimum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	Total ash per cent by weight (maximum)	Acid soluble ash per cent by weight (maximum)	Castor husk	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Good	9.0	29.0	8.0	9.0	8.0	1.0	Nil	1. Oil cake of good and fair grade shall be the product of niger seeds ( <i>Guizotia abyssinica</i> Cass) obtained after the extraction of oil from sound and clean niger seeds by power-driven machinery. 2. Ghani oil cake shall be the product obtained after the extraction of oil from clean and sound niger seeds ( <i>Guizotia abyssinica</i> Cass) by animal-driven ghani or chakka. 3. The material shall be in firm texture. 4. It shall be free from harmful constituents and castor cake or husk. 5. It shall be free from rancidity adulterants, insects or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odour. 6. It shall be free from dirt and extraneous matter.
Fair	9.0	23.0	10.0	12.0	8.0	2.0	Nil	
Ghani cake	10.0	27.0	13.0	9.0	8.0	1.0	Nil	

Note: The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis.

## SCHEDULE IX B

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of niger seed oil cake-solvent extracted

Grade designation	Moisture per cent by weight (maximum)	Crude protein (nitrogen $\times 6.25$ ) per cent by weight (minimum)	Crude fat or other extract per cent by weight (maximum)	Acid insoluble ash per cent by weight (maximum)	Crude fibre per cent by weight (maximum)	General characteristics
1	2	3	4	5	6	7
Good	9.0	35.0	1.0	1.0	12.0	The solvent extracted niger oil cake (meal) shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from the ghani or expeller pressed niger seed oil cake shall have been obtained by pressing clean, sound niger seed ( <i>Guizotia abyssinica</i> Cass). The meal shall have been subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and to remove traces of solvent. The material shall be free from harmful constituents of castor cake or husk or both or mahua cake. It shall be free from rancidity adulterants, insect or fungus infestation and from misty odour.
Fair	9.0	29.0	1.0	2.5	15.0	

Notes : 1. The values specified under columns 3 to 6 are on moisture free basis.

2. The specifications are at draft stage with Indian Standards Institution and not yet finalised.

3. Solvent for extraction : Only hexane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The requirements of the solvent shall be as follows:—

Boiling range 63°C to 71°C Aromatic content max. : 1 per cent.

Non-volatile content max. : 0.001 gm/100 ml.

## शुद्धिपत्र

कां०अ० 253—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 31 जुलाई, 1976 के पृष्ठ 2644 से 2646 पर प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्राम विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० भा० 2783 तारीख 13 जुलाई 1976 में निम्नलिखित शब्दों की जाएंगी अर्थात :—

1. उक्त अधिसूचना में जहाँ कहीं भी "अंकन" शब्द आया है उसके स्थान पर "चिह्नकित" शब्द पढ़ें।
2. नियम 5 के उपनियम 2 में,
  - (1) "अभिधान चिह्न" के स्थान पर "श्रेणी अभिधान चिह्न" पढ़ें।
  - (2) "प्राधिकरण के प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण प्रमाणपत्र" शब्द पढ़ें।
3. नियम 6 के उपनियम (3) में;—
  - (1) दूसरी पंक्ति में, "व्यवस्थित" शब्द के स्थान पर "उपवर्णित" शब्द पढ़ें;

(2) तीसरी पंक्ति में, "आधान" शब्द के पश्चात् "पात्र" शब्द जोड़ें;

4. नियम 7 के उपनियम (i) में (ii) खण्ड (क) में 'अक्षत' शब्द के स्थान पर "मजबूत" शब्द पढ़ें।

(ii) उप नियम 2 में, "आधानों" के स्थान पर "आधान पात्र" शब्द पढ़ें;

5. अनुसूची 2 में (i) स्तम्भ शीर्ष 6 में "K<sub>2</sub>O" अक्षर और अंकों के स्थान पर "K<sub>2</sub>O" पढ़ें;

(ii) स्तम्भ 8 में (क) मद (1) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "बाव" पढ़ें;

(ख) मद (ख) में "रजक" शब्द के स्थान पर "रंजक" शब्द पढ़ें।

[संख्या 13-2/74-ए०एम०]  
ए० के० अग्रवाल, उप सचिव

## CORRIGENDA

S.O. 253.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Rural Development) No. S.O. 2783, dated the 13th July, 1976, published at pages 2644 to 2648 in the Gazette of India—Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 31st July, 1976.—

(i) in rule 7, in sub-rule (1), in clause (a), for "sound the clean," read "sound and clean";

(ii) in SCHEDULE—II,—

(a) below the heading "Grade Designation and Definition of quality of Kangra Tea", for the column numbers and the headings above them, read—

Grade Designation	Particulars of quality Special Characteristics						General Characteristics
	Total ash percentage by weight	Total ash soluble in boiling distilled water minimum	Ash insoluble in HCL Maximum % by weight	Water soluble extract minimum % by weight	Alkalinity of soluble Ash expressed as K <sub>2</sub> O % by weight	Crude fibre % by weight maximum	
1	2	3	4	5	6	7	8

(b) in column 8, in item 1, for "Camellia tea", read "Camellia thea";

(iii) in SCHEDULE-III, in item (f), for "forward" read "forwarded".

[No. F. 13-2/74-AM]  
A. K. AGARWAL, Dy. Secy.

## पर्यटन और माणर मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1977

कां०अ० 254—केन्द्रीय सरकार वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 44 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायु निगम नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम वायु (निगम संशोधन) नियम, 1977 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. वायु निगम नियम, 1954 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात :—

"(घ) "प्रबन्ध निदेशक"—से निगम का प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है;"

3. उक्त नियम के नियम 3 में, उप नियम (4) में,

(i) "फरवरी के प्रथम दिन" शब्दों के स्थान पर "अप्रैल के प्रथम दिन" शब्द रखे जायेंगे,

(ii) "पूर्ववर्ती वर्ष" शब्दों का खोप किया जाएगा;

4. उक्त नियम के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा।

"6. वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा तैयार करना और प्रस्तुत करना—प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निगम के कार्यों और क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तथा निगम के वित्तीय परिणामों को दक्षित करते हुए वार्षिक लेखा ऐसे समनुषंगी लेखा के साथ तैयार किया जाएगा जो केन्द्रीय

सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट और लेखा, जिसे निगम की सामान्य मुद्रा लगा कर प्राधिकृत किया गया हो और जो उसके द्वारा सम्यक् रूप से पारित हो, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के समक्ष आगामी 31 अगस्त को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त रिपोर्ट और लेखा, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा सम्यकरूप से लेखा परीक्षा किए जाने और प्रमाणित किए जाने के पश्चात् आगामी 30 सितम्बर को या उससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु निगम से कोई अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार, उक्त नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की समिति से, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक या केन्द्रीय सरकार को लेखा प्रस्तुत किए जाने की तारीख उतनी अवधि तक बढ़ा सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।

5. उक्त नियम के नियम 8 में, अन्त में निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे अर्थात् :—

“किन्तु निगम, आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग करके भंडारों, औजारों और संयंत्रों की चुनी हुई मयों के स्थापन की व्यवस्था कर सकेगा।”

6. उक्त नियम के नियम 15 में, उप-नियम (2) में, खंड (ग) में “बेतार प्रचालक” शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 16 में, जहां कहीं भी “पौण्ड” “मील भत्ता” और “मील” शब्द आए हों उनके स्थान पर, क्रमशः “किलोग्राम” “किलोमीटर भत्ता” और “किलोमीटर” शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 41 का लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियम के नियम 43 में, उप नियम (1) में, “वायुयान के प्रचालन कर्माधिकारी का कोई सदस्य” शब्दों के स्थान पर “निगम को कोई कर्मचारी” शब्द रखे जायेंगे।

10. उक्त नियम के नियम 43-क और 43-ख में, जहां कहीं भी “महाप्रबन्धक” शब्द आए हों उनके स्थान पर “प्रबन्ध निदेशक” शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियम के नियम 50 का लोप किया जाएगा।

12. उक्त नियम के नियम 51 में;

(1) उप नियम (2) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्

“(क-क) समिति का कोई सदस्य समिति के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर समिति से पदत्याग कर सकेगा। पद त्याग, त्यागपत्र में वर्णित तारीख से या समिति के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्तवर्ती हो, प्रभावी होगा।”

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधि निगम के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न एककों में कार्य कर रहे कर्मचारियों में से गुप्त मतदान द्वारा, निर्वाचित किए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी बारह से अनधिक उतनी इकाइयों में विभक्त किए जाएंगे जितनी निगम समय-समय पर अवधारित करे।”

(iii) उपनियम (5) में, खण्ड (ख) में “निगम का प्रधान कार्यपालक अधिकारी” जो श्रम कल्याण का भारसाधक हो शब्दों के स्थान पर निगम का प्रधान कार्यपालक अधिकारी “जो श्रम कल्याण का भारसाधक हो या उसका नाम निर्देशित शब्द रखे जाएंगे।

13. उक्त नियम के नियम 55 में, उप नियम (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु गणवृत्ति का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ किसी आकस्मिक रिक्ति को लेख में नहीं लिया जाएगा।”

14. उक्त नियम के अध्याय 9-ख में, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रबन्ध निदेशक की सेवा के नियन्त्रण और शर्तें”

15. उक्त नियम के नियम 58-ख में “महाप्रबन्धक” शब्दों के स्थान पर “प्रबन्ध निदेशक” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० ए० बी० 18012/5/74-ए० सी०]

सी० एल० डोंगरा, उप सचिव

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 12th September, 1977

**S.O. 254.**—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Air Corporation Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Air Corporations (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Air Corporations Rules, 1954 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

“(d) “Managing Director” means “the Managing Director of the Corporation”.

3. In rule 3 of the said rules, in sub-rule (4),—(i) for the words “first day of February”, the words “first day of April” shall be substituted ;

(ii) the words “preceding the year” shall be omitted.

4. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“6. Preparation and submission of annual report and annual accounts.—As soon as may be after the end of each financial year, an annual report on the work and activities of the Corporation and the annual accounts showing the financial results of the Corporation shall be prepared with such subsidiary accounts as may be specified by the Central Government. The report and accounts authenticated by affixing the common seal of, and duly passed by, the Corporation shall be submitted to the Comptroller and Auditor General of India on or before the 31st day of August following. The said report and accounts duly audited and certified by the Comptroller and Auditor-General shall be submitted to the Central Government on or before the 30th September following :

Provided that on a request received from the Corporation, the Central Government may, with the concurrence of the said Comptroller and Auditor General, extend the date of submission of the accounts to the Comptroller and Auditor General or to the Central Government by such period as it may think fit.”

5. In rule 8 of the said rules, the following words shall be inserted at the end, namely :—

“The Corporation may, however, arrange for verification of selected items of stores, tools and plant by using the latest techniques.”

6. In rule 15 of the said rules, in sub-rule (2), in clause (c) the words, “wireless operators” shall be omitted.

7. In rule 16 of the said rules, for the words “lbs”, “mileage” and “miles”, wherever they occur, the words “kgs”, “kilometres” and “kilometres”, shall respectively be substituted.

8. Rule 41 of the said rules shall be omitted.



9. In rule 43 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "a member of the operating crew of an aircraft" the words "any employee of the Corporation" shall be substituted.

10. In rules 43-A and 43-B of the said rules, for the words "General Manager", wherever they occur, the words "Managing Director" shall be substituted.

11. Rule 50 of the said rules shall be omitted.

12. In rule 51 of the said rules,—

(i) in sub-rule (2), after clause (a), the following clause shall be inserted at the end, namely :—

"(a-a) A member of the Committee may resign from the Committee by giving a notice in writing to the Chairman of the Committee. The resignation shall be effective from the date mentioned in the letter of resignation or from the date of acceptance of the resignation by the Chairman of the Committee, whichever is later."

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The representatives of employees on the Committee shall be elected by the employees of the Corporation by means of secret ballot from amongst employees working in various units and for this purpose, the employees shall be divided into such number of units not exceeding twelve as the Corporation may determine from time to time."

(iii) In sub-rule (5), in clause (b), for the words "The principal executive officer of the Corporation in charge of labour welfare", the words "The principal executive officer of the Corporation in Charge of labour welfare or his nominee" shall be substituted.

13. In rule 55 of the said rules, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted at the end namely :—

"Provided that for the purpose of determining the quorum, any casual vacancy shall not be taken into account."

14. In Chapter IX-B of the said rules, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"The terms and conditions of Service of Managing Director".

15. In rule 58-B of the said rules, for the words "General Managers", the words "Managing Directors" shall be substituted.

[No. A. V. 18012/5/74-AC]

C. L. DHINGRA, Dy. Secy.

### नौबहम व परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

का० आ० 255.—दीपघर अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दीपघरों को "सामान्य दीपघर" घोषित करती है, अर्थात् :—

1. कम्बोयङ्क दीपघर ।
2. बेपुर दीपघर ।

[का० सं० 33-डी(2)/76]

एस० आर० राव, अवसर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 7th January, 1978

S.O. 255.—In pursuance of Clause (c) of section 2 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), the Central Government hereby declares the following lighthouses to be "General Lighthouses" for the purpose of the said Act, namely :—

177 GI/77—6

1. Kachchigadh Lighthouse.

2. Bypore Lighthouse.

[File No. 33-D(2)/76]

S. RAMACHANDRA RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1978

का० आ० 256.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 8 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 में, नियम 8 के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु ऐसी प्रत्येक संविदा, जिसकी विषय-वस्तु मूल्य में दस हजार रुपए से अधिक हो, लिखित रूप में और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा बोर्ड के सामान्य मुद्रा से मुहर की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसी कोई संविदा, जो पूर्ववर्ती परन्तुक में निविष्ट है और जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है अध्यक्ष की बजाए उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जा सकती ।"

[सं० एल डी वी/18/77-डी-3]

वी० शंकरलिंगम, अवसर सचिव

New Delhi, the 10th January, 1977

S.O. 256.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 8 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, for the proviso to rule 8, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that every such contract the subject matter of which exceeds rupees ten thousand in value shall be in writing and signed by the Chairman and shall be sealed with the common seal of the Board :

Provided further that any such contract as is referred to in the preceding proviso which has been approved by the Chairman may be signed by the Deputy Chairman instead of the Chairman."

[No. LDV/18/77-D.III]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

### निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1977

का० आ० 257.—यतः केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की बृहत योजना में नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है तथा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अन्तर्गत 16-10-76 की नोटिस सं० 16(264) 76-एम० पी० द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अश्लेषित नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर आक्षेपों/सुझाव आश्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने अनुसूची में उल्लिखित उक्त संशोधन के सम्बन्ध में आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, दिल्ली की बृहत योजना और जोनल विकास प्लान में संशोधन करने का निश्चय किया है।

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली की उक्त बृहत योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

संशोधन :—

1. 1.157 हेक्टर (2.864 एकड़) भूमि भाग जो रिंग रोड (64.0 मीटर) तथा लिंक रोड (30.48 मीटर) डिफेंस कालोनी की तरफ का चौराहा है जिसका भू-उपयोग क्षेत्रीय विकास योजना के जोन डी० 20 (डिफेंस कालोनी) में दो प्राइमरी स्कूलों के लिये उद्दिष्ट था, को बदल कर "आयोजना क्षेत्र केन्द्र" (स्थानीय पणन केन्द्र) कर दिया गया है।
2. 1.121 हेक्टर (2.771 एकड़) माप का भूमि भाग जो वर्तमान बर्माशील पेट्रोल पम्प (लिंक रोड) के पीछे है तथा जिसका भू-उपयोग क्षेत्रीय विकास योजना के जोन डी०-20 (डिफेंस कालोनी) में "आयोजना क्षेत्र केन्द्र" (स्थानीय पणन केन्द्र) के लिए उद्दिष्ट था बदल कर "प्राइमरी स्कूल", कर दिया गया है।
3. 690 वर्गमीटर (825 वर्गगज) माप का क्षेत्र (जंगपुरा प्लॉट नं० 1 से 8 तक) का क्षेत्र भू-उपयोग जो क्षेत्रीय विकास योजना के जोन डी०-17 (निजामुद्दीन) में "रिहायशी" प्रयोजन के लिये उद्दिष्ट है, को बदल कर "आयोजना क्षेत्र केन्द्र" (स्थानीय पणन केन्द्र) कर दिया गया है।
4. 1.934 (4.78 एकड़) (प्रभोक रोड में प्लॉट नं० 1 और 3 तक) का भू-उपयोग जो क्षेत्रीय विकास योजना के जोन डी-3 (कर्जन रोड) में "शैक्षणिक प्रयोजन" (उच्चतर माध्यमिक स्कूल) था को बदलकर "रिहायशी" (राज्य अतिथि आवास) प्रयोजन कर दिया है।

[सं० के०-13011(32)/76-यू० डी०-1(ए०)]

डी० पी० ओहरी, अवर सचिव

#### MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 30th May, 1977

**S.O. 257.**—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published by the Delhi Development Authority with Notice No. F. 16(264)/76-MP, dated 16-10-76 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas the Central Government after considering the objections and suggestions with regard to the said modifications mentioned hereunder, have decided to modify the Master Plan for Delhi and Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :

#### MODIFICATIONS :

1. The land use of an area measuring 1.157 hec. (2.864 acres) earmarked for two Primary Schools in the Zonal Development Plan for Zone D-20 (Defence Colony), at the crossing of the Ring Road (64.0 mts.) and Link Road (30.48 mts.), towards Defence Colony is changed to 'Planning Area Centre' (Local Shopping Centre);

2. The land use of an area measuring 1.121 hec. (2.771 acres) earmarked for 'Planning Area Centre' (Local Shopping Centre) in the Zonal Development Plan for Zone D-20 (Defence Colony) in the rear of the existing Burmah Shell petrol pump (Link Road), is changed to 'Primary Schools';

3. The land use of an area (Plot Nos. 1 to 8 in Jangpura Extension) measuring 690 sq. mts. (825 sq. yds.), earmarked for 'residential use' in the Zonal Development Plan for Zone D-17 (Nizamuddin), is changed to 'Planning Area Centre' (Local Shopping Centre);

4. The land of an area (Plot Nos. 1 and 3, Ashoka Road), measuring 1.934 hec. (4.78 acres), earmarked for 'educational use' (Higher Secondary School) in the Zonal Development Plan for Zone D-3 (Curzon Road) is changed to 'residential' (State Guest House) use.

[No. K. 13011(32)/76-UDI(A)]  
D. P. OHRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978

क्र० आ० 258.—यतः केन्द्रीय सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली की बृहत योजना में उनमें उल्लिखित क्षेत्रों के बारे में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है तथा अधिसूचना सं० एफ० 20(8)/77-एम० पी० दिनांक 1 अक्टूबर, 1977 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर आक्षेपों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त संशोधन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली की बृहत योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली की उक्त बृहत योजना में उस तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है जिस तारीख में यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगी, नामतः

संशोधन:—

"बृहत योजना में विशेष उपयोगों" भू-उपयोग (उपयोग क्षेत्र एम०-3) के लिये निर्धारित लगभग 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) अंगभूत भूमि के क्षेत्र के भू-उपयोग को जो कि इंजीनियरिंग कालेज (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, महरोली रोड) के दक्षिण में और क्षेत्र एफ-11 (मुनीरका) में पड़ने वाली भूमि जो पश्चिम में स्थित है, जिसे 'नर्सरी' के लिये निर्धारित किया गया है उसे "सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (धार्मिक) में परिवर्तित किया जाता है।"

[सं० के०-13011/35/77-यू० डी० 1(ए०)]

एच० आर० गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 12th January, 1978

**S.O. 258.**—Whereas certain modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published Notice with No. F. 20(8)/77-MP, dated the 1st October, 1977 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objection or suggestion has been received with regard to the aforesaid modification; the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :

(1 acrs) forming part of the land earmarked for "special industrial" land use (Use Zone M-3) in the Master Plan, located in the south of Engineering College (Indian Institute of Technology, Mehrauli Road) and in the west of the land earmarked for "nurseries", falling in Zone F-11 (Munirka), is changed to "public and semi-public facilities (Religious)".

#### MODIFICATION :

The land use of an area measuring about 0.405 hect.

[No. K-13011/35/77-UDI(A)]

H. R. GOEL, Under Secy.

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1977

का० आ० 259.—केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 के नियम 4(ख) के अनुसरण में, किए गए पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों की पहली मार्च, 1973/1974/1975/1976 को प्राधिकृत स्थायी स्टाफ संख्या नियत करती है :—

ग्रेड	प्राधिकृत स्थायी स्टाफ संख्या			
	1-3-73 को	1-3-74 को	1-3-75 को	1-3-76 को
श्रेणी-1				
सेलेक्शन ग्रेड	1	1	1	1
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड				
(सीनियर स्केल)	5	5	5	5
(जूनियर स्केल)	6	7	7	7
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	21	24	23	24
ग्रेड-1	123	126	124	130
ग्रेड-2	69	65	64	75
श्रेणी-1 के पदों के 10 प्रतिशत के हिसाब से छुट्टी रिजर्व जोड़िए	22	23	22	24
श्रेणी-1 के पदों के 15 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व जोड़िए ।	34	34	34	36
श्रेणी-2				
ग्रेड-3	141	151	154	272
ग्रेड 4	324	334	336	237
श्रेणी-2 के पदों के 10 प्रतिशत के हिसाब से छुट्टी रिजर्व जोड़िए ।	46	48	49	51
श्रेणी-2 के पदों के 5 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व जोड़िए	23	24	24	25
कुल स्टाफ संख्या	815	842	843	887

2. केन्द्रीय सूचना सेवा की 1 मार्च, 1973, 1 मार्च, 1974, 1 मार्च, 1975 और 1 मार्च, 1976 को प्राधिकृत स्थायी स्टाफ संख्या क्रमशः 815, 842, 843 और 887 नियत कर दी गई है ।

[फाइल संख्या ए-11011/7/76-मो० आई० एस०]

एस० रामस्वामी, अधीक्षक सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION &amp; BROADCASTING

New Delhi, the 9th November, 1977

**S.O. 259.**—In pursuance of rule 4 (b) of the Central Information Service Rules, 1959, the Central Government as the result of the review undertaken, hereby fixes the authorised permanent strength of the following grades of the Central Information Service as on the March 1, 1973/1974/1975/1976.

Grade	Authorised Permanent Strength			
	As on 1-3-1973	As on 1-3-1974	As on 1-3-1975	As on 1-3-1976
Class I				
Selection Grade	1	1	1	1
S.A.G.				
(Senior Scale)	5	5	5	5
(Junior Scale)	6	7	7	7
J.A.G.	21	24	23	24
Grade I	123	126	124	130
Grade II	69	65	64	75
Add Leave Reserve @ 10 % of Class I post	22	23	22	24
Add Deputation Reserve @ 15 % of Class I posts	34	34	34	36
Class II				
Grade III	141	151	154	272
Grade IV	324	334	336	237
Add L.R. @ 10 % of Class II posts	46	48	49	51
Add D.R. @ 5 % of Class II post	23	24	24	25
Total Strength	815	842	843	887

2. The total authorised permanent strength of the Central Information Service has been fixed at 815, 842, 843 & 887 as on 1st March, 1973, 1st March, 1974, 1st March, 1975 and 1st March, 1976 respectively.

[F. No. A 11011/7/76 CIS]  
S. RAMASWAMY, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

का० आ० 260.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 8 के उप-नियम (3) द्वारा प्रवक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को एक जमदारी, 1978 से 31 जनवरी, 1978 तक उक्त बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है :—

- श्री कमलेश्वर
- प्रो० के० जी० अग्रवाल
- श्री एस० एस० रेगे
- प्रो० (श्रीमती) विजय राजाध्वश
- श्री डी० जी० नागदर्शी
- डा० (श्रीमती) चारुणीला बी० गुप्त
- श्रीमती कमला तिलक
- श्रीमती पद्मा के० देसाई
- डॉ० (कुमारी) लक्ष्मी एम० मोनेजी
- श्रीमती नलिनी एम० सूर्यवंकर
- श्रीमती मणिदेन देसाई
- श्रीमती टी० बी० दहेजिया
- श्रीमती लक्ष्मी शर्मा
- श्री एस० डी० शाह
- श्री एस० ई० हसन
- श्री तलाक्षी शाह
- श्री राजनारायण सिंह
- श्रीमती आर० एस० दोगा
- श्री रसिक जे० शाह
- श्रीमती मृणालिनी चौकसी
- श्रीमती ललिता एन० वापत
- श्रीमती एस० गुलरजानी
- श्रीमती मालती गिलानी
- श्रीमती आशा सेठ
- श्रीमती अन्जु अग्रवाल
- श्री जोए० अन्सारी
- श्रीमती निम्मी कुमार

[का० सं० 11/3/76-एफ०सी०]

New Delhi, the 31st December, 1977

**S.O. 260.**—In exercise of the powers conferred by Section 5 (1) of the Cinematograph Act, 1952 and Sub-rule (3) of Rule 8 read with Sub-rule (1) of Rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby reappoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as Members of the Advisory Panel of the said Board at Bombay with effect from 1st January, 1978, upto 31st January, 1978 :—

1. Shri Kamaleshwar
2. Prof. K. G. Aggarwal
3. Shri S. S. Rege
4. Prof. (Smt.) Vijaya Rajadhyaksha
5. Shri D. G. Nadkarni
6. Dr. (Smt.) Charusheela B. Gupta
7. Smt. Kamala Tihak
8. Smt. Padma K. Desai
9. Dr. (Miss) Labuben S. Soncni
10. Smt. Nalini S. Sukthankar
11. Smt. Maniben Desai
12. Smt. T. V. Dehejia
13. Smt. Laxmi Wahi
14. Shri S. D. Shah
15. S. E. Hassnain
16. Shri Talakshi Shah
17. Shri Rajnarain Singh
18. Smt. R. S. Boga
19. Shri Rasik J. Shah
20. Smt. Mrinalini Choksi
21. Smt. Lalita N. Bapat
22. Smt. S. Gularajani
23. Smt. Malati Gilani
24. Smt. Asha Sheth
25. Smt. Manju Aggarwal
26. Shri Zoe Ansari
27. Smt. Nimmi Kumar.

[F. No. 11/3/76-FC]

**का० आ० 261.**—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(3) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (3) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1978 से 31 जनवरी, 1978 तक उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया गया है :—

1. श्री टी० नीलकन्तन
2. श्रीमती सौम्या कैलाशम
3. श्री माहम्मद युसुफ कोकण
4. श्री एम० गोविन्दन
5. श्रीमती सी० एल० मीनाक्षी अम्मा
6. श्री पी० बी० चलयपेश्वर राव
7. श्री पी० के० रामलिंगम
8. श्री जी० वरदप्पा
9. श्रीमती आर० सुवर्णे
10. श्री पी० बी० भागीरथी
11. श्रीमती बर्था लोबो
12. श्रीमती इन्दिरा डी० कोठारी
13. श्रीमती मालती चेन्दुर
14. श्री सी० आर० शर्मा
15. श्रीमती राजी रंगचारी
16. श्रीमती पद्मिनी अच्युता मेनन
17. डा० एस० विजय लक्ष्मी

18. श्रीमती लीला पार्थसारथी
19. कुमारी पी० शान्ता बाई
20. श्रीमती एम० लीलावती
21. श्रीमती रोहिणी कृष्णाचन्द्र
22. डा० (कुमारी) सी० एम० लीलावती
23. श्रीमती हमलता अजनेयुलु
24. श्रीमती सारा सैयद युसुफ
25. श्रीमती जी० दुबे
26. श्रीमती पद्मा सदानन्दम

[(का० सं० 11/3/76-एफ० सी०)]

**S.O. 261.**—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and Sub-rule (3) of Rule 8 read with Sub-rule (1) of Rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby appoints the following persons, after consultation with the Central Board of Film Censors, as Member of the Advisory Panel of the said Board at Madras with effect from 1st January, 1978, upto 31st January 1978 :—

1. Shri T. Neelakanthan
2. Smt. Soundra Kailasam
3. Shri Mohd. Yousuf Kokan
4. Shri M. Govindan
5. Smt. C. L. Meenakshi Amma
6. Shri P. V. Chalapatheswara Rao
7. Shri P. K. Ramalingam
8. Shri G. Varadappa
9. Smt. R. Suvarna
10. Smt. P. V. Bhagirathi
11. Smt. Bertha Lobo
12. Smt. Indira D. Kothari
13. Smt. Malati Chandur
14. Shri C. R. Sharma
15. Smt. Raji Rangachari
16. Smt. Padmini Achutha Menon
17. Dr. S. Vijayalakshmi
18. Smt. Leela Parthasarathi
19. Kumari P. Shanta Bai
20. Smt. M. Leelavathi
21. Smt. Rohini Krishnachandra
22. Dr. (Miss) C. M. Leelavathi
23. Smt. Hemlata Anjaneyulu
24. Smt. Sara Syed Yustuff
25. Smt. G. Dubey
26. Smt. Padma Sadanandam

[F. No. 11/3/76-FC]

**का० आ० 262.**—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (3) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की एक जनवरी 1978 से 31 जनवरी, 1978 तक उक्त बोर्ड के कलकत्ता सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है :—

1. श्रीमती उमा सन्नामवीस
2. श्री सैलन मुकर्जी
3. श्रीमती अर्चु सहैव अय्युव
4. श्रीमती काजल सेनगुप्त
5. श्रीमती गैब्या दत्त
6. श्रीमती आशा पूर्णदेवी
7. श्री मुणील के० चक्रवर्ती
8. श्री आर० पी० गुप्ता

9. श्री अनन्त महापात्र
10. श्रीमती उषा खां
11. श्री रानेन अयन दत्त
12. श्रीमती जयश्री सेन
13. श्रीमती मोनाक्षी बसु

[फा० सं० 11/3/76-फ० सी०]

प्रार० ए० शर्मा, डेस्क अधिकारी

**S.O. 262.**—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of Rule 8 read with Sub-rule (1) of Rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby reappoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as Members of the Advisory Panel of the said Board at Calcutta with effect from 1st January, 1978, upto 31st January 1978:—

1. Smt. Uma Sabanabis
2. Shri Sallen Mookerji
3. Smt. Abu Sayeed Ayyub
4. Smt. Kajal Sen Gupta
5. Smt. Shaibya Dutt
6. Smt. Asha Purna Debi
7. Shri Sujit K. Chakrabarti
8. Shri R. P. Gupta
9. Shri Anant Mahapatra
10. Smt. Usha Khan
11. Shri Ranen Ayan Dutta
12. Smt. Minakshi Basu
13. Smt. Jayasree Sen

[F. No. 11/3/76-FC]

R. S. SHARMA, Desk Officer

### पूरी और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1977

फा० आ० 263—निष्कांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अशोक चन्द्र बांद्योपाध्याय, इसके द्वारा अपर जज, लघुवाद न्यायालय, लखनऊ को, जिन्हें इस विभाग की 31 अक्टूबर, 1977 की अधिसूचना संख्या 1(4)/विशेष सेल/77-एस०एस०-II द्वारा सहायक महाभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, महाभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियों को सौंपता हूँ :

- (1) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन अपील सुनने की शक्तियाँ; और
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन पुनरीक्षण की शक्तियाँ।

[सं० 1(4)/वि०सै०/77-एस०एस०-II]

अशोक चन्द्र बांद्योपाध्याय, महाभिरक्षक

### MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 29th December, 1977

**S.O. 263.**—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by Sub-Section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I, A. C. Bandyopadhyay, hereby delegate to the Additional Judge, Small Causes Court, Lucknow appointed as Assistant

Custodian General vide this Department's notification No. 1(4)/Spl. Cell/77-SS. II dated the 31st October, 1977 the following powers of the Custodian General :—

- (i) Powers under Section 24 of the said Act to hear appeals; and
- (ii) Powers of revision under Section 27 of the said Act.

[No. 1(4)/Spl. Cell/77-SS. II]

A. C. BANDYOPADHYAY, Custodian General.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

फा० आ० 264.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप नियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) की धारा (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा भारत सरकार पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग के आदेश संख्या 1/4/68-सतर्कता, दिनांक 29 नवम्बर, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश की अनुसूची में :—

- (क) "भाग II—सामान्य केन्द्रीय सेवा—श्रेणी III" में कालम 2 और 3 में "उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "बन्दोबस्त आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) "भाग III—सामान्य केन्द्रीय सेवा—श्रेणी IV" में कालम 5 में "उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "बन्दोबस्त आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 1/4/68-सतर्कता]

एम०सी० वर्मा, निदेशक

### ORDER

New Delhi, the 7th January, 1978

**S.O. 264.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of the rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the General Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) No. 1/4/68-AV dated the 29th November, 1975, namely :—

In the Schedule to the said order,—

- (a) in "Part II—General Central Service—Class-III" in columns 2 and 3, for the words, "Deputy Chief Settlement Commissioner", the words, "Settlement Commissioner" shall be substituted;
- (b) in "Part III—General Central Services—Class-IV" in Column 5, for the words, "Deputy Chief Settlement Commissioner" the words, "Settlement Commissioner", shall be substituted.

[No. 1/4/68-AV]

M. C. VERMA, Director

### अम संज्ञालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1978

फा० आ० 265.—केन्द्रीय सरकार, भूना पत्थर और डोलोमाइट खान अम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 10 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वित्त पोषित अपने क्रिया कलापों का वृत्त देते हुए, उस वर्ष के लेखा विवरण के साथ, निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

## भाग I

सामान्य :—चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 के अधीन गठित की गई थी, जिनमें किसी खान में उत्पादित उतने चूना पत्थर और डोलोमाइट पर, जितना

(i) किसी कारखाने के अधिभोगी को बेचा जाता है या अस्थायी व्ययन किया जाता है; या

(ii) ऐसी खान के स्वामी द्वारा, सीमेंट, लोहा या इस्पात के निर्माण संबंधी किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है; चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण को अभिवृद्धि करने के लिए एक रुपया प्रति मीटरी टन से अनधिक की दर से उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था की गई है। उद्ग्रहण की वास्तविक दर बीस पैसे प्रति मीटरी टन है। उपकर की प्रायः मुख्यतः चूना पत्थर या डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, रोगों के निवारण और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार, तथा जीवन स्तर के जिसके अन्तर्गत आवास और पोषण आदि भी सम्मिलित है, सुधार के लिए उपयोग में लाई जाती है।

2. प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, देश के ऐसे अठ्ठारह राज्यों गोवा और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों को जिनमें चूना पत्थर और डोलोमाइट खानें हैं, पांच क्षेत्रों में बांट दिया गया है, और कोयला, अभ्रक तथा लोह अयस्क खानों के उसी प्रकार के कल्याण संगठनों के अधीन कुछ विद्यमान कल्याण आयुक्तों और अन्य अधिकारियों को अधिनियम और नियमों के प्रवर्तन के लिए कल्याण और उपकर आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदेशों का आवंटन निम्नलिखित है :—

क्रम	क्षेत्र का संख्या मुख्यालय	सम्मिलित राज्य	वह अधिकारी जिसे कार्य सौंपा गया है
1	2	3	4
1.	जबलपुर	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा संघ राज्य क्षेत्र।	उप कोयला खान कल्याण आयुक्त, जबलपुर
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आसाम और मेघालय	कल्याण आयुक्त, भुवनेश्वर
3.	करमा	बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू, कश्मीर और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	अभ्रक खान कल्याण आयुक्त, करमा, बिहार।
4.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब	अभ्रक खान कल्याण आयुक्त, भीलवाड़ा राजस्थान।
5.	बंगलौर	कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश	लोह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, बंगलौर

अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था की जा चुकी है। जहां-जहां आवश्यक समझा गया है वहां अनिश्चित जोनल कार्यालय खोले जा रहे हैं।

(i) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं :—चार प्राथमिक औषधालय—जमुआ-रामगढ़ (अस्थान, राजस्थान), गोदत (राजस्थान) छोटा उबेपुर (गुजरात), नन्दिनी और जामूल (मध्य प्रदेश) में एक-एक, और एक चल चिकित्सा यूनिट सतना क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में और एक स्थायी एवं चल औषधालय देहरादून (उत्तर प्रदेश) में, उन स्थानों में या उनके पास रहने वाले चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों के कर्मचारियों और उनके कुटुम्बों को चिकित्सीय सुविधाएं देने के लिए कार्य करते रहे।

वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान पांच चल चिकित्सा यूनिटों ने मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), रोहतास (बिहार), बंगलौर (कर्नाटक), भुवनेश्वर (राजस्थान) और रणवाव (गुजरात), में एक-एक और एक एम्बुलेंस स्थायी औषधालय ने इंदौरपुर (जुनागढ़-गुजरात) में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। उड़ीसा राज्य में प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है।

(ii) चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों के लिए घातक और गंभीर दुर्घटना, प्रसुविधा स्कीम के अधीन बीस मामलों में अर्थात् एक जबलपुर क्षेत्र में, दो बंगलौर क्षेत्र में, तेरह भुवनेश्वर क्षेत्र में और एक भीलवाड़ा क्षेत्र में और तीन करमा क्षेत्र में, वित्तीय सहायता मंजूर की गई। करमा क्षेत्र में, तपेविक के मरीजों के लिए, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि, बिहार के तपेविक के अस्पताल करमा में, तपेविक से पीड़ित कर्मचारियों के अंतर्गत उपचार के लिए शैयाएं प्रारंभ की गईं। जबलपुर क्षेत्र में एक तपेविक के मरीज की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई। भुवनेश्वर क्षेत्र में, पुराने पक्षाघात से पीड़ित एक कर्मकार को बारह मास से अधिक अवधि के लिए प्रति मास 50 रु० की दर से निर्वाह भत्ता मंजूर किया गया। कैंसर से पीड़ित एक कर्मकार को भुवनेश्वर क्षेत्र में 500 रुपये की राशि दी गई।

(iii) शैक्षिक और मनोरंजन सुविधाएं :—(क) छात्रवृत्ति देने की स्कीम : चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों के कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों को छात्रवृत्तियां देने की स्कीम मंजूर की गई। इस स्कीम के अधीन 1976-77 के दौरान, भीलवाड़ा क्षेत्र में 142, भुवनेश्वर क्षेत्र में 37, जबलपुर क्षेत्र में 17, करमा क्षेत्र में 86 और बंगलौर क्षेत्र में 521 आवेदकों की छात्रवृत्तियां विभिन्न वर्गों पर मंजूर की गईं।

(ख) चल सिनेमा यूनिट और फिल्म प्रदर्शन :—देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक चल सिनेमा यूनिट कार्य करती रही है। बिहार क्षेत्र में तीन और चल सिनेमा यूनिटें भी, बनजयी (रोहतास-बिहार), करमा (बिहार) और चूक (मिर्जापुर-उत्तर प्रदेश) प्रत्येक में एक, कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान एक चल सिनेमा यूनिट ने भुवनेश्वर क्षेत्र में और एक ने जबलपुर क्षेत्र में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सभी क्षेत्रों में चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों के कर्मचारियों के लिए, उन्हीं जैसे कल्याण संगठनों की सहायता से फिल्म प्रदर्शन की भी व्यवस्था की गई थी।

(ग) टूर्नामेंट और खेलकूद के सामान का प्रदाय :—मध्य प्रदेश में जमूला में एक फुटबाल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। ऐसे ही भीलवाड़ा क्षेत्र में कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए अन्तर-प्रबन्ध तंत्र खेलकूद प्रतियोगिता की गई थी। बंगलौर क्षेत्र में पन्द्रह दिन विभिन्न खान प्रबन्ध तंत्रों को खेलकूद सामग्री प्रदान की गई थी।

(घ) प्रोजेक्टरों और रेडियो सेटों की व्यवस्था :—रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान विभिन्न खान प्रबन्धकों को पांच 16 मि०मि० प्रोजेक्टरों (4 बंगलौर क्षेत्र में और 1 जबलपुर क्षेत्र में), उनके उप साधनों सहित, दिए गए थे। भुवनेश्वर क्षेत्र में खान प्रबन्धकों को लाउड स्पीकरों के साथ पांच रेडियो सेट भी दिए गए थे।

(iv) जल प्रदाय :—भुवनेश्वर क्षेत्र में चार जल प्रदाय स्कीमें मंजूर की गई हैं और खान के प्रबन्धकों को 76,000 रु० की राशि दी गई थी। एक अन्य जल प्रदाय स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जबलपुर क्षेत्र में खान प्रबन्धक को भी 93,000 रु० की राशि दी गई थी। भुवनेश्वर क्षेत्र में 4 कुओं को भी पूरा किया गया था।

(v) आवास सुविधाएं :—निम्न लागत आवास स्कीम के अधीन (जिसका पुनः नाम टाइटन-I आवास स्कीम रखा गया है) 1237 घर मंजूर किए गए थे और रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान 270 घर पूरे कर लिए गए हैं।

## भाग II

वर्ष 1976-77 का लेखा विवरण

1-4-1976 को अर्थक्षेत्र	75,90,529
वर्ष 1976-77 के दौरान प्राप्तियाँ	71,00,517
वर्ष 1976-77 के दौरान व्यय	40,55,115
31-3-1977 को अंतर्क्षेत्र	1,06,35,931

## भाग III

वर्ष 1977-78 की प्राप्ति और व्यय के प्राक्कलन

प्राक्कलित प्राप्ति	80,00,000
प्राक्कलित व्यय	60,64,000

[फा० सं० जेड० 16016/1/77-एम०बी०]

पी० के० सेन, अवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th January, 1978

**S.O. 265.**—In pursuance of Section 10 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972), the Central Government hereby publishes the following report giving an account of its activities financed under the said Act during the Financial year 1976-77 together with a statement of accounts for that year :—

## PART I

**General.**—The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act 1972 which provides for levy and collection of a cess on so much of Limestone and Dolomite produced in any mine,

- as is sold or otherwise disposed of the occupier of any factory, or
- as is used by the owner of such mine for any purpose in connection with the manufacture of cement, iron or steel,

to promote the welfare of the persons employed in limestone and dolomite mines at a rate not exceeding one rupee per metric tonne. The actual rate of levy is, however, twenty paise per metric tonne. The proceeds of the cess are utilised mainly for the improvement of public health and sanitation, prevention of diseases and the provision and improvement of medical facilities and improvement of standards of living conditions including housing and nutrition etc. of persons employed in the limestone or dolomite mines.

2. For administrative Convenience, the eighteen States and Union Territories of Goa and of Delhi having limestone and dolomite mines in the country have been grouped into five regions and some of the existing Welfare Commissioners under the sister Welfare Organisations for coal, mica and iron ore miners and other officers have been appointed as Welfare and Cess Commissioners for the enforcement of the Act and Rules. The allocation of the regions is as under :—

Sl. No. of the region	Head Quarters	States covered	Work entrusted to
		3	4
1. Jabalpur		Madhya Pradesh	Deputy Coal Mines
		Maharashtra and	Welfare Commis-
		Union Terri-	sioner, Jabalpur.
		tory of Goa.	Welfare Commissioner
2. Bhubaneswar		Orissa, West	Bhubaneswar.
		Bangal, Assam	
		and Meghalaya	
3. Karma		Bihar, Uttar Pradesh,	Mica Mines Welfare
		Jammu and Kashmir	Commissioner Karma
		and Union Territory	(Bihar)
		of Delhi.	
4. Bhilwara		Rajasthan, Gujarat	Mica Mines Welfare
		Haryana Himachal	Commissioner Bhil-
		Pradesh and Punjab.	wara (Rajasthan).

1	2	3	4
5. Bangalore	Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh	Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Bangalore.	

The machinery for the enforcement of the Act has already been set up in the various regions. Additional zonal offices are being set up wherever considered necessary.

(i) Medical Facilities.—Four Ayurvedic Dispensaries, one each at Jamua-Ramgarh (Asthali, Rajasthan), Gotan (Rajasthan), Chotta Udepur (Gujarat), Nandini and Jamul (Madhya Pradesh), one Mobile Medical Unit in Satna Zone (Madhya Pradesh) and one Static-cum-Mobile Dispensary at Dehradun (Uttar Pradesh) continued to function for providing medical facilities to the limestone and dolomite mine workers and the members of their families in and around these places. Five Mobile Medical Units, one each at Mirzapur (Uttar Pradesh), Rohtas (Bihar), Bangalore (Karnataka), Kukda (Rajasthan) and Ranavav (Gujarat) and one Static Allopathic Dispensary at Dungarpur (Junagarh-Gujarat) also started functioning during the financial year 1976-77. A Maternity-cum-Child Welfare Centre has also been sanctioned to be set up in Orissa State.

(ii) Financial assistance was sanctioned under the Fatal and Serious Accident Benefit Scheme for limestone and dolomite miners in respect of twenty cases; one in Jabalpur region two in Bangalore region, thirteen in Bhubaneswar region, one in Bhilwara region and three in Karma region. In Karma region, beds were got reserved for T. B. Patients in the T. B. Hospital, Karma of the Mica Mines Labour Welfare Fund, Bihar for the indoor treatment of workers suffering from T. B. One T. B. patient was sanctioned financial assistance in Jabalpur region. In Bhubaneswar region, subsistence allowance at the rate of Rs. 50 per month for a period not exceeding twelve months was sanctioned to a worker suffering from prolonged paralysis. A sum of Rs. 500 was given to a worker suffering from cancer in Bhubaneswar region.

(iii) Educational and recreational facilities.—(a) Scheme for the award of scholarships.—A Scheme providing for the award of scholarships to the sons and daughters of workers in limestone and dolomite mines has been sanctioned. Under this Scheme 142 applicants in Bhilwara region, 37 in Bhubaneswar region, 17 in Jabalpur region, 86 in Karma region and 521 in Bangalore region were sanctioned scholarships at varied rates during the year 1976-77.

(b) Mobile Cinema Units and film shows.—One Mobile Cinema Unit continued to function at Dehradun (Uttar Pradesh). Three more Mobile Cinema Units, one each at Banjai (Rohtas-Bihar), Karma (Bihar) and Churk Mirzapur (Uttar Pradesh) also started functioning in Bihar Region. One Mobile Cinema Unit in Bhubaneswar region and one in Jabalpur region also started functioning during the period under report. Film shows to the workers of limestone and dolomite mines were also arranged with the help of sister Mines Welfare Organisations in all regions.

(c) Tournaments and supply of sports-material.—one football tournament was arranged at Jamula in Madhya Pradesh. Similarly an Inter-Management Athletic and sports meet was held for the recreation of the workers in Bhilwara region. Sports material was supplied to fifteen different mine managements in Bangalore region.

(d) Provision of projectors and radio sets.—Five 16 mm Projectors (4 in Bangalore region and 1 in Jabalpur region) with its accessories were provided to different mine managements during the period under report. Five radio-sets alongwith loud speakers were also provided to mine managements in Bhubaneswar region.

(iv) Water Supply.—Four water supply schemes have been sanctioned in Bhubaneswar region and a sum



of Rs. 76,000 was paid to mine managements. A sum of Rs. 93,000 was also paid to a mine management in Jabalpur region for the implementation of another Water Supply Scheme. In Bhubaneswar region 4 wells were also completed.

- (v) Housing facilities.—Under the Low Cost Housing Scheme (renamed as Type I Housing Scheme) 1237 houses were sanctioned and 270 have been completed during the period under report.

## PART II

Statement of accounts for the year 1976-77.

Opening balance as on 1-4-1976	Rs. 75,90,529
Receipts during the year 1976-77	Rs. 71,00,517
Expenditure during the year 1976-77	Rs. 40,55,115
closing balance as on 31-3-1977	Rs. 106,35,931

## PART III

Estimates of Receipts and Expenditure for the year 1977-78	
Estimated receipts	Rs. 80,00,000
Estimated Expenditure	Rs. 60,64,000

[F. No. Z-16016/1/77-M.V.]  
P. K. SEN, Under Secy.

New Delhi, the 10th January, 1978

**S.O. 266.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Katkona Colliery of Western Coalfields Limited, District Surguja and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th December, 1977.

### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(11) of 1976

#### PARTIES :

Employers in relation to the Management of Katkona Colliery of Western Coalfields Limited, Post Office Katkona, District Surguja (M.P.) and their workmen Sarvashri Baburam S/o Kanayaram, Jainath S/o Bodhan and Ramsubhag S/o Bhagirath through the President, M. P. Koyla Mazdoor Panchayat, P.O. Kurasia, Distt. Surguja (M.P.).

#### APPEARANCES :

For Employers.—Shri Sirmukudam, Law Officer.

For Workmen.—Shri Hardeo Singh, President of the Union.

INDUSTRY : Coal Mines DISTRICT : Surguja (M.P.)

Dated : December, 23rd, 1977

#### AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its order No. L22012/34/75/DIII(B) dated the 5th April 1976 for adjudication of the following industrial dispute by this Tribunal :

"Whether the action of the management of Katkona Colliery of Western Coal Fields Limited, Post Office Katkona District Surguja (Madhya Pradesh) in dismissing Sarvashri Baboo Ram S/o Kanayaram Jairam S/o Bodhram & Ram Subhag S/o Bhagirath with effect from 22-9-1975 is justified ? If not to what relief are the said workmen are entitled".

2. It is not disputed that Sri K. P. Singh, Branch President of M. P. Koyla Mazdoor Panchayat who was not 177 GI/77—7

an employee in Katkona Colliery served the management with a notice of demands and sat on hunger strike within the premises of the mine near the store since the evening of 28/4/1975. The three workmen of the colliery also gave notice of 12 hours sympathetic hunger strike and were found sitting with Sri K. P. Singh since the evening of 28th April 1975. They were the workers of the third shift and were expected to report on duty at 11.00 P.M. that night. They were marked absent in the third shift and were charge-sheeted for participating in strike/ hunger strike till the next date and for inciting others to do so. The charges were held as proved after due enquiry and the three workmen were dismissed. The whole episode was quite peaceful and non-violent. On the reference being made the management raised preliminary legal objections against the right of Sri Hardeo Singh, President of Koyla Mazdoor Panchayat to represent the workmen. Union's representative capacity was also challenged. The union on the other hand challenged the right of the management being represented by a practicing advocate. These points were decided vide order dated the 10th December 1976 which was upheld by the High Court of Madhya Pradesh.

3. The management's other legal objections relating to validity of reference and union's objection against the validity of enquiry proceedings were then decided on 19/10/1977 and the union was given an opportunity to cross-examine the witnesses who had appeared before the enquiry officer. Management examined fresh witnesses also.

4. The case of the management is that the charges of the misconduct were fully established by the evidence while the union's case is that the charges did not constitute any misconduct as admitted and proved conduct of hunger strike should be distinguished from the unproved allegation of strike and mere absence of the workmen from duty. As such the order of dismissal was wholly unwarranted. The allegation of inciting others to violence is alleged to be not established at all.

5. The charges in the cases of all the three workmen were identical. They may be reproduced as follows :

"(1) that on 28th April, 1975 while you had your duty in the third shift you staged a strike/hunger strike from 7.00 P.M. within the premises of the mine and also you were preaching/inciting other workers to do so, you continued to strike upto 8.30 A.M. of 29/4/1975.

(2) that you had resorted to strike as specified under clause (1) above without notifying to the authorities as required under the provisions of Section 22 of the Industrial Disputes Act and as such it is an illegal strike within the meaning of Section 24 of the Industrial Disputes Act.

If the above charges are proved it would constitute acts subversive of discipline and also constitute serious misconduct within the meaning of the aforesaid standing orders and even otherwise considering what is misconduct has to be reasonably construed."

6. In Babu Ram's enquiry file Ex. M-2 page No. 4 is Ex. M-2/1 the notice dated 27-4-1975, signed by these three workmen and Alam Singh raising 4 demands before the Manager and informing him that if the demands were not conceded they will have to resort to one day's token hunger strike with effect from 6.00 P.M. of the next day i.e. 28-4-1975 in front of colliery office.

Section 2(q) defines strike as follows :—

"Strike means cessation of work by a body of persons employed in any industry acting in combination or a concerted refusal or refusal under common understanding of any number of persons who are or have been so employed to work or to accept employment".

Thus for bringing the act within the mischief of this definition object of the combination or common understanding should be stop working or to refuse to perform the normal duties and not simply to undertake fast for pressing certain demands or, to say in Gandhian language, for purifying the soul. Remaining absent from duty for that purpose

does not mean entertaining a desire of the combination to stop the work. One who undertakes a fast may not naturally perform the manual labour simultaneously, hence he may remain absent from duty. Such absence would not be covered within the mischief of the aforesaid definition of the word 'strike'. The workman in the present case did not want to press their demands by stopping work. They only wanted to undertake fast in sympathy of Sri Eingh who was pressing the demands by undertaking the fast. Thus the workmen did not go on strike when they absented themselves from duty for undertaking one day's fast.

7. Malhotra in his commentary on Industrial Disputes Act, 1973 edition, Volume I page 242, has enumerated various nomenclatures and types of the strikes but hunger strike is not included in that list for obvious reasons. Though the word 'strike' appears in the expression 'hunger strike' yet hunger strike is not included within the concept of strike as defined in Section 2 (q) of the Industrial Disputes Act. Therefore in the present case of sitting on hunger strike even after absents from duty in sympathy of the hunger strike by a union leader will not amount to going on strike within the meaning of the Industrial Disputes Act because the avowed object is not the cessation of work.

8. Even if it is taken to be going on strike within the meaning of Section 2(q) of the Act, the strike is a legitimate weapon in the hands of the workmen for pressing their demands and they cannot be punished for participating in a strike unless the service conditions or standing orders prohibit such participation and till the strikers remain peaceful and non-violent. The strike becomes illegal in a public utility service as the Coal mines are, only when according to the opening clause in Section 22 of the Industrial Disputes Act, the strike is staged 'in breach of contract'. In the present case no service condition prohibiting participation in strike has been alleged or proved. As such the strike was not illegal.

9. Even in case of illegal strike when the standing orders do not pronounce such participation as misconduct, the participants cannot be punished with the penalty of dismissal merely on account of such peaceful participation. They may have preached or incited others unsuccessfully to participate in the strike but there is no evidence nor any charge that they offered physical obstruction to the loyal workers. Under such circumstances the Supreme Court has held in *Oriental Textile Finishing Mills Vs. Labour Court*, 1971(8) SCLJ 531(536) that:

"Even where the strike is illegal it does not justify the management from terminating their services merely on that ground, though if it can be shown on enquiry that the conduct of the workmen amounted to misconduct it can do so".

Preaching or inciting other to participate in a hunger strike has not been included in the list of misconducts enumerated in standing order No. 17. Clause (i) of clause (i) of the same contemplates preaching or inciting of violence for which there is no charge. Preaching or inciting to join the strike is altogether different from preaching or inciting violence. It is clear from the evidence that these workmen were quite peaceful. They never offered physical resistance nor man handled any workman. The words that they were preaching or inciting violence were obviously subsequently interpolated in the statements of the witnesses as is clearly visible to the naked eye and the witnesses have admitted that they did not utter such words before the enquiry officer. Such tampering with the record in a public sector undertaking cannot but be condemned in strongest terms and persons responsible should be taken to task for committing the crime of fabricating false evidence. Thus no misconduct was proved against them.

10. Moreover in the present case four persons i.e. these three workmen and Alam Singh participated in the strike and called other to join the same. There was no distinguishing feature between the conduct of these workmen and that of Alam Singh yet the latter was given no punishment and was taken back on duty, while these three workmen were punished with the drastic penalty of dismissal for the same act. Motive is being imputed for this discrimination. It is said that Alam Singh agreed to leave Kovla Mazdoor Panchayat while others did not hence distinction was

made in their cases. Whatever the reason such unreasonable discrimination smacks of victimisation. The action can be successfully assailed on this ground as well. In *Burn & Co. Vs. their workmen* 5 SCLJ 3333 (3338) about 4 workers were suspended because they had participated in the illegal strike alongwith several others who had been taken back in service, it was observed that:

"It cannot be said that mere participation in the strike would justify their suspension or dismissal, particularly when no clear distinction can be made between these persons and the very large number of workman who had been taken back into service although they had participated in the strike".

11. For all the reasons given above it is held that the dismissal of these three workmen by the management was wholly unjustified and the management is directed to reinstate them from the day they were dismissed from service. The period from the date of their dismissal to the date of reinstatement shall be counted as spent on duty and wages for this period shall be paid to them with other consequent benefits of annual increments etc. They shall be granted the leave due for 28-4-1975. The management shall further pay Rs. 50/- as costs to the workmen.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L-22012(34)/75-D III(B)/D. IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

New Delhi, the 11th January, 1978

**S.O. 267.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dena Bank, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd January, 1978.

**BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT**

**HYDERABAD**

**Industrial Dispute No. 7 of 1977**

**BETWEEN**

**Workmen of Dena Bank, Nampalli Branch, Hyderabad.**

**AND**

**The Management of Dena Bank, Nampalli Branch, Hyderabad.**

**APPEARANCES:**

Sri K. J. Dixit, General Secretary of A.P. Bank Employees' Congress and Sri P. Vivekananda Rao, Secretary, A. P. Bank Employees' Federation for Workmen.

Sri D. V. Kulkarni, Officer for the Management.

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, through its Order No. L-12011/63/76-D, II A dated 4-5-1977, referred under Sections 7A and 10(i)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 the following dispute existing between the Employers in relation to the Management of Dena Bank, Hyderabad and their Workmen to this Tribunal for adjudication:—

Whether the action of the management of Dena Bank, Hyderabad in appointing Sri Seshavaram, Clerk-cum-Typist, Nampalli as Cashier in that Branch w.e.f. 20-10-1976 ignoring the claim of Shri P. S. Raju, Clerk-cum-Cashier in the same Branch is justified? If not, to what relief is Shri P. S. Raju entitled?

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 7 of 1977 and notices were ordered to be issued to both the parties.

3. On behalf of the Dena Bank Staff Union, Andhra Pradesh a claim statement was filed contending as follows:—

This Union represents Sri P. S. Raju Clerk-cum-Cashier in the Nampalli Branch of Dena Bank. The Management of the Nampalli Branch by its order dated 20-10-1976 instructed Sri P. S. Raju who is the claimant in the dispute to hand over charge of the Cash Department to Sri Seshavaram Clerk-cum-Typist working in the same Branch. This order is violative of the first Bi-partite Settlement dated 19-10-1966 between the Workmen and the Management which continues to bind both the parties. In terms of paragraphs 20.1 and 20.2 of the said Settlement combined designations are limited to two and by the impugned order Sri Seshavaram, Clerk-cum-Typist was awarded one more designation as Cashier in violation of the Settlement and contrary to the practice obtaining in the Bank in the matter of entrustment of the duties in the Cash Department. This was done solely with a view to favouring Sri Seshavaram and the Dena Bank Employees' Union which enjoys the patronage of the Management. In Dena Bank whenever vacancies arise in the Cash Department of a Branch attracting Special Allowance the same are filled by the senior most among the staff working in the Cash Department. Sri P. S. Raju by virtue of his designation and experience in the Cash Department ought to have been entrusted with Cashier's duties as was done prior to the date of the impugned order. This practice was over-looked and given a go-by in favour of Sri Seshavaram violating the first Bi-partite settlement and Section 9A of the Industrial Disputes Act, 1947. The Management's action in this regard is arbitrary and illegal and it amounts to unfair labour practice. Hence it is requested that an award might be passed declaring the Management's order dt. 20-10-1976 as illegal and void, directing the Management to restore Sri P. S. Raju to the post of Cashier attracting Special Allowance with effect from 20-10-1976 and pay Special Allowance to him from that date onwards.

4. The Management of Bank filed a counter contending as follows :—Sri Seshavaram being the senior most Clerk in the Branch was being entrusted with the work of Cashier when the regular Cashier went on leave. As a practice the Management of the Nampalli Branch has been entrusting the work of Cashier to the senior most Clerk. Accordingly Sri Seshavaram the Senior most clerk in the Branch was entrusted with the duties of Cashier. Whenever the regular Cashier was absent on leave or otherwise. Entrustment of additional duties of Cashier does not mean adding additional designation. It is not true to say that the bi-partite Settlement dated 19-10-1966 was violated by the Management. Sri Shaik Iqbal was Cashier in the Nampalli Branch drawing Special Allowance. When he was on leave on 5-3-1975 and on 21-6-1975; Sri Seshavaram the senior most Clerk in the Branch was entrusted with Cashier's duties and paid pro-rata Special Allowance, for the days he worked as Cashier as can be seen from the debit notes dated 11-3-1975 and 24-6-1975. However when Sri Iqbal proceeded on leave with effect from 8-6-1976, Sri P. S. Raju a Junior Clerk was asked through oversight to work as Cashier over looking the claims of Sri Seshavaram the senior most Clerk. This mistake was subsequently noticed and rectified by issuing the letter dated 20-10-1976 entrusting Cashier's duties to Sri Seshavaram. It can be seen from paragraph 5.5., 5.6., 5.8 of the Bi-partite Settlement dated 19-10-1966 that a workman would be entitled to Special Allowance if he is required to perform duty/duties and/or undertakes the responsibilities listed against the category, irrespective of his designation/nomenclature or any general authority vested in him, and that entrusting additional duties which would attract Special Allowance would not mean addition to the designation. It is left to the discretion of the Management to select the proper person for entrusting such additional duties. As per the practice in the Nampalli Branch the senior most among the Clerks is entrusted with the duties of Cashier attracting special allowance and it is not the senior most Clerk working in the Cash Department that is entrusted with those duties as alleged by the Workmen. Sri P. S. Raju is junior to Sri Seshavaram in service and is therefore not entitled to be posted as Cashier in preference to Sri Seshavaram. Sri Seshavaram joined the Bank in August, 1973 whereas Sri Raju joined in May, 1975. Sri Seshavaram has been working in the Nampalli Branch from August, 1973 whereas Sri Raju joined it in April, 1976. There is no violation of Section 9A of the I.D. Act, 1947 as there was no change in the conditions of service. The other allegations in the claims statement are denied. It is therefore requested that the claim might be rejected.

5. Another counter was filed on behalf of the Dena Bank Employees' Federation representing Sri Seshavaram with the following allegations :—As a matter of fact Sri Seshava-

taram is the person who is entitled from the beginning to receive the Key Allowance. But the Manager of Nampalli Branch being close to the Dena Bank Staff Union which is affiliated to units of the INTUC in the Banking Sector, denied Sri Seshavaram's right to hold the Key of the Cash Department and receive Special Allowance. Hence the Employees' Union took up the matter with the Head office/Regional Director and thereupon the mistake committed by the Manager of the Nampalli Branch was rectified and Sri Seshavaram was allowed to hold the key. The decision of the Management is not violative of the Bi-partite Settlement and it is in consonance with the existing practice. In Dena Bank there are no designations like Shroffs, and Cashiers working exclusively in the Cash Department. Whenever called upon all are required to work both in Accounts and Cash Departments. There is no question of making a security deposit for working in the Cash Department of Dena Bank as in the case of other Banks. In all the Branches of Dena Bank in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamilnadu and Goa, the practice of considering Branch-wise seniority for purposes of Special Allowance irrespective of designations has been in vogue. The Management rightly considered the seniority of Sri Seshavaram who is the senior most by virtue of his joining the Nampalli Branch earlier than Sri Raju for being entitled to the Key Allowance. Further Sri Seshavaram had worked in the Cash Department previously and drew Special Allowance even before Sri Raju's entry into the Bank's service as Clerk-cum-Cashier. There is no question of Section 9A being violated. Hence the action of the Management in appointing Sri Seshavaram Clerk-cum-Typist as Chief Cashier of the Nampalli Branch with effect from 20-10-1976 is perfectly in order and the claim is liable to be rejected.

6. On behalf of the Staff Union representing Sri P. S. Raju who is the aggrieved workman in this case W.W.1 was examined and Exs. W1 to W4 were marked. W.W.1 is at present working as Accountant in the local Head Office of Dena Bank, namely, the main Branch situated in the Bank Street, Hyderabad. This Branch is described as the main Branch since it is the oldest of all the five Branches situated in the twin cities. On behalf of the Management and the Employees' Union, Sri Seshavaram, whose appointment as Chief Cashier of the Nampalli Branch with effect from 20-10-1976 is disputed by the Staff Union, was examined as M.W.1 and Exs. M1 to M6 were marked.

7. Seshavaram who was examined as M.W.1 was appointed as Typist-cum-Clerk and joined the Nampalli Branch of Dena Bank in August, 1973. At that time Seetaramaiah and Shaik Iqbal were working in the same Branch as Cashier cum-Clerks and Smt. Ambika Devi as Typist-cum-Clerk. They were the only persons working in the Clerical cadre of the Nampalli Branch when M.W.1 entered service. Shaik Iqbal resigned and Seetaramaiah was promoted as Officer. Smt. Ambika Devi was transferred to another Branch. One S. Veerachari who entered the Bank's service in 1971 was previously working as Cashier in the main Branch. He was involved in a case of shortage of cash of Rs. 60,000.00. There was a departmental enquiry against him which resulted in punishment being inflicted. These facts were stated across the bar by Sri D. V. Kulkarni, Officer, Dena Bank. Veerachari was transferred to the Nampalli Branch in June, 1974, and he did not work in the Cash Department of that Branch. Later on D. Mohan Rao who is Typist-cum-Clerk and Suresh who is a Cashier-cum-Clerk joined the Nampalli Branch. Both of them are seniors to M.W.1 in the over-all service in the Bank. P. S. Raju is a Commerce graduate and he previously worked in the Army Educational Corps. He was discharged in April, 1975 on medical grounds and was appointed as Cashier-cum-Clerk in Dena Bank in April, 1975. Ex. W. 4 is the copy of the order of appointment issued to him. He was confirmed as Cashier-cum-Clerk with effect from 1-11-1975, while he was working in the Station Road Branch, Bangalore Region. Subsequently on transfer he joined the Nampalli Branch as Cashier-cum-Clerk in April, 1976. Thus both from the point of view overall service in the Bank and from the point of view of service in the Nampalli Branch, P. S. Raju is junior to M.W.1. In the early part of 1976 Shaik Iqbal was the Cashier in the Nampalli Branch. The Chief Cashier is also known as Paying Cashier as distinct from Receiving Cashier. The Receiving Cashier only receives remittances made into the Bank and hands over cash to the Paying Cashier who holds custody of the Cash jointly with the Manager and the Accountant. The Paying Cashier also makes cash payments against cheques and drafts. The person

next in rank to the Paying Cashier is deputed for making remittances into the Reserve Bank of India. In view of the onerous duties entrusted to the Paying Cashier, he gets Special Allowance which is also known as Key Allowance. The amount of this allowance in the case of Paying Cashiers of Dena Bank is Rs. 33.00 per month in addition to proportionate D.A. On account of this Special Allowance the Paying Cashier receives extra emoluments of about Rs. 90.00 per month in addition to his regular salary and D.A. When Shaik Iqbal who was the permanent incumbent was on leave in March and June, 1973, M.W.1 was entrusted with the duties of Paying Cashier and he was paid pro-rata Special Allowance for those days as can be seen from Exs. M4 and M5., the debit notes. Shaik Iqbal applied for long leave with effect from 8-6-1976. The then Manager of the Nampalli Branch appointed P. S. Raju as Paying Cashier in that vacancy. Immediately thereafter M.W.1 lodged a protest through the Employees' Union with the Regional Manager, Dena Bank, Bangalore Region, Bangalore on 8-6-1976 and Ex. M6 is the representation submitted by the Employees' Union in that connection. While matters stood thus the Manager of Nampalli Branch appears to have directed M.W.1 on 9-6-1976 to carry cash to the Reserve Bank of India. As mentioned above, this work is entrusted only to the person who is next in rank to the Paying Cashier. M.W.1 submitted Ex. W2 the letter dated 12-6-1976 to the Branch Manager declining to accept this duty entrusted to him and pointing out that a few days earlier the change of Cash Department had been handed over by the Manager to a Junior Clerk ignoring the fact that M.W.1 had performed the duties of Paying and Receiving Cashier on previous occasions. Finally under the instructions of the Regional Manager, Ex. W3 the letter dated 20-10-1976 was issued by the Branch Manager of Nampalli Branch to P. S. Raju advising him to handover Cashier's duties to M.W.1. So from 20-10-1976 onwards M.W.1 has been functioning as Paying Cashier in supersession of P. S. Raju who had been appointed to that post in June, 1976 by the Branch Manager. This led to a dispute raised by the Staff Union on behalf of P. S. Raju and ultimately resulted in the present reference.

8. On behalf of the Staff Union which is espousing the cause of P. S. Raju, three contentions are urged for the purpose of showing that M.W.1's appointment as Paying Cashier in the place of P. S. Raju with effect from 20-10-1976 is irregular. In the first place it is argued that M.W.1's appointment as Paying Cashier violates the terms of the Bi-partite Settlement which prohibits the combination of more than two designations in the same person. Secondly it is urged that M. W. 1's appointment as Paying Cashier is contrary to the existing practice. Lastly it is contended that M.W. 1's appointment as Paying Cashier amounts to variation of conditions of service without notice which is prohibited under Section 9A of the I. D. Act. All these contentions are refuted on behalf of the Management and the Employees' Union which supports M.W. 1.

9. As regards the first contention reliance is placed by the Staff Union on paragraphs 20.1 and 20.2 of the Bi-partite Settlement which deal with combined designations. What these two paragraphs in effect lay down is that not more than two designations should be combined in the case of any workmen. On the strength of these two paragraphs the contention advanced is that the appointment of M.W. 1 as Paying Cashier virtually amounts to combining the designation of Cashier with those of Clerk-cum-Typist since M. W. 1 was originally appointed only as Clerk-cum-Typist. But paragraph 5.6 of the Bi-partite Settlement shows that Special Allowance is intended only to compensate a workman for performance of discharge of certain Additional duties and functions requiring greater skill and responsibility over and above the routine duties or functions of a workman in the same cadre. Paragraph 5.7 refers to Appendix B which enumerates the additional duties and functions which would entitle a workman to Special Allowance. A reference to appendix B shows that the duties of a Cashier involve holding the Bank's cash, Keys and/or other valuables in safe custody generally with an officer and being accountable for them and being responsible for the running of the Cash Department and counter-signing cheques and/or drafts, payment orders, deposit receipts etc. It is therefore clear that this is not a case of an additional designation being added to that of a Typist-cum-Clerk. On the other hand it is only a case of entrustment of additional duties and functions which would entitle the workmen to Special Allowance. An ordinary Clerk, a Typist-cum-Clerk

and a Cashier-cum-Clerk are all in the same Clerical cadre and their scales of pay are identical. Paragraphs 20.1 and 20.2 of the Bi-partite Settlement do not expressly prohibit the entrustment of the additional duties and functions of a Cashier either to an ordinary Clerk or to a Typist-cum-Clerk. Moreover paragraph 5.8 shows that a workman would be entitled to a Special Allowance irrespective of his designation or nomenclature or any general authority vested in him. Hence there is no substance in the contention that the appointment of M. W. 1 as Paying Cashier violates the prohibition contained in the Bi-partite Settlement against the combination of more than two designations in the same individual.

10. The second contention urged on behalf of the Staff Union is based on an alleged practice existing in the various Branches of Dena Bank. According to the Staff Union the practice which is in vogue is that whenever the Paying Cashier is absent either on leave or otherwise the senior most Cashier-cum-Clerk working in the Cash Department is entrusted with the additional duties of Paying Cashier thereby entitling him to receive the Special Allowance. It is also urged that P. S. Raju is the senior most member of the Staff working in the Cash Department of Nampalli Branch and that in accordance with the aforesaid practice he alone ought to have been appointed as Paying Cashier when Shaik Iqbal proceeded on leave in June, 1976 and that M. W. 1's appointment as Paying Cashier ordered on 20-10-1976 effects a departure from this established practice. To prove that such a practice as the one mentioned above exists the Staff Union examined W. W. 1 and marked Ex. W 1. W. W. 1 is working as Accountant in the Main Branch situated in the Bank Street, Hyderabad. He states that he allocates duties to various Members of the Staff some times in consultation with the Branch Manager and some times on his own responsibility and that the allocation of duties is done mostly on the basis of the practice prevailing in his Branch. It is also his evidence that a Typist-cum-Clerk is not allotted the duties of Cashier-cum-Clerk and vice versa. V. A. R. Sarma is the permanent Paying Cashier in the Main Branch. Ex. P 1 is a statement mentioning the names of several other Cashier-cum-Clerks who were entrusted with the duties of Paying Cashier when the permanent incumbent went on leave during 1973 to 1977. The last column of Ex. W 1 mentions the rank held by these substitutes in the order of their seniority in the main Branch as a whole. It is seen from Ex. W. 1 that Cashier-cum-Clerks holding junior positions when compared with other members of the Staff working in the other Departments of the Main Branch were entrusted with the duties of Paying Cashier during 1973 to 1977 in the absence of the permanent incumbent V. A. R. Sarma. W. W. 1 states that other persons working either as Clerks or as Typist-cum-Clerks were not being entrusted with the duties of Cashier even though they were seniors to the Cashier-cum-Clerk who is entrusted with such duties during the permanent incumbent's absence. W. W. 1 was questioned about one Nand Kumar an ordinary Clerk. Nand Kumar was senior to V. A. R. Sarma in the Bank's service and he had also worked as Clerk in the Cash Department. Though V. A. R. Sarma had longer service in the Cash Department and was senior to Nand Kumar as far as Cash Department is concerned, Nand Kumar was appointed as Chief Cashier considering his general seniority even before V. A. R. Sarma. Thus Nand Kumar's instance provides an exception to the general practice prevailing in the Main Branch. W. W. 1 also mentions the case of B. Rama Rao who was appointed in 1971 as Clerk-cum-Typist in Shamshabad Branch. Ex. M 1 is the appointment order dated, 11-2-1971 showing that B. Rama Rao was appointed as Typist-cum-Clerk in Shamshabad Branch. Ex. M 2 is the memorandum dated 14-9-1971 showing that B. Rama Rao was confirmed as Typist-cum-Clerk with effect from 1-9-1971 in Shamshabad Branch. But B. Rama Rao (S. No. 13. of Ex. W 1) acted as Chief Cashier or Paying Cashier for a day in March, 1975 during V. A. R. Sarma's absence. When this was appointed out to W. W. 1 he stated that as per the records available in the Main Branch from 1974 onwards. B. Rama Rao was a Cashier-cum-Clerk. He also stated that B. Rama Rao was working as Chief Cashier in Shamshabad Branch and was transferred to the main Branch in 1974 presumably as Cashier-cum-Clerk. Hence from W. W. 1's evidence it is obvious that though B. Rama Rao was originally appointed in the Shamshabad Branch as Typist-cum-Clerk he was subsequently appointed as the Chief Cashier in the same Branch. This is another instance of a person not belonging to the Cashier Department being posted as Chief Cashier. Yet

another instance elicited through W. W. 1 is that of Madhav the General Secretary of the Staff Union. He is a Typist-cum-Clerk and when he was sent to the Saroornagar Branch on deputation in 1973 he has posted as Chief Cashier of the Saroornagar Branch as can be seen from Ex. M. 3 the relevant entries from Pages 182 to 191 of the Cash Scroll maintained by the Saroornagar Branch. Thus these three instances namely those of Nand Kumar, B. Rama Rao and Madhav prove that there is no hard and fast rule that only the senior most Clerk Working in the Cash Department should be entrusted with the duties of Paying Cashier in the absence of the permanent incumbent and that such entrustment may also be made considering the general seniority of a particular Clerk in whichever Department he might be working. W. W. 1 speaks about the practice prevailing in the Main Branch and he pleads ignorance of the practice in force in the Nampalli Branch. This shows that the practice varies from branch to branch. In paragraph 5.23 of Desais Award we find a reference to the fact that "the circumstances determining the extent of responsibility of a special post differ not merely from Bank to Bank or area to area, but also from Branch to Branch of the same Bank". Hence we are not concerned with what the practice in the Main Branch of Dena Bank situated in the Banks Street, Hyderabad is. On the other hand we are concerned only with the practice prevailing in the Nampalli Branch where M. W. 1 and P. S. Raju are working.

11. Exs. M4 and M5 go to show that in March and June, 1975, M. W. 1 was entrusted with the duty of Paying Cashier in the absence of the permanent incumbent Shaik Iqbal and that he was also paid pro-rata Special Allowance for the additional duties entrusted to him. At that time M. W. 1 was the senior most of all the Clerks, Typist-cum-Clerks and Cashier-cum-Clerks working in the Nampalli Branch. D. Mohan Rao and Suresh who are senior to M. W. 1 in the Banks general service joined the Nampalli Branch some time after June, 1974 with the result that they became junior to M. W. 1 in the Branch service. Veerachari who is Cashier-cum-Clerk is also senior to M. W. 1 in the Bank's general service. But he joined the Nampalli Branch in June, 1974. Hence he too was junior to M. W. 1 in the Branch service. P. S. Raju joined the Nampalli Branch as Cashier-cum-Clerk only in April, 1976. He is junior to M. W. 1 not only in the Bank's general service but also in the Branch service. It was under those circumstances that M. W. 1 was appointed in March and June, 1975 as Paying Cashier in the absence of the permanent incumbent. He was entrusted with Paying Cashier's duty on those two occasions only because he was the senior most among the Clerks, Typist-cum-Clerks and Cashier-cum-Clerks working in the Nampalli Branch taking the Branch service alone into consideration. P. S. Raju has not chosen to give evidence nor was any witness examined on behalf of the Staff Union to prove that even in the Nampalli Branch the prevalent practice is only to entrust the senior most Cashier-cum-Clerk with the duties of Paying Cashier in the absence of the permanent incumbent, ignoring the Branch seniority of the other Clerks or Typist-cum-Clerks. Hence we have to accept M. W. 1's evidence regarding the practice prevailing in the Nampalli Branch and the practice is that when the permanent Paying Cashier is absent the senior most member of the Staff, whether he is an ordinary Clerk or a Typist-cum-Clerk or a Cashier-cum-Clerk, is entrusted with the duties of Paying Cashier, the seniority being considered on the basis of the service in the Branch. When P. S. Raju was appointed as Paying Cashier in June, 1976 M. W. 1 promptly lodged a protest through the Employees' Union. The Management immediately rectified the mistake and appointed M. W. 1 as Paying Cashier with effect from 20-10-1976 in the place of P. S. Raju thereby bringing matters in conformity with the practice prevailing in the Nampalli Branch. Hence even the second contention urged on behalf of the Staff Union cannot be accepted.

12. In view of what has been stated above it has to be held that M. W. 1's appointment as Paying Cashier is in consonance with the practice in vogue in the Nampalli Branch. Thus there is no alteration in the conditions of service necessitating the issue of a notice as contemplated under Section 9A of the I. D. Act, 1947. Hence the 1 contention urged on behalf of the Staff Union also is devoid of substance.

13. For all these reasons I hold that M. W. 1's appointment as Chief Cashier or Paying Cashier of the Nampalli

Branch of Dena Bank with effect from 20-10-1976 in the place of P. S. Raju is perfectly justified and that P. S. Raju is not entitled to any relief in this regard. Hence the claim put forward by the Dena Bank Staff Union is hereby rejected.

An award is hereby passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 30th day of November, 1977.

K. P. NARAYANA RAO, Industrial Tribunal.

#### APPENDIX OF EVIDENCE

For Workmen.	Witnesses Examined
W. W. 1 : Shri Y. P. Shaw.	For Management.
	M. W. 1 Shri T. Seshavaram.

#### DOCUMENTS MARKED ON BEHALF OF WORKMEN

- Ex. W. 1 : Statement showing the Particulars of Entrustment of Duties of Cashier with Special Allowance in Leave Vacancies during 1973 to 1977 of Shri V. A. R. Sarma.
- Ex. W. 2 : Copy of the application given by Shri T. Seshavaram addressed to the Branch Manager, Dena Bank on 12-6-1976.
- Ex. W. 3 : Order of Transfer of charge dated 20-10-1977 Passed by the Bank.
- Ex. W. 4 : Photo Stat Copy of Appointment of Shri P. S. Raju.

#### DOCUMENTS MARKED ON BEHALF OF RESPONDENT

- Ex. M. 1 : Appointment Order of Shri B. Rama Rao dated 11-2-1971, given by the Bank.
- Ex. M. 2 : Salary Particulars of Shri B. Rama Rao furnished by the Bank on 14-9-1971.
- Ex. M. 3 : Cash Book for the period from 2-1-1973 to 11-5-1974.
- Ex. M. 4 : Photo Stat Copy of Voucher for Key Allowance to Shri T. Seshavaram dated 11-3-1975.
- Ex. M. 5 : Photo Stat Copy of Voucher for Key Allowance to Shri T. Seshavaram dated 24-6-1975.
- Ex. M. 6 : Copy of the application dated 8-6-1976 given by Dena Bank Employees' Union (Regd.) addressed to the Regional Manager, Dena Bank, Bangalore Region, Bangalore regarding allocation of Cash duties for special allowance.

K. P. NARAYANA RAO, Industrial Tribunal.  
[F. No.L-12011/63/76-D. II. A.]

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978

का० जा० 268.—केन्द्रीय सरकार ने, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उप-बन्धों के अनुसरण में, सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्चगेट, मुम्बई के सम्बन्ध में नियोजकों और उसके कर्मचारियों, के जिनका प्रतिनिधित्व इण्डियन नेशनल सीमेंट एण्ड एलाइड वर्क्स फेडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, मुम्बई करती है, मध्य हुए माध्यस्थता करार को भारत के राजपत्र में श्रम मंत्रालय के आदेश सं० एल-290/13/2/77-डी-III की, तारीख 28 नवम्बर, 1977 में प्रकाशित किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि निर्देश करने वाले व्यक्ति, प्रत्येक पक्ष की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3क) के अनुसरण में, उन नियोजकों और कर्मचारियों की जानकारी के लिए, जो इस माध्यस्थता करार के पक्षकार नहीं हैं किन्तु विवाद से सम्बन्धित हैं यह अधिसूचित करती है कि उन्हें अपना केस मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

[सं० एल-29013/2/77-डी-III-बी]

जगदीश प्रसाद, अवसर सचिव

New Delhi, the 12th January, 1978

**S.O. 268.**—Whereas in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government has published the arbitration agreement between the employers in relation to Cement Manufacturers' Association, Express Building Churchgate Bombay and its workmen represented by Indian National Cement and Allied Workers Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay, in the Gazette of India vide Order Ministry of Labour No. L-29013/2/77-D-III-B dated 28th November, 1977;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3A) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby notify for the information of the employers and workmen who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute that they shall be given an opportunity of presenting their case before the Arbitrators.

[No. L-29013/2/77-D-III-B]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1978

**क्रा० आ० 269.**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उसके द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5य की उपधारा (2) के अधीन, ऐसे अधिकारियों की बाबत जिनका अधिकतम वेतन बारह सौ रुपये से अधिक और पांच सौ रुपये से प्रत्युन हो, प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ, केन्द्रीय भविष्य निधि अध्याय द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

[सं० ए-36019 (2)/77-पी एफ-1]

New Delhi, the 11th January, 1978

**S.O. 269.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 19 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, hereby, directs that the power exercisable by it under sub-section (2) of Section 5D of the aforesaid Act shall also be exercisable by the Central Provident Fund Commissioner in respect of Officers whose maximum monthly salary is not more than twelve hundred rupees and not less than five hundred rupees.

[No. A. 36019(2)/77-PFI]

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1978

**क्रा० आ० 270.**—यतः आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री विलसुब्रह्म के स्थान पर श्री बी० प्रताप रेड्डी, सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, भ्रम, रोजगार और तकनीकी शिक्षा विभाग, हैदराबाद को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के भ्रम

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्रा० आ० 1517 तारीख 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद् 8 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री बी० प्रताप रेड्डी,

सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार,

भ्रम, रोजगार और तकनीकी शिक्षा विभाग,

हैदराबाद।"

[संख्या यू-16012(2)/76-एच० आर्०]

New Delhi, the 13th January, 1978

**S.O. 270.**—Whereas the State Government of Andhra Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri B. Pratap Reddy, Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Labour, Employment and Technical Education Department, Hyderabad to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Dilukhram;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri B. Pratap Reddy,

Secretary to the Government of Andhra Pradesh,

Labour, Employment and Technical Education Department,

Hyderabad."

[No. U-16012(2)/76-H.I.]

**क्रा० आ० 271.**—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 29 जनवरी, 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"तहसील और जिला भरतपुर में

(1) उत्तर में कस्बा भरतपुर चक संख्या 1,

(2) दक्षिण में ग्राम सीलड़ा,

(3) पूर्व में ग्राम मल्लाह; तथा

(4) पश्चिम में ग्राम अनाह,

से घिरे ग्राम श्रीनगर के क्षेत्र।"

[सं० एस-38013/13/76-एच० आर्०]

एस० एस० सहस्रनामान, उप सचिव

**S.O. 271.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 29th January, 1978 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI, except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of

the said Act shall come into force in the following areas in the State of Rajasthan, namely :—

"The areas within the Village Srinagar bounded by :—

- (i) Kasba Bharatpur Chak No. 1 in the North,
- (ii) Village Jheelara in the South,
- (iii) Village Mallah in the East; and
- (iv) Village Anah in the West,

in Tehsil and District Bharatpur."

[No. S-38013/13/76-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 12th January, 1978

**S.O. 272.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad, and their workman, which was received by the Central Government on the 5th January, 1978.

# **CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL— CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD**

**Reference No. 16 of 1977**

**Old No. 48 of 1975**

## **PARTIES :**

Employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P. O. Jealgora, District Dhanbad.

**AND**

Their workman.

## **APPEARANCES :**

For Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For Workman—Shri D. Narsingh, Advocate.

**INDUSTRY :** Coal.

**STATE :** Bihar.

Dated, Dhanbad, the 30th December, 1977

## **AWARD**

This is a reference U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by the Government of India, Ministry of Labour under Order No. L-2012/6/75-DIIA dated the 13th May, 1975. The schedule of reference is extracted below :—

## **SCHEDULE**

"Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P. O. Jealgora, District. Dhanbad in dismissing from service Shri Md. Siddique, Pump Khalasi, Jamadoba Colliery, with effect from 17-8-1968 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The dispute was raised U/S 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947, by the individual workman Md. Siddique and he is dead. A point has been raised that the reference lapses with his death and the Tribunal is not competent to give an award.

3. Shri D. Narsing was authorised by the concerned workman to represent him. With his death that authority also lapses as it has been argued. But to arrive at a proper conclusion I permitted him to argue his point. According to him once an industrial dispute has been validly referred for adjudication to the Tribunal, it cannot refuse to give its award on merits of the dispute as the industrial dispute does not come to an end with the death of the workman concerned.

4. It is necessary to examine the case of both sides and to find out as whether the industrial dispute referred to this Tribunal still exists or has ceased to exist with the death of the concerned workman.

5. Section 36 of the Industrial Disputes Act, 1947 deals with representation of parties and 36(1) deals with the representation of workman who is a party to a dispute and it envisages three types of cases for his representation. To clarify the position, I quote the relevant section below :—

36(1) A workman who is a party to a dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under this Act by—

- (a) "any member of the executive or other office bearer" of a registered trade union of which he is a member;
- (b) "any member of the executive or other office bearer" of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated;
- (c) where the worker is not a member of any trade union, by an officer of any trade union connected with, or by any other workman employed in, the industry in which the worker is employed and authorised in such manner as may be prescribed.

6. The proceedings relating to dispute as envisaged in Section 2-A, whether before a Conciliatory authority or an Adjudicatory authority, alteration in condition of service U/S 33, complaints U/S 33-A and recovery and computation proceeding U/S 33C are of the nature in which a workman is to be represented in his individual capacity. On the other hand, in all other disputes which are of collective nature which relates to the community of the workmen as a whole and the interest of workmen is not of individual nature, the workman is to be represented as a part of the community of the workmen. Clauses (a) (b) of Sub-Section (1) of Section 36 give the right to a workman to be represented in any proceeding under the Act by an officer of a registered union of which he is a member. But where such workman is not a member of any trade union, Clause (c) confers the right upon such a workman to be represented in any proceedings under the Act by an officer of any trade union connected with, or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed by authorising such a representative in a prescribed manner. Thus, a workman in the proceeding relating to the dispute envisaged in Section 2-A of the proceeding U/S 33, 33-A and 33-C will have the right to be represented by another person in terms of Section 36(1). He has, therefore, the right to change his representative as well at any time he likes. But the right to be represented in such a case is co-terminous with the life of the workman and cannot out-live him. In other words representation lapses after the death of the workman.

7. In this connection I may refer to the case of Bihar Working Journalists' Union, Petitioner Vs. H. R. Chaudhuri and another, Opposite Parties reported in 1968 Lab. J. C. 515=A.I.R. 1968 Patna 135. Shri Gouri Shankar Prasad, Sri Surnedra Mishra and Shri Abhiram Jha were the workmen concerned in the reference and the schedule was—

"Whether the claims of the following sub-editors of Indian Nation and Aryavarta that they are entitled to pay and emoluments of Chief Sub-Editors in terms of Order No. S.O. 1257 dated the 29th May, 1959 of the Govt. of India, Ministry of Labour and Employment are justified. If so, from what date and with what relief."

During the pendency of the proceeding Shri Abhiram Jha died and the Tribunal took the view that it had no jurisdiction to adjudicate upon the claim put forward on his behalf on the ground that he had died while the adjudication proceedings were still pending. The Bihar Working Journalists' Union, Patna, through its General Secretary which had sponsored the dispute went in writ and argument of the learned Counsel on its behalf was that the Tribunal was in error. It was urged that the death of Abhiram Jha during the pendency of the adjudication proceedings could not divest the Tribunal of its jurisdiction to adjudicate upon the industrial dispute since the real contesting party before it



was the union. It was further argued that once an industrial dispute had been validly referred for adjudication to a Labour Court or Tribunal, it could not refuse to give its award on merits of the dispute as industrial dispute did not come to an end with the death of the workman concerned. An alternative argument was raised that the Tribunal ought to have brought the heir of the legal representatives of the deceased workman on the record and then should have proceeded with the adjudication of the dispute.

8. The Hon'ble Judges of the High Court referred to the two decisions of the Labour Appellate Tribunal (Calcutta Bench), one in *Mazdoor Union Sugar Factory, Biswan Vs. Sarseria Biswan Sugar Factory Ltd.*, 1952 Lab. A. C. 294 and the other in *Rahat Hussain Vs. M/s. Lipton Ltd.*, Calcutta 1954 Lab. A. C. 90. Their Lordships also referred to Section 36 of the Industrial Disputes Act and come to the conclusion that "There could be no room for doubt that the authority of a person or a body of persons to represent any person cannot continue beyond the latter's lifetime. The principle of representation is based upon the relationship of principal and agent. Where the principal is dead, the authority of the Agent to act for him automatically ceases". "Therefore, it must follow that the petitioner Union was not competent to represent the case of Abhiram Jha before the Tribunal after his death. The Union could act on behalf of its principal but not on behalf of its heirs or legal representatives".

9. Their Lordships considered two cases, one of the Madras High Court in *Working Journalists of the "Hindu" Madras A.I.R. 1961 Madras 370* and *Bombay Union of Journalists Vs. The "Hindu" Bombay, A.I.R. 1963 Supreme Court 318* and were of the view that those two cases were not about the death of the workmen whose cause had been sponsored by the union or majority of the workmen. They considered Section 2-k of the Industrial Disputes Act and in their opinion—

"The use of the present tense "is" in the above definition is significant and indicates the continuing character of an industrial dispute. It follows that a dispute which in the past was an industrial dispute cannot be a dispute "which is connected with..." so as to fall within the ambit of an industrial dispute as defined in the Act. Keeping in view the continuing character of an industrial dispute we have to see whether it survives the death of the workman concerned. It is manifest that in certain cases it cannot so survive".

10. According to their Lordship where a workman had been wrongfully dismissed and his claim for reinstatement had given rise to an industrial dispute which had been referred to for adjudication to a Labour Court of Tribunal, there could be no doubt that the death of the workman during the pendency of the adjudication proceedings puts an end to the industrial dispute for the simple reason that he could no longer be reinstated. But when a dispute arise with regard to the status of a workman and such a workman died the other workman or their union might still be interested in adjudication of the status of the deceased workman because that might affect the status of his successor-in-office and in that case the industrial dispute did not cease to exist.

11. Their Lordships thus came to the decision that where it was an individual dispute, with the death of the individual workman concerned the dispute lapsed and where it was a collective dispute it continued to exist even after the death of one individual workman. They also held that where the dispute was concerning one workman but that was to affect the status of his successor-in-office in that case the industrial dispute would subsist even after the death of the individual workman.

12. Applying the above principles what we find in the instant case is that the concerned workman who had raised a dispute U/s 2-A of the Industrial Disputes Act had raised the question of his dismissal and prayer was for reinstatement and consequently with his death the industrial dispute came to an end and the claim does not survive. It may be said that his legal heirs may have some claim over his wages in case of reinstatement but that cannot form part of the present industrial dispute as the legal heirs could not be substituted in this dispute. The monetary claim if any may be a subject matter

of a case in another forum and not here. Therefore, the contention of Shri D. Narsingh, Advocate, does not hold good and with the death of the concerned workman the Tribunal ceases to have its jurisdiction to adjudicate upon the industrial dispute that had been validly referred to it. As the position stands the dispute having lapsed, no adjudication can be made. This is my award.

S. R. SINHA, Presiding Officer  
[No. L-20012/6/75-D. III(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer  
नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1978

का० अ० 273प्र.—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे बनाने का, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

दो मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से यदि कोई आशेष या सुझाव प्राप्त होते हैं तो केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

#### अधिसूचना का प्रारूप

केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों के अधीन जलयानों, तट क्षेत्रों और सर्वेक्षण पार्टियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की बाबत विरचित विशेष विनियमों को ध्यान में रखते हुए, यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 13 और धारा 14 के उपबन्ध, उक्त कर्मचारियों, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

- (1) पत्तन आयुक्त उक्त विनियमों को अंग्रेजी भाषा में और बहुसंख्या कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा या भाषाओं में एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करेगा ;
- (2) पूर्वोक्त विनियमों में कोई संशोधन करने से पूर्व, पत्तन आयुक्त प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी सम्बद्ध कर्मचारियों को सूचना द्वारा देगा जो पत्तन आयुक्त के कार्यालय के सूचना-पट पर लगाई जाएगी और वह ऐसी सूचना के बीच जिन के भीतर उसके संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा; और
- (3) उपयुक्त शर्त (1) में निर्दिष्ट पुस्तिका की एक प्रति और उसके प्रत्येक संशोधन की एक प्रति प्रत्येक सम्बद्ध कर्मचारी को दी जाएगी।

[सं० एस-32014(7)/77-इन्सू सी (एम० इन्सू)]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 13th January, 1978

S.O. 273.—The following draft of a notification, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.



Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of said draft before the expiry of the said period of two months will be considered by the Central Government.

## DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government, having regard to the special regulations that have been framed in respect of the service conditions of employees working in vessels, shore stations and survey parties under the Calcutta port Commissioners, hereby directs that, the provisions of sections 13 and 14 of the said Act shall not apply to the said employees for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following conditions, namely:—

- (i) The Port Commissioner shall publish the said regulations in a pamphlet form in the English language and in the language or the languages understood by the majority of the employees;
- (ii) before making any amendments to the aforesaid regulations, the Port Commissioners shall inform the employees concerned by notice, to be put up on the notice board of the Office of the Port Commissioner of the proposed amendment and shall consider any suggestions that may be made in respect thereof within twenty days of such notice; and
- (iii) a copy of the pamphlet referred to in condition (i) above and a copy of every amendment thereto shall be supplied to each employee concerned.

[No. S-32014(7)/77-WC(MW)]  
HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1978

का० घा० 274.—भारत सरकार के अपर सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन प्रादेश संख्या 673/12/77-सीमा शुल्क-8 तारीख 28 नवम्बर, 1977 जारी किया था जिसमें श्री पी० बी० भार्द्वाज, प्रमोद खार उर्फ वायथन अखिल खार उर्फ प्रमोद खार (प्रादेश) उर्फ भोगरी खार उर्फ चिकना खार, प्लेट नं० 5, पहली मंजिल, बी० विंग, गुरु हिम्मत सहकारी समिति, 140, हा० मस्कार हेनस रोड, मजगांव, मुम्बई-10, को माल की तस्करी करने और माल की तस्करी का बुध्दिराज करने से रोकने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, मुम्बई, में निरुद्ध करने और अभिरक्षा में रखने का निदेश दिया था; और

2. चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि प्रादेश का निष्पादन न हो सके फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

3. अतः केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश करती है कि उपरोक्त व्यक्ति इस प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, गुरुतर, मुम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[सं० 673/12/77-सीमा शुल्क—VIII]  
रतन बाबानी, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## ORDER

New Delhi, the 18th January, 1978

S.O. 274.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, issued order F. No. 673/12/77-Cus. VIII dated the 28th November, 1977 under section 3(1) ibid directing that Shri P.B.I. Abdul Khader alias Baythan Abdul Khader @ Abdul Khader (Padiakere) @ Dongri Khader @ Chikna Kader be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods and abetting the smuggling of goods; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby direct the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Greater Bombay, within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/12/77-Cus. VIII]  
R. K. THAWANI, Dy. Secy.

## बाणिज्य मंत्रालय

प्रादेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

का० घा० 275.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों को निर्यात से पूर्ण ब्वासिटी नियंत्रण और निरीक्षणधीन करने के लिए निर्यात (ब्वासिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षाानुसार कतिपय प्रस्ताव भारत सरकार के बाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश सं० का० घा० 408, तारीख 29 जनवरी, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उप-खंड-(II) तारीख 29 जनवरी, 1977 में प्रकाशित किए गए थे;

और उन सब व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त प्रादेश के प्रकाशित होने से 45 दिन के भीतर, आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 29 जनवरी, 1977 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब, निर्यात (ब्वासिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है—

(1) अधिसूचित करती है कि भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के निर्यात से पूर्ण ब्वासिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी;

(2) निरीक्षण के प्रकार को भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के निर्यात निरीक्षण) नियम, 1977 के अनुसार निरीक्षण ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो कि निर्यात से

पूर्व ऐसी भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों को लागू होगा;

- (3) (क) निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों को, जो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मानक विनिर्देश होंगे, निर्यात भंडार के सहमत विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है; या

(ख) मब (क) में निर्दिष्ट किसी भी विनिर्देश की अनुपस्थिति में, इस आदेश की अनुसूची में दिए विनिर्देशों को, भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है;

- (4) भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के निर्यात का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में तब तक प्रतिषेध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कनकता, कोचिन, विल्लो और मद्रास में स्थापित अधिकारणों में से किसी एक के द्वारा दिया गया इस आदेश का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसी भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों का परेक्षण क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश को कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के नमूनों के जल मार्ग, धूल मार्ग या वायु मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगा बशर्ते कि ऐसे नमूनों का कुल भार 5 किलोग्राम से अधिक न हो।

3. इस आदेश में 'भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों' से पकाने की किसी भी मान्यता प्राप्त वस्तु में भून कर तथा नमक लगाकर या सुखी भूनकर तथा नमक लगा कर तैयार की गई झुलसी हुई, बिना झुलसी, साधत तथा टुकड़ों के रूप में काजू की गिरियाँ अभिप्रेत हैं।

4. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

#### अनुसूची

[पैरा 1 (3) (ख) देखिए]

भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

#### 1. कच्चा माल

1.1. काजू की गिरियाँ, जिनमें झुलसी हुई, बिना झुलसी, साधत और टुकड़े होंगे भूतने और नमक लगाने के लिए प्रयोग की जाएंगी।

1.2. ये किसी भी प्रकार की जंतुबाधा, फफूँशी विहृत गंध और बीजा-वरण से पूर्णतः मुक्त होंगी।

#### 2. तैयार करने की विधि

2.1. भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियाँ पकाने की किसी भी मान्यता प्राप्त वस्तु में भूनकर तथा नमक लगाकर या सुखी भून कर तथा नमक लगाकर तैयार की जाएंगी।

2.2. पकाने के लिए प्रयुक्त बर्तन स्टेनलैस स्टील के होने चाहिए।

2.3. भूतने से पहले गिरियों में नमी का अंश 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

#### 3. उत्पाद अपेक्षाएँ

3.1. क्रेता तथा विक्रेता के मध्य हुए संविदा में जैसा बिया गया है उसके अनुसार वर्ग श्रेणियों को अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि वे तथ्यों को अग्रवर्ण रूप में प्रस्तुत न करें।

3.2. काजू की गिरियाँ भून कर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात् रसायन विश्लेषण पर, नीचे दी गई सारणी के स्वीकृत स्तरों के भीतर होंगी।

#### सारणी

#### स्वीकृत स्तर

वसा रहित अम्ल

0.4% (श्रीलंक अम्ल के रूप में)

पैराक्साइड मूल्य

सत वसा के भार के अनुसार  
सत वसा का 2 एम० ई० क्यू०  
2/कि०ग्रा०

भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों में वसा मुक्त अम्ल तथा पैराक्साइड मूल्य के अनुमान की पद्धति यहाँ उपाबंध में दी गई अवधारण की पद्धति के अनुसार होगी।

3.3. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1966 के अन्तर्गत स्वीकृत सुरक्षात्मक तथा सुगंधित पदार्थ।

#### 4. पैकिंग

4.1. भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियाँ क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट आकार तथा अन्य अपेक्षाओं वाले डिब्बों में पैक की जाएंगी।

4.2. गिरियाँ संविदा की अपेक्षानुसार पन्नी पैक भी की जा सकती हैं।

4.3. डिब्बे नए साफ तथा जंग से या किसी भी प्रकार की खराबी से मुक्त होंगे।

4.4. गिरियाँ डिब्बों में पैकिंग में या जड़ गैस के माध्यम में पैक की जाएंगी।

4.5. डिब्बे क्रेता की पैकिंग अपेक्षाओं के अनुसार कोट के डिब्बों में या रोगाणुनाशक लकड़ी के बक्से में पैक किए जाएंगे।

4.6. प्रत्येक डिब्बे या बक्से पर निम्नलिखित को बरतने के लिए चिह्नित किया जाएगा :—

(क) उत्पाद का नाम

(ख) विनिर्माता का नाम

(ग) पोत—सबाम चिन्ह

(घ) शुद्ध तथा कुल भार कि०ग्रा० में

#### 5. सीलिंग

6.1. प्रत्येक परेक्षण को पैकिंग के पश्चात् इस प्रकार उपयुक्त रूप से सील किया जाएगा जैसा परिपत्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

#### उपाबंध

#### पैराक्साइड मूल्य का आवश्यकतम :

50 ग्राम काजू की गिरियों को तोलकर उन्हें बक्की में पीसें, पाउडर की गई सामग्री को 250 मि० ली० वाली डाटवार कोणाकार बोतल में लेकर उसमें 150 मि० ली० क्लोरोफार्म मिलाएं। बोतल को रात भर हलिलन में रख दें। अगले दिन चूषण करके घोल को बोतल में छान लें। फिर दोबारा अवशेष को 100 मि० ली० क्लोरोफार्म के साथ मिलाएं और उसे दो घंटे के लिए हलिलन में रखकर छान लें। तब मिश्रित क्लोरोफार्म सार की मात्रा को 250 मि० ली० कर लें।

10 मि० ली० सार या लगभग 0.5 ग्रा० वसा वाले उपयुक्त संबंध भाग में से प्रत्येक को पहले से ही सुखाएँ तथा तोल लिए गए (250 मि० ली० की क्षमता वाले) बीकरों में पिपेट द्वारा निकाल लें। डिश को वाटरबाथ पर रखकर क्लोरोफार्म को वाष्पीकृत कर लें। तब डिशों को एक निर्वात बोवेन पर जो 70° से० पर रखी जाती है, अन्तरित कर दें। वाष्पीकरण नियंत्रित स्थिति में एक घंटे तक करें, फिर डिशों को निकाल लें और उन्हें घोषित में ठंडा करके तोल लें। डिशों को फिर बोवेन में 30 मिमट के लिए रखें और फिर निकाल लें, ठंडा कर लें तथा तोल लें। यह क्रिया तब तक दोहराई जाए जब तक कि दो लगातार भारों के बीच का अन्तर 5 मि० ग्रा० से अधिक न रहे जाए।

## MINISTRY OF COMMERCE

## ORDER

New Delhi, the 21st January, 1978

क्लोरोफार्म में सार का संखंड भाग, जिसमें लगभग 4 ग्राम वसा हो, 500 मि० सी० वाली डाटदार कोणाकार बोतल में ले लें और अपेक्षित मात्रा में सोडियम एसिटिक एसिड को मिला लें ताकि क्लोरोफार्म और एसिटिक एसिड का अनुपात 2 : 3 हो जाए। 0.5 मि० सी० संतृप्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल इसमें पिपेट द्वारा मिलाएं और घोल को स्थिर रखें तथा ठीक एक मिनट तक उसे बार-बार हिलाते रहें और तत्पश्चात् 50 मि० सी० आसुत जल मिला लें।

इसे 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट के साथ, उसे धीरे-धीरे डालते हुए, टाइट्रेट करें और लगातार और तेजी के साथ हिलाते हुए तब तक टाइट्रेशन जारी रखें जब तक कि पीला रंग लगभग अवशेष नहीं हो जाता। उसमें 0.1 मि० सी० एक प्रतिशत स्टार्च सूचक को थोड़े धार टाइट्रेशन को तब तक जारी रखें जब तक कि नीला रंग लगभग समाप्त नहीं हो जाता।

## टिप्पण —

- (1) अभिकर्मक का प्रतिदिन शून्य (स्लैक) अवधारण करें। काला टाइट्रेशन 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट के 0.1 मि० सी० से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (2) यदि घोल का रंग टाइट्रेशन शुरू करने से पहले हल्का पीला हो तो इस समय स्टार्च सूचक मिलाया जा सकता है।
- (3) यदि टाइट्रेशन 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट घोल के 0.5 मि० सी० से कम हो तो 0.01 एन सोडियम थायोसल्फेट घोल का प्रयोग करते हुए अवधारण को दोहराएं।

## संगणना :

पैराक्साइड मूल्य, मिली तुल्यांकों के रूप में (ए-बी) × एन × 1000 इन्व्यू पैराक्साइड प्रति 1000 ग्राम वसा  
जहाँ ए=इस नमूने का टाइट्रेशन ;  
बी=इस शून्य (स्लैक) का टाइट्रेशन ;  
एन=सोडियम थायोसल्फेट की नार्मलता  
इन्व्यू=परख के लिए ली गई वसा का भार

## वसा रहित अम्लों का आकलन :

क्लोरोफार्म का संखंड भाग, जिसमें लगभग 5 ग्राम वसा हो, एक तोली हुई कोणाकार बोतल में रख लें। क्लोरोफार्म को वाटरबाथ पर बाष्पित कर लें। निर्वत ओवेन में, निर्वत करके, क्लोरोफार्म के बिना तब तक को डूर कर दें। बोतल को क्लोरोफार्म मुक्त वसा के साथ तौल लें। पूर्ण अल्कोहल (आसुत) को, फिनॉलफथेन का सूचक के रूप में प्रयोग करते हुए तनुकृत सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में, निष्प्रभावित कर लें। वसा में 50 मि० सी० गर्म निष्प्रभावित अल्कोहल मिला लें और बोतल को अच्छी तरह हिला लें। 0.1 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड को तब तक टाइट्रेट करते रहें जब तक कि गुलाबी रंग जो 30 सेकंड तक स्थिर रहता है न आ जाए।

टिप्पण : यदि टाइट्रेशन 0.1 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल के 0.5 मि० सी० से कम है तो 0.02 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल प्रयोग करते हुए अवधारण को दोहराएं।

## संगणना :

क्रोलिक जैसी वसा मुक्त अम्ल, प्रतिशत =  $\frac{E \times \text{एन} \times 28.2}{\text{इन्व्यू}}$

## जहाँ

ए=सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल का मि० सी०  
एन=सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल की नार्मलटी; तथा  
इन्व्यू=परख के लिए ली गई वसा का भार, ग्राम में  
[सं० 8(22)/76-मि०नि० तथा नि०उ०]

S.O. 275.—Whereas for the development of the export trade if India certain proposals for subjecting roasted and salted cashew kernels to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India—Part II, Section 3, Sub-section (ii)—dated the 29th January 1977 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 408, dated the 29th January, 1977;

And whereas objections and suggestions were invited within forty-five days of the publication of the said order from all persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 29th January, 1977;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

- (1) notifies that Roasted and Salted Cashew Kernels shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- (2) specifies the type of inspection in accordance with the Export of Roasted and Salted Cashew Kernels (Inspection) Rules, 1977 as the type of inspection which would be applied to such Roasted and Salted Cashew Kernels prior to export;
- (3) recognise ;
  - (a) the specifications, which shall be national or international standard specifications declared by the exporter as the agreed specifications of the export contract, or
  - (b) in the absence of any specifications mentioned in item (a), the specifications set out in the Schedule to this Order as the standard specifications for Roasted and Salted Cashew Kernels;
- (4) prohibits the export in the course of international trade of roasted and salted cashew kernels unless the same is accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of such roasted and salted cashew kernels satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is exportworthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of samples of roasted and salted cashew kernels to prospective buyers, provided such samples do not exceed 5 kg. net weight.

3. In this Order "Roasted and Salted Cashew Kernels" mean cashew kernels scorched, unscorched, wholes and pieces as prepared through roasting in any recognised cooking medium and salting, or through the dry-roasting process and salting.

4. This Order shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

## SCHEDULE

[See paragraph 1 (3) (b)]

Specifications for roasted and salted cashew kernels

## 1. RAW MATERIAL

1.1 Cashew Kernels, which shall include scorched, un-scorched whole or pieces shall be used for roasting and salting.

1.2 They shall be completely free from insect infestations of any kind, fungal growth, rancidity and the presence of testa.

## 2. PREPARATION

2.1 Roasted and salted cashew kernels shall be prepared by roasting the cashew kernels in any of the recognised cooking media and salting, or through the dry roasting and salting process.

2.2 The cooking utensils used shall be of stainless steel.

2.3 The moisture content of the kernels before roasting shall not be more than 3.5 per cent.

## 3. PRODUCT REQUIREMENTS

3.1 The grade designations as stipulated in the contract between the buyer and the seller shall be allowed unless they make any misrepresentation of the facts.

3.2 The kernels, after the preparation through roasting and salting, on chemical analysis, shall be within the acceptance levels shown in the Table below :—

## THE TABLE ACCEPTANCE LEVELS

Free Fatty Acid .. 0.4% (as oleic acid) on the weight of extracted fat

Peroxide value .. 2 meq. %/kg. of extracted fat.

The method of estimates of Free Fatty Acid and Peroxide Value in Roasted and Salted Cashew Kernels shall be as per the method of determination given in the Annexure hereto.

3.3 Preservatives and flavouring agents permitted under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1966.

## 4. PACKING

4.1 The roasted and salted cashew kernels shall be packed in consumer containers of the size and other requirements as may be specified by the buyer.

4.2 The kernels may also be foil packed as required in the contract.

4.3 The containers shall be new, clean and free from rusting or any kind of damage.

4.4 Kernels shall be packed in the containers under vacuum or in the medium of inert gas.

4.5 The containers shall be packed in cardboard cartons or disinfected wooden cases according to the packaging requirements of the buyer.

4.6 Each carton or case shall be marked to show :—

- (a) name of the product.
- (b) name of the manufacturer.
- (c) shipping marks.
- (d) Net and gross weight in kgs.

## 5. SEALING

5.1 Each consignment after packing shall be suitably sealed as may be specified by the Council.

## ANNEXURE

## Estimation of peroxide value

Weigh 50 gms. of cashew kernels and powder these in a grinder. Take the powdered material in 250 ml. stoppered

conical flask and add 150 ml. of chloroform, keep the flask in shaker over night. Next day the slurry is filtered in a buchner flask under suction. The residue again mixed with 100 ml. of chloroform and kept in a Shaker for two hours and filter. The volume of the combined chloroform extracts is then made upto 250 ml.

10 ml. each of the extract or suitable aliquot portion containing about 0.5 gm. fat is pipetted out into two previously dried and weight small beakers (250 ml. capacity). Chloroform evaporate the chloroform by keeping the dishes on water bath. Then the dishes are transferred to a vacuum oven maintained at 70°C evaporation under vacuum is carried out for one hour. Dishes are taken out, cooled in a desiccator and weighed. The dishes are again kept in the oven for 30 minutes, then taken out, cooled and weighed. This process is repeated until the difference between the two consecutive weighing is not more than 5 mg.

Aliquot are the chloroform extract containing about 4 gm. of fat is taken in 500 ml. stoppered conical flask and required quantity of glacial acetic acid is added to get 2:3 ratio of chloroform acetic acid. 0.5 ml. of saturated potassium iodide solution is pipetted out into this and the solution is allowed to stand with occasional shaking for exactly 1 minute and then 50 ml. distilled water is added.

Titrate this with 0.1 N sodium thiosulphate adding it gradually and with constant and vigorous shaking Titration is continued until the yellow colour has almost disappeared. 0.5 ml. of 1 per cent starch indicator is added and the titration is continued until the blue colour just disappeared.

NOTE : (1) Conduct blank determination of the reagent daily. Blank titration should not exceed 0.1 ml. of 0.1 N sodium thiosulphate.

(2) If the colour of the solution is light yellow before the start of titration, starch indicator may be added at that stage.

(3) If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1 N sodium thiosulphate solution, repeat the determination using 0.01 N sodium thiosulphate solution.

## Calculation :

Peroxide value as milli equivalents of  $-(A-B) \times N \times 1000W$   
peroxide per 1000 g of fat

Where A = Titration of this sample;

B = Titration of this blank;

N = Normality of Sodium thiosulphate ;

W = Weight of fat taken for test.

## Estimation of free fatty acids

An aliquot of the chloroform containing about 5 gm. of fat is taken in a weighed conical flask. Chloroform is evaporated off on a water bath. Traces of chloroform is removed under vacuum in the vacuum oven. Flask is weighed with chloroform free fat.

Absolute alcohol (Distilled) is, neutralised with dilute sodium hydroxide solution using phenolphthalein as indicator. To the fat 50 ml. of hot, neutralised alcohol is added and the flask is shaken well. Titrate with 0.1 N sodium hydroxide till a pink colour which is stable for 30 seconds appear.

Note : If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1 N sodium hydroxide solution repeat the determination using 0.02 N sodium hydroxide solution.

## Calculations :

Free fatty acid as oleic, per cent  $-\frac{A \times N \times 282}{W}$

Where

A = ml. of the sodium hydroxide solution

N = normality of the sodium hydroxide solution; and

W = weight in gms. of fat taken for test.

का० ४१०२७६.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अधिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अधिकरणों में से कोई एक अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) इस प्रावधान में 'भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों' से पकाने की किसी भी माय्यता प्राप्त वस्तु में भून कर तथा नमक लगाकर या सूखी भूनकर तथा नमक लगा कर तैयार की गई झुलसी हुई, बिना झुलसी, साबुत तथा टुकड़ों के रूप में काजू की गिरियाँ अभिप्रेत हैं।

3. निरीक्षण का आधार:—भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों का निर्यात के लिए निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मानक विनिर्देश जिसे इसमें इसके पश्चात् मान्य विनिर्देश कहा गया है के अनुरूप हैं।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता निर्यात किए जाने के लिए आश्रित परेषण का विवरण देते हुए अधिकरण के निकटतम कार्यालय में आवेदन-पत्र देगा जिससे कि वह ऐसे परेषण का परीक्षण यह देखने के लिए कर सके या करवा सके कि वह नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात-कर्ता उसी समय ऐसे आवेदन की एक प्रति निरीक्षण के लिए परिषद् के निकटतम कार्यालय को भी देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन निर्यात-कर्ता के पक्ष से परेषण की रवानगी के प्रत्याशित समय के कम से कम 15 दिन पहले अधिकरण के कार्यालय में जाना चाहिए।

(3) उप-नियम (2) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर अधिकरण, परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों का निरीक्षण यह देखने के विचार से करेगा कि वह मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(4) निर्यात-कर्ता अधिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण कर सके।

(5) यदि निरीक्षण के पश्चात् अधिकरण का यह समाधान हो जाए कि निर्यात की जाने वाली भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों का परेषण मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो अधिकरण सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर यह घोषणा करने वाला प्रमाण-पत्र देगा कि भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है और निर्यात-योग्य है।

परन्तु जहां अधिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं हुआ है, वहां वह उक्त 15 दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यात-कर्ता को देगा।

(6) अधिकरण, निरीक्षित परेषण का पोत लवान से पूर्व भंडार करने के किसी भी स्थान पर या अभिवहन के दौरान, ऐसा पर्यवेक्षण कर सकता है जैसा वह इन नियमों के प्रयोजनों की तुष्टि के लिए आवश्यक समझे।

5. निरीक्षण फीस :—प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम 30 रुपये के अधीन रहते हुए, पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक 100 रुपये के लिए या उसके भाग के लिए 30 पैसे की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी।

6. अपील:—(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने पर व्यक्ति कोई व्यक्ति, ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए तीन से अधिक तथा सात से अधिक विशेषज्ञों वाले पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सद्यः संख्या के कम से कम दो तिहाई सद्यः गैर सरकारी होंगे।

(3) विशेषज्ञों के पैनल के लिए गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील, उसके प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर विशेषज्ञों के पैनल द्वारा निपटा दी जाएगी।

[सं० 6(22)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

सी० बी० कुकरेती, उप निदेशक

**S.O. 276.**—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Roasted and Salted Cashew Kernels (Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of publication in official gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the Export Inspection agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act;

(c) "Roasted and Salted Cashew Kernels" mean cashew kernels, scorched, unscorched, whole or pieces prepared through roasting in any recognised cooking medium and salting, or through the dry-roasting process and salting.

3. Basis of Inspection.—Inspection of roasted and salted cashew kernels for export shall be carried out with a view to seeing that they conform to the standard specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act, (hereinafter referred to as the recognised specification).

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export roasted and salted cashew kernels shall submit an application to the nearest office of the agency giving particulars of the consignment intended to be exported, to enable it to examine such consignment or cause the same to be examined to see whether the same conforms to the specifications referred to in rule 3 and the exporter shall at the same time endorse a copy of such application for inspection to the nearest office of the Council.

(2) Every application under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than 15 days before the anticipated time of despatch of the consignment from the exporter's premises.

(3) On receipt of the application under sub-rule (2), the agency shall inspect the consignment of roasted and salted cashew kernels as per the instructions issued by the Council in this behalf from time to time with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications.

(4) The exporter shall provide all necessary facilities to the agency to enable them to carry out such inspection.

(5) If, after inspection, the agency is satisfied that the consignment of roasted and salted cashew kernels to be exported complies with the requirements of the recognised specifications the agency shall, within 15 days of the intimation, issue a certificate declaring that the consignment of roasted and salted cashew kernels satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is export-worthy :

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall, within the said period of 15 days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

(6) The agency may exercise such supervision to the inspected consignment at any place of storage or transit prior to its shipment as it may consider necessary for satisfying the purposes of these rules.

5. Inspection fee.—Subject to a minimum of Rs. 30 for each consignment, a fee @ 30 paise for every Rs. 100 FOB value or part thereof for each consignment shall be paid as inspection fee.

6. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by it, prefer an appeal to such Panel of Experts consisting of not less than 3 but not more than 7 persons as may be constituted by the Central Government for the purpose.

(2) At least two-thirds of the total membership of the Panel of experts shall consist of non-Officials.

(3) The quorum for the Panel of Experts shall be 3.

(4) The appeal shall be disposed of by the Panel of Experts within 15 days of its receipt.

[No. 6(22)/76-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Dy. Director

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

सुद्धि-पत्र

कां.भा. 277.—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 24 सितम्बर, 1977 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की अधिसूचना सं. कां.भा. 2958, तारीख 5 सितम्बर, 1977 में, पृष्ठ 3419 पर,

(1) "औसत अतिशेष के समस्त अतिरिक्त रकम" के स्थान पर "उसके जमाखते अधिदाय और उस पर ब्याज की औसत रकम के बराबर अतिरिक्त रकम" पढ़ें।

(2) "जमाखते में अतिशेष" के स्थान पर "जमाखते में अधिदाय और उस पर ब्याज का शेष अतिशेष" पढ़ें।

(3) दो स्थानों पर आये वाले "290 रुपये" के स्थान पर "291 रुपये" पढ़ें।

(4) टिप्पण 1 में—(क) "वार्षिक ब्याज" के स्थान पर "अधिदाय पर वार्षिक ब्याज" पढ़ें;

(ख) —"ब्याज" के स्थान पर "अधिदायों पर ब्याज" पढ़ें।

[सं. कां. 13(10)-ई.बी. (बी.)/76-अं.भं.निं.]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 21st January, 1978

### CORRIGENDA

S.O. 277.—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. S.O. 2958, dated the 5th September, 1977, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 24th September, 1977, at page 3420,

(1) for "additional amount equal to the average balance", read "additional amount equal to the average amount of subscription and interest thereon at the credit";

(2) for "the balance at the credit", read "balance representing subscription with interest thereon at the credit";

(3) for "Rs. 290" occurring in two places read "Rs. 291";

(4) in Note I—(a) for "annual interest" read "annual interest on subscription";

(b) for "interest", read "interest on subscription".

[No. F. 13(10)-EV(B)/76-CPF]

### सुद्धि-पत्र

कां.भा. 278.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 3(ii), तारीख 24 सितम्बर, 1977 में पृष्ठ 3417-3418 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की अधिसूचना सं. कां.भा. 2957, तारीख 5 सितम्बर, 1977 में पृष्ठ 3417 पर "290 रुपये" जो दो स्थानों पर आया है, के स्थान पर "291 रुपये" पढ़ें।

[संख्या कां. 13(10)-ई.बी. (बी.)/76-सां.भं.निं.]

एस० एस० एस० मल्लोत्रा, प्रवर सचिव

### CORRIGENDUM

S.O. 278.—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. S.O. 2957, dated the 5th September, 1977 published on pages 3418-3419 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th September, 1977, at page 3418, for "Rs. 290" occurring in two places read "Rs. 291".

[No. F. 13(10)-EV(B)/76-GPF]

S. S. L. MALHOTRA

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1978

कां. भा. 279.—कां. भा. संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मंडी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-2-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है।

[संख्या 5-5/78-पी० एच० बी०]

के० बी० मुद्गल, सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

## MINISTRY OF COMMUNICATION

(P&T Board)

New Delhi, the 17th January, 1978

S.O. 279.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-2-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Mandi Telephone Exchange, N.W. Circle.

[No. 5-5/78-PHB]

K. B. MUDGAL, Assst. Director General (PHB)

## वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1978

कां० 280.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की बाधत नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) संशोधन नियम, 1978 है।
- (2) ये 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त होंगे।
2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में, नियम 33-क में खण्ड (क) के उपखण्ड (1) में "3,000 रुपये" श्रृंखला और अक्षर के स्थान पर "4,000 रुपये" श्रृंखला और अक्षर रखे जायेंगे।

[सं० एफ० 13(7)-ई०बी०(बी०)/77-सा०भ०मि०]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 23rd January, 1978

S.O. 280.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:—

- (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 1978.
- (2) They shall come into force on the 1st day of February, 1978.
2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in rule 33-A, in sub-clause (i) of clause (a), for the letters and figures "Rs. 3,000", the letters and figures "Rs. 4,000", shall be substituted.

[No. F. 13(7)-EV(B)/77-GPF]

कां० 281.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की बाधत नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, ग्रंथदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम ग्रंथदायी भविष्य निधि (भारत) संशोधन नियम, 1978 है।
- (2) ये 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त होंगे।

2. ग्रंथदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 में,

नियम 35-क में खण्ड (क) के उप खण्ड (i) में "3,000 रुपये" श्रृंखला और अक्षर के स्थान पर "4,000 रुपये" श्रृंखला और अक्षर रखे जायेंगे।

[सं० एफ० 13(7)-ई०बी०(बी०)/77-भं०भ०मि०]

एस० एस० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

S.O. 281.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely:—

- (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Amendment Rules, 1978.
- (2) They shall come into force on the 1st day of February, 1978.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, in rule 35-A, in sub-clause (i) of clause (a), for the letters and figures "Rs. 3,000", the letters and figures "Rs. 4,000" shall be substituted.

[No. F. 13(7)-EV(B)/77-CPF]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

## श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

का. आ. 282.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 29 जनवरी, 1978 को उस सारीख के रूप में नियत करती है, जिसके उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केवल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"(1) जिला पालघाट, तालुक चित्तूर में राजस्वग्राम चित्तूर, कोलहिन्जमपाड़ा, थत्तमंगलम, कोजीपथी और वडावन्नूर के क्षेत्र।

(2) जिला पालघाट, तालुक पालघाट में राजस्वग्राम एलापल्ली के क्षेत्र।"

[सं. एस. 38013/27/77-एच. आर्ह.]

एस. एस. सहस्त्रनामन, उप सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st January, 1978

S.O. 282.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 29th January, 1978 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely:—

"(1) The areas within the revenue village of Chittur, Kozhinjampara, Thattamangalam, Kozhipathy and Vada-vannur in Chittur Taluk in the Palghat District.

(2) The areas within the revenue village of Elapully in Palghat Taluk in the Palghat District."

[No. S-38013/27/77-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 20th January, 1978

S.O. 283.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal (Central), Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen which was received by the Central Government on the 3rd January, 1978.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 8 of 1977

BETWEEN

Workmen of Bank of Baroda, Pedanandipadu Branch, Guntur District.

AND

The management of Bank of Baroda, Pedanandipadu Branch, Guntur District.

## APPEARANCES :

Sri Y. D. Rao, General Secretary, The Bank of Baroda Staff Union for Workman.

Sri M. Panduranga Rao and Sri A. Krishna Rao, Advocates for the Management.

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, through Order No. L-12012/2/77-D.II.A dated 30-5-1977, referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the following dispute existing between the Employers in relation to the Management of the Bank of Baroda, Pedanandipadu, Guntur District and their Workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management the Bank of Baroda in not paying any salary of Shri T. Bosu Babu, Clerk in the Pedanandipadu Branch of the Bank in Guntur Dist. for the period from 29-11-73 to 2-9-74 and in not allowing him to work in the Bank after 2-9-74 is legal and justified ? If not to what relief is the workman entitled ?

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 8 of 1977 and notices were ordered to be issued to both the parties, in response to which the Workmen filed a claims statement and the Management filed a counter. There is no need to refer to the contents of the claims statement and the counter in view of the subsequent developments.

3. On 8-12-1977 the General Secretary of the Bank of Baroda Staff Union, Andhra Pradesh filed M. P. No. 159 of 1977 seeking an adjournment so that the proposals put forward by the Management of the Bank might be considered. The proposals which emanated from the Bank are also mentioned in the said petition and they are that the Management should employ the Workman concerned, namely, Sri T. Bosu Babu as a fresh employee in any of its branches in Andhra Pradesh on probation in the clerical cadre on starting basic salary as per the Bi-partite Settlement subject to the conditions that he should be found medically fit, that his absorption as stated above should be in full and final settle-

ment of all his claims against the Bank and that he should withdraw all his representations made to various authorities in the matter.

4. This day i.e. on 22-12-1977, a Memo was filed by the General Secretary of the Staff Union stating that in view of the agreement reached as mentioned in the letter dated 8-12-1977 (M.P. No. 159/77) between the Union, the Workman and the Management, the Union did not press its claim and that nil award might be passed. This Memo is signed by the concerned workman, Sri Bosu Babu and also by the Counsel appearing for the Management of the Bank. Now that the Workman concerned as well as the Union has agreed for the re-absorption of the workman concerned into clerical cadre on probation subject to his being found medically fit and subject to his giving up all other claims against the Management of the Bank, it has to be taken that the dispute has been amicably adjusted out of Court to the entire satisfaction of both the parties. The terms subject to which the workman concerned is to be re-absorbed are also fair in the circumstances. In view of the fact that the Union does not press its claim, there is no need to proceed further in the matter.

5. A nil award is hereby passed.

6. An apprehension is expressed by the Union that the Management of the Bank might terminate the services of the concerned workman even during the period of probation as a measure of victimisation though there may not be any valid grounds for doing so. I am sure that in the interests of industrial peace the Management would not resort to any such drastic action and that the workman would be afforded all reasonable opportunities to give satisfaction to the Management in the discharge of his duties during the period of probation.

Dictated to the Senographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 22nd day of December, 1977.

K. P. NARAYANA RAO, Industrial Tribunal.

[F. No. L-12012/2/77-D.II.A]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.